चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 5 अंक

1986 से प्रकाशित

18 मई–24 मई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

मुलायम, अमर, सुब्रत और चंदा

अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हिलेरी क्लिंटन के फाउंडेशन को भारतीय राजनीतिज्ञ अमर सिंह से मिले भारी-भरकम चंदे पर जो भी बवाल मचा हो, लेकिन अमर सिंह की सपा में वापसी पर छाया तो पड़ ही गई है. हालांकि, पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि सपा में वापसी के बारे में अमर सिंह ही मीडिया को बताएंगे. इसमें यह इशारा भी निहित था कि क्लिंटन फाउंडेशन को अमर सिंह द्वारा दिए गए 50 लाख डॉलर के चंदे के बारे में भी वही मीडिया को बताएं. इस बात पर लोग हैरत ज़रूर जता रहे हैं कि अमर सिंह के हलफनामे में उनकी कुल संपत्ति 50 लाख डॉलर है, तो उन्होंने क्लिंटन फाउंडेशन को उतनी ही रकम कैसे दे दी? आख़िर क्या है इस चंदे का सच? पढ़िए इस ख़ास रिपोर्ट में...

प्रभात रंजन दीन

क्लिंटन फाउंडेशन को अमर सिंह का लाखों डॉलर का चंदा सुर्खियों में आया, लेकिन न्यूयॉर्क पोस्ट ने इस प्रकरण में समाजवादी पार्टी और सुब्रत राय सहारा के कोरम की तरफ़ ध्यान नहीं दिया. क्लिंटन फाउंडेशन को जिस समय चंदा दिए जाने की बात कही गई है, वह समय अमर-मुलायम-सुब्रत के कोरम के बगैर पूरा ही नहीं होता. मुलायम सिंह की तरफ़ से क्लिंटन को सारे सत्ता सुख देने और सहारा की तरफ़ से क्लिंटन को ऐश्वर्य का भोग चढ़ाने के कृत्य आम लोगों ने देखे हैं. हम केवल उन्हें फिर से सामने रख रहे हैं और दृश्यों को जोड़ दे रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय राजनीति समझने वाले लोग इसे हिलेरी क्लिंटन के राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने की प्रतिरोधी सियासत से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं घरेलू राजनीति की नब्ज समझने वाले लोग अमर सिंह के समाजवादी पार्टी में वापस होने के ऐन समय पर हुई तिकड़मी सियासत से जोड़कर. जिस तरह डेमोक्रैट पार्टी में रहते हुए बराक ओबामा नहीं चाहते कि हिलेरी क्लिंटन अमेरिका की राष्ट्रपति बनें, उसी तरह समाजवादी पार्टी में रहते हुए प्रो. राम गोपाल यादव नहीं चाहते कि अमर सिंह फिर से पार्टी में वापस आए. यह चंदा-दृश्य बहुत सोच-समझ कर योजनाबद्ध तरीके से सामने लाया गया है, जबकि है यह बहुत पुराना मामला.

बहरहाल, अभी हम क्लिंटन फाउंडेशन को अमर सिंह द्वारा चंदा दिए जाने का प्रकरण देखते चलें, अन्य जुड़े हुए तथ्य इसके बाद देखेंगे. न्यूयॉर्क पोस्ट ने क्लिंटन कैश नामक एक किताब के हवाले से लिखा है कि अमर सिंह एवं अन्य कुछ संगठनों ने वर्ष 2008 में क्लिंटन फाउंडेशन को लाखों डॉलर का चंदा दिया था. यह चंदा 10 लाख डॉलर से 50 लाख डॉलर के बीच था. न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमर सिंह ने 2008 में उस संवेदनशील वक्त पर चंदा दिया था, जब अमेरिकी कांग्रेस में ऐतिहासिक भारत-अमेरिका असैनिक परमाणु करार पर मुहर लगने के बारे में चर्चा हुई थी. सीनेट इंडिया कॉकस की तत्कालीन सह-अध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित सीनेटर हिलेरी क्लिंटन ने विधेयक का समर्थन किया था, जिसे कांग्रेस ने बहुमत से पारित किया था. क्लिंटन कैश किताब के लेखक पीटर श्वाइजर ने सवाल उठाया है कि क्या अमर सिंह परमाणु करार के लिए जोर देते हुए भारत में अन्य प्रभावशाली हितों के वाहक तो नहीं थे? श्वाइजर ने लिखा है, अगर यह सच है, तो इसका मतलब है कि अमर सिंह ने अपने पूरे नेट-वर्थ का 20 से 100 प्रतिशत के बीच क्लिंटन फाउंडेशन को दिया था. इस मसले पर अमर सिंह ने किसी तरह की गड़बड़ी की बात खारिज करते हुए कहा है, मैं अनुमानों और अटकलों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता. मैं क़ानून का पालन करने वाला नागरिक हूं, जिसने देश के किसी क़ानून का उल्लंघन नहीं किया. मैं हाई प्रोफाइल व्यक्ति हूं, जिसकी कलकत्ता एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालयों, कानपुर सत्र न्यायालय, उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क़ानूनी तथा प्रशासनिक तरीके से जांच-पड़ताल की, लेकिन कोई मेरे ख़िलाफ़ कुछ साबित नहीं कर सका. क्लिंटन फाउंडेशन एवं उसके प्रचार विभाग ने भी कुछ ऐसा ही कहा और गड़बड़ी की बात पूरी तरह खारिज की, लेकिन चंदा पाने की बात से इंकार नहीं किया. फाउंडेशन ने कहा कि उसके सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए चंदा लेने में पूरी पारदर्शिता बरती गई.

अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हिलेरी क्लिंटन के फाउंडेशन को भारतीय राजनीतिज्ञ अमर सिंह से मिले भारी-भरकम चंदे पर जो भी बवाल मचा हो, लेकिन अमर सिंह की सपा में वापसी पर छाया तो पड़ ही गई है. हालांकि, पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि सपा में वापसी के बारे में अमर सिंह ही मीडिया को बताएंगे. इसमें यह इशारा भी निहित था कि क्लिंटन फाउंडेशन को अमर सिंह द्वारा दिए गए 50 लाख डॉलर के चंदे के बारे में भी वही मीडिया को बताएं. इस बात पर लोग हैरत ज़रूर जता रहे हैं कि अमर सिंह के हलफनामे में उनकी कुल संपत्ति 50 लाख डॉलर है, तो उन्होंने क्लिंटन फाउंडेशन को उतनी ही रकम कैसे दे दी? क्या उन्होंने अपनी पूरी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

चंदा देने वालों में सिर्फ़ अमर नहीं

क्लिंटन फाउंडेशन को चंदा देने वालों में अमर सिंह के अलावा 900 अत्यंत प्रमुख हस्तियां शामिल हैं. इनमें अमेरिकी-भारतीय एनआरआई, भारतीय, एनजीओ और अमेरिकी-भारतीय कंपनियां शुमार हैं. 250 डॉलर तक का चंदा देने वालों में 2,82,759 लोगों के नाम शामिल हैं. क्लिंटन फाउंडेशन को 251 डॉलर से एक हज़ार डॉलर तक का चंदा देने वालों में 650 भारतीयों के नाम हैं. एक हज़ार एक डॉलर से लेकर पांच हज़ार डॉलर तक का चंदा देने वालों में 150 भारतीयों के नाम हैं. 10 लाख से लेकर 50 लाख डॉलर तक का चंदा देने वालों में अमर सिंह के अलावा इन्फो ग्रुप के चेयरमैन विन गुप्ता, सेवेन हिल्स ग्रुप के स्वामी डेव कटरागड्डा और उद्योगपति लक्ष्मी एन. मित्तल के नाम शामिल हैं. पांच लाख से लेकर 10 लाख डॉलर तक का चंदा देने वालों में चॉपर ट्रेडिंग के राज फर्नांडो और एकता फाउंडेशन की अमृता एवं अशोक महबूबानी के नाम हैं. ढाई लाख से लेकर पांच लाख डॉलर तक का चंदा देने वाले भारतीयों में उद्योगपति अजित गुलाबचंद और तत्कालीन प्रमुख होटल व्यवसायी ललित सूरी (अब मरहूम) के नाम शामिल हैं. एक लाख डॉलर से लेकर ढाई लाख डॉलर तक का चंदा देने वालों में फ्रैंक इस्लाम और उनकी पत्नी डेब्बी ड्रीज़मेन के साथ-साथ अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन की अध्यक्ष एवं शाह कैपिटल पार्टनर्स की सीएफओ लता कृष्णन और रिलाएंस यूरोप लिमिटेड शामिल हैं. क्लिंटन फाउंडेशन को 50 हज़ार डॉलर से लेकर एक लाख डॉलर तक का चंदा देने वालों में हिंदुजा फाउंडेशन और जेनरल अटलांटिक के स्पेशल एडवाइजर दिनयर देवित्रे समेत दस लोगों के नाम शामिल हैं. 25 हज़ार से लेकर 50 हज़ार डॉलर तक का चंदा देने वालों में प्रमुख उद्योगपति आदि गोदरेज की पत्नी परमेश्वर ए. गोदरेज और देशपांडे फाउंडेशन के डी देशपांडे समेत 13 नाम शामिल हैं. 10 हज़ार से लेकर 25 हज़ार डॉलर तक का चंदा देने वालों में मेकेंजडी के मैनेजिंग डायरेक्टर रजत गुप्ता, फिल्मकार एम नाइट श्यामलन, तकनीकी विशेषज्ञ रणवीर त्रेहान समेत 41 लोगों के नाम हैं. पांच हज़ार से लेकर 10 हज़ार डॉलर तक का चंदा देने वालों में संत निरंकारी मिशन, वाधवानी फाउंडेशन के रोमेश वाधवानी समेत 32 नाम शामिल हैं. ■

मराठवाड़ा के गिरमिटिया मज़दूर पलायन की अंतहीन दास्तां | P-3

भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ किसान गोलबंद हो रहे हैं | P-4

भाजपा विधायक की नज़र में भाजपा दलित विरोधी | P-6

मुलायम, अमर, सुब्रत और चंदा

पृष्ठ 1 का शेष

संपत्ति क्लिंटन फाउंडेशन के नाम लिख दी या फिर चंदे की रकम का किसी अन्य स्रोत से जुगाड़ किया? अमर सिंह की इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी में कई अन्य तथ्य जुड़े होने की संभावनाएं बनती और दिखती हैं.

कौन भूल सकता है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहते जब बिल क्लिंटन लखनऊ आए थे, तो अमर सिंह ने उनकी कैसी अगवानी की थी. उसके बाद अमर सिंह ने वाशिंगटन जाकर हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात भी की थी. क्लिंटन फाउंडेशन ग़रीबी मिटाने, एड्स एवं कई दूसरे सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम चलाता है. तब 2005 का सितंबर महीना था. उत्तर प्रदेश विकास परिषद ने क्लिंटन को लखनऊ आमंत्रित किया था. सात सितंबर को बिल क्लिंटन एक दिन के लिए लखनऊ आए थे, लेकिन उनके लिए की गई व्यवस्था ऐसी थी, जैसे महीनों के लिए की गई हो. क्लिंटन एवं उनके साथ आए अधिकारियों को लखनऊ के सबसे महंगे पंच सितारा होटल ताज में ठहराया गया था. होटल की दूसरी मंजिल बाकायदा सील कर दी गई थी. 18 कमरे उनके लिए आरक्षित थे. इसके अलावा तीन अन्य स्थान भी सुरक्षित रखे गए थे. क्लिंटन के कमरे में कई हज़ार वाट का संगीत यंत्र लगाया गया था. क्लिंटन ने रात्रि भोज मुख्यमंत्री निवास पर किया था. इसके लिए दिल्ली के कारीगरों ने प्लाइवुड का जो विशेष पंडाल बनाया था, वह आंधी, पानी एवं भूकंप प्रतिरोधी होने के साथ-साथ बुलेटप्रूफ भी था. इस पर उस समय एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ था.

10 हज़ार वर्ग फुट में बने पंडाल में हर घंटे सौ यूनिट बिजली खर्च हुई. इसे 7.5 किलोवाट के 30 बड़े वातानुकूलन संयंत्रों द्वारा ठंडा किया जा रहा था. 1,000 केवी के दो ट्रांसफार्मर मुख्यमंत्री आवास के पास अलग से लगाए गए थे. इसके लिए छह लाख रुपये का भुगतान किया गया था. इसके अलावा स्वत: चालू और बंद होने वाले ऑटोमेटिक जेनरेटर भी लगाए गए थे. क्लिंटन की सुरक्षा के लिए ताज होटल में दो पुलिस अधीक्षक, तीन अपर पुलिस अधीक्षक, छह उपाधीक्षक, सात थानाध्यक्ष, 175 सिपाही और एक प्लाटून पीएसी तैनात थी. इसके अलावा अमौसी हवाई अड्डे पर दो अतिरिक्त अधीक्षक, तीन उपाधीक्षक, पांच थाना प्रभारी, 75 सिपाही और एक कंपनी पीएसी तैनात थी. मुख्यमंत्री आवास पर दो पुलिस उप-महानिरीक्षक, दो अतिरिक्त अधीक्षक, पांच उपाधीक्षक, चार थाना प्रभारी, 26 उपनिरीक्षक, 84 सिपाही और एक कंपनी पीएसी तैनात थी. लखनऊ में पूर्व में तैनात रहे चार मजिस्ट्रेटों को भी इसके लिए विशेष रूप से बुला लिया गया था.

क्लिंटन को खाने-पीने के लिए जो व्यंजन प्रस्तुत किए गए, उसके लिए मुंबई, दिल्ली एवं जयपुर के उन होटलों से परामर्श किया गया था, जहां क्लिंटन अपनी पिछली यात्राओं के दौरान ठहरे थे. आते ही उन्हें नींबू, चांदी के वर्क एवं जड़ी-बूटियों से निर्मित लखनऊ का विशेष शरबत मुफर्रा नवाब और इटली से मंगाई गई एले-बीन निर्मित कॉफी पेश की गई थी. नाश्ते के लिए टर्किश सैंडविच, भारतीय अमूल पनीर, इटली के शेदार, गौडा एवं आइडम्स पनीर और फ्रांस के मोजरेला पनीर का इंतजाम था. साथ ही केला और न्यूजीलैंड से मंगाया गया कीवी फल था. चॉकलेट की ब्राउनी प्लैटरी भी उन्होंने चखी थी. उनके कमरों के फ्रिज में ठंडी डाइट कोक भी भरी रही. उनके भोजन के लिए जो अवधी व्यंजन तैयार किए गए, उनमें चिकन काठी, रोल, चिकन टिक्का, मुर्ग अवधी, कोरमा, मुर्ग लबाबदार, माही टिक्का, पनीर टिक्का, काकोरी कबाब, घुलावटी कबाब, मुर्ग शाही कोरमा वगैरह प्रमुख रूप से शामिल थे. मछली, उबली सब्जियां, कॉर्न और चिकन के विदेशी व्यंजन भी थे. भोजन के बाद मीठे के नाम पर मुजफ्फर सेवई, शाही टुकड़ा और कई तरह की आइसक्रीमों की व्यवस्था थी. होटल ताज के शराबखाने ने भी इस अवसर पर विशेष तैयारी की थी.

रात्रि भोज के बाद नाच-गाने के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त श्यामक डावर नृत्य दल बुलाया गया था. विडंबना देखिए, उसके छह दिन पहले ही एक सितंबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी लखनऊ आए थे, लेकिन कोई जान भी नहीं सका कि मनमोहन कब आए और कब चले गए. लेकिन, जिन सड़कों से क्लिंटन को गुज़रना था, उनके डिवाइडर और पेवर पर नया रंग-रोगन कर गमले रखे गए थे. बिजली के लट्टुओं को बदल कर रिफ्लेक्टर लगाए गए. सैकड़ों खम्बों के रंग बदले गए. ताज होटल के सामने वाली दीवार पर धौलपुरी पत्थर लगाए गए और सफाई तो स्वर्गिक थी. क्लिंटन के स्वागत में हुए रात्रि भोज में 150 विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे. इनमें मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, अमिताभ बच्चन एवं सुब्रत राय सहारा का पूरा परिवार, अजीत सिंह एवं बंगारप्पा जैसे नेता, अनिल अंबानी, अमर सिंह समेत उत्तर प्रदेश विकास परिषद के सभी सदस्य, कुछ अख़बार मालिक और चुनिंदा नौकरशाह शामिल थे. मुलायम सिंह और क्लिंटन के बीच दुभाषिए का काम अमिताभ बच्चन ने किया. इस अभूतपूर्व स्वागत का अर्थ क्या था, इसकी पहेली सुलझाने में लोगों को अधिक वक्त नहीं लगा था. परमाणु करार पर बाहर-बाहर के विरोध और अंदर-अंदर के प्रेम दृश्य लोगों को सारे निहितार्थ समझा रहे थे.

इस यात्रा की खूबी यह थी कि क्लिंटन अमेरिका से सीधे लखनऊ पहुंचे थे. तब किसी ने चुटकी भी ली थी कि ग्लोबल कंपनी के डायरेक्टर के रूप में क्लिंटन सीधे लखनऊ आ रहे हैं. क्लिंटन के स्वागत में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, सुब्रत राय सहारा, राज्य के तत्कालीन ब्रैंड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, कुमार मंगलम बिड़ला, मुकेश अंबानी, आदी गोदरेज, रामदास पै, केवी कामत, एस बंगारप्पा, डॉ. प्रताप रेड्डी और नंदन नीलेकणी के साथ राज्य की तत्कालीन मुख्य सचिव नीरा यादव की मौजूदगी उल्लेखनीय थी. फिल्मी हस्तियों में सुभाष गई, राजकुमार संतोषी, करण जौहर, गोविंद निहलानी, मुजफ्फर अली एवं कमलेश पांडे का नाम तो है ही, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, श्रीदेवी एवं ऐश्वर्या राय जैसी खूबसूरत हस्तियां खास तौर पर उल्लेखनीय थीं. जाहिर है, इसमें अमर सिंह और सुब्रत राय सहारा की केंद्रीय भूमिका रही होगी. क्लिंटन की उस भव्य स्वागत गाथा को फिर से लिखने का मक़सद सिर्फ़ इतना है कि चंदा देने के पीछे की वजहों और स्वार्थों से संबद्ध सारे चेहरे साफ़-साफ़ दिखने लग जाएं. ■

feedback@chauthiduniya.com

अखिलेश का क्लिंटन प्रेम

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब जुलाई, 2014 में लखनऊ आए, तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी उनके स्वागत में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी. अमौसी हवाई अड्डे पर अखिलेश यादव क्लिंटन के स्वागत में खुद मौजूद थे. क्लिंटन लखनऊ में केवल पांच घंटे रहे. इतनी देर के लिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था में दो पुलिस अधीक्षक, आठ उपाधीक्षक, 10 थानाध्यक्ष, सात निरीक्षक, 250 कांस्टेबल और पीएसी की 10 कंपनियों की तैनाती की गई थी. क्लिंटन को जिस रास्ते से गुज़रना था, उसकी साफ़-सफाई, रंग-रोगन और प्रशासनिक तामाझाम तो इसके अतिरिक्त हैं. ■

सपा और अमर ने मिलकर की कांग्रेस की मदद

अब यह साफ़ हो गया है कि अमर सिंह एवं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस नीत संप्रग सरकार को उबारने और कॉरपोरेट हितों को संरक्षण दिलाने की नीयत से क्लिंटन फाउंडेशन को चंदा देकर हिलेरी क्लिंटन से मदद ली थी. यह बात अब खुल गई है कि सीनेटर रहते हुए बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन ने भारत के लिए सीनेट में लॉबिंग की. इसमें अमेरिकी-भारतीय उद्योगपति संत सिंह चटवाल सक्रिय थे. चटवाल की भूमिका के कारण ही यूपीए सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से नवाजने की कोशिश की थी. अमेरिका में हुई लॉबिंग में एक तरफ़ जेनेरिक इलेक्ट्रिक और वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक जैसे अमेरिकी कॉरपोरेट घराने के, तो दूसरी तरफ़ अनिल अंबानी की कंपनी एडीएजी के हित साधे जा रहे थे. ■

तब अमर के बचाव में कूद पड़े थे मुलायम

वर्ष 2008-09 में जब क्लिंटन फाउंडेशन को चंदा देने का मसला उछला था, तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हराकर (विधानसभा चुनाव 2007) बहुजन समाज पार्टी सत्ता पर काबिज हो चुकी थी. प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने क्लिंटन फाउंडेशन को अमर सिंह द्वारा भारी रकम बतौर चंदा दिए जाने की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी. इस सिफारिश से संबंधित पत्र केंद्र सरकार को औपचारिक तौर पर भेज भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद जांच का क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला. जबकि बहुजन समाज पार्टी ने अमर सिंह के ख़िलाफ़ फेमा के तहत मामला दर्ज कराने की मांग की थी और आरोप लगाया था कि क्लिंटन फाउंडेशन को चंदा देना विदेशी मुद्रा नियामक क़ानून का उल्लंघन है. तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की उस सिफारिश पर मुलायम सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी और अमर सिंह का बचाव किया था. मुलायम सिंह ने कहा था कि मायावती खुद बहुत बड़ी भ्रष्ट हैं, वह क्या दूसरों की जांच कराएंगी. उन्हें तो नैतिक अधिकार ही नहीं है बोलने का. ■

नाम वालों से अधिक हैं अनाम

क्लिंटन फाउंडेशन को चंदा देने वाली 900 वीवीआईपी हस्तियों के अलावा हज़ारों लोगों के नाम सामने आए हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी काफी है, जिनका नाम सूची में नहीं है, लेकिन उनका चंदा क्लिंटन फाउंडेशन को प्राप्त हुआ है. फाउंडेशन को चंदा देने वाली अनाम हस्तियों में देश के कई नामी पूंजीपति, नेता, व्यापारी एवं धनाढ्य एनजीओ स्वामी शामिल हैं, जिनके अमेरिका में बड़े-बड़े कारोबार हैं, होटल हैं और अनेक स्वार्थ संबद्ध हैं. इन अनाम हस्तियों में कौन नेता है, कौन पूंजीपति है, कौन अर्थ के गलियारे का बिचौलिया है, सारी जानकारी मौजूद है. लेकिन उनके नाम दस्तावेज़ों पर नहीं हैं, इसलिए नाम प्रकाशित करने में क़ानूनी बाधा है. ■

केंद्र से लेकर यूपी तक चलती थी चटवाल की

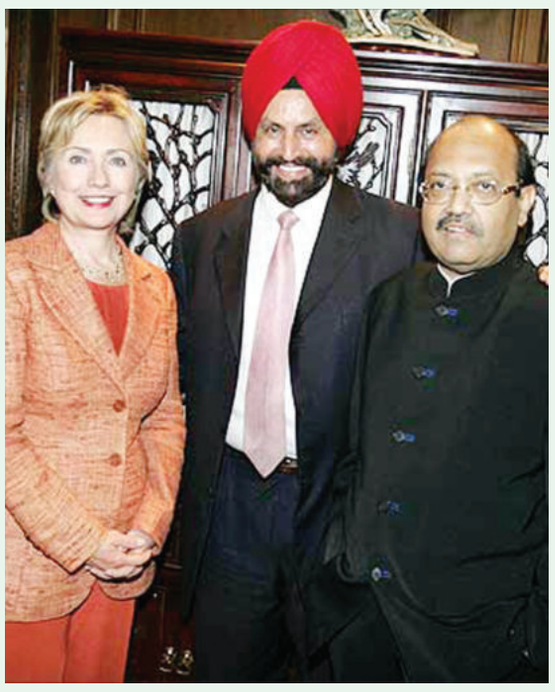

क्लिंटन फाउंडेशन के चार ट्रस्टियों में दो भारतीय हैं. इनमें संत सिंह चटवाल का नाम अव्वल है. चटवाल अमेरिकी सत्ता गलियारे के साथ-साथ भारत और खास तौर पर, उत्तर प्रदेश के सत्ता गलियारे में भी काफी सक्रिय रहे हैं. केंद्र में कांग्रेस शासन के सत्ता अलमबरदारों से चटवाल की काफी निकटता रही है और उत्तर प्रदेश में भी वह तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, सपा के तत्कालीन महासचिव अमर सिंह एवं तत्कालीन पूंजीपति सुब्रत राय सहारा के नज़दीक रहे हैं. स्वनामधन्य संत सिंह चटवाल पर अमेरिका में वित्तीय अपराध और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप हैं. भारतीय मूल के अमेरिकी होटल उद्योगपति संत सिंह चटवाल न्यूयॉर्क की अदालत के सामने ग़ैर-क़ानूनी तरीकों से राजनीतिक चंदा देने का जुर्म स्वीकार कर चुके हैं. उनका रिकॉर्डेड वक्तव्य है कि ग़ैर-क़ानूनी तरीकों से दिए गए पैसों से ही सत्ता तक पहुंच बनती है. सिस्टम में घुसने और उसे खरीदने का यही एकमात्र रास्ता है. चटवाल अमेरिका में कई रेस्तरां और मोटेल चेन के मालिक हैं और हाल तक न्यूयॉर्क के हैंपशायर होटल के मैनेजमेंट बोर्ड के अध्यक्ष थे.न्यूयॉर्क की एक अदालत में चटवाल ने स्वीकार किया था कि उन्होंने 2007 से 2011 के दौरान अपनी जेब से पैसा देकर दूसरे लोगों से चंदा दिलवाया और तीन राजनीतिक उम्मीदवारों के लिए एक लाख अस्सी हज़ार डॉलर तक का चंदा दिया. सरकारी पक्ष का कहना था कि चटवाल ने अपने कर्मचारियों और होटल में काम करने वाले ठेकेदारों के ज़रिये चंदा दिया, जिससे वह प्रशासन के अधिकारियों और कांग्रेस के सदस्यों तक अपनी पहुंच बना सकें. उन पर गवाहों को खरीदने की कोशिश करने जैसे गंभीर आरोप भी थे. चटवाल ने 2008 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डेमोक्रैटिक पार्टी की उम्मीदवारी के लिए बराक ओबामा के ख़िलाफ़ लड़ रही हिलेरी क्लिंटन के लिए एक लाख डॉलर का चंदा जुटाया था. चटवाल की इस स्वीकारोक्ति के बाद तो राजनीतिक हस्तियों में चंदा लौटाने की होड़ लग गई थी. क्लिंटन फाउंडेशन के विवादास्पद ट्रस्टियों में एक और भारतीय का नाम है. वह हैं, विनोद गुप्ता. अमेरिका में डाटाबेस फर्म इन्फोयूएसए के संस्थापक एवं अध्यक्ष विनोद गुप्ता क्लिंटन फाउंडेशन के ट्रस्टी और बिल क्लिंटन के प्रमुख वित्तीय सलाहकार रहे हैं. वर्ष 2008 में उन पर धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगे थे. उन पर आरोप था कि कॉरपोरेट फंड के क़रीब एक करोड़ डॉलर की धनराशि उन्होंने चार्टर विमान से यात्रा करने, निजी क्रेडिट काड्र्स, आलीशान नौका और 20 आलीशान गाड़ियां खरीदने में खर्च कर दी. विनोद गुप्ता ने इन खर्चों में से 40 लाख डॉलर की रकम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के ज़रिये धोखाधड़ी करके समायोजित करा दी. गुप्ता ने बिल क्लिंटन को भी क़रीब 30 लाख डॉलर दिए थे. फाउंडेशन के दो अन्य ट्रस्टियों विक्टर दहडालेह और रोनाल्डो गोंजालेज बन्सटर पर भी गंभीर वित्तीय अपराध के आरोप रहे हैं. ■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 11
दिल्ली, 18 मई-24 मई 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-42296060
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

मराठवाड़ा के गिरमिटिया मज़दूर

पलायन की अंतहीन दास्तां

बीड सहित पूरा मराठवाड़ा लगातार तीन वर्षों से भयंकर सूखे की चपेट में है. सिंचाई के अभाव में फसलें चौपट हो रही हैं. नतीजतन, लागत भी नहीं निकल पा रही है. पानी और चारे की कमी के कारण पशुओं का असमय मरना जारी है. बीड ज़िले से लाखों लोग हर साल गन्ना तोड़ने (काटने) पश्चिम महाराष्ट्र जाते हैं. फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि यहां पहले भूमिहीन मज़दूर काम करते थे, लेकिन अब वैसे किसानों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, जो ख़ुद दस-बारह बीघा ज़मीन के मालिक हैं. यह किस्सा महाराष्ट्र के उस इलाक़े का है, जिसने सूबे को चार मुख्यमंत्री दिए हैं. अव्वल यह कि दूसरे शहरों में काम करने वाले यहां के मज़दूरों की संख्या कितनी है, इसकी मुकम्मल जानकारी स्थानीय ज़िला प्रशासन को भी नहीं है. गन्ना मज़दूरों की दयनीय हालत और किसान आत्महत्या की वजह तलाशने के लिए चौथी दुनिया संवाददाता ने उन गांवों का दौरा किया, जहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं. प्रस्तुत है, इसी विषय पर यह ख़ास रिपोर्ट...

अभिषेक रंजन सिंह

बीड की पहचान मज़दूरों के ज़िले के रूप में होती है. आज़ादी से पहले और आज़ादी के छियासठ वर्षों बाद भी यहां के भूमिहीन मज़दूर सतारा, सांगली, कोल्हापुर और पुणे स्थित गन्ना के खेतों एवं चीनी मिलों में काम करते हैं. मज़दूरों का पलायन बीड की एक बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार, प्रशासन और मीडिया इसे मज़दूरों का पुश्तैनी धंधा मानकर ख़ास तव्वजो नहीं देते. हर साल समूचे मराठवाड़ा से कितनी संख्या में मज़दूर पश्चिमी महाराष्ट्र स्थित गन्ना के खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, इसका कोई सरकारी लेखा-जोखा मौजूद नहीं है. अपने गांव से मीलों दूर काम करने वाले ये मज़दूर कितने सुरक्षित हैं, इसकी कोई जवाबदेही मराठवाड़ा के संबंधित ज़िला प्रशासन और नेताओं पर नहीं है. मराठवाड़ा के गन्ना मज़दूरों की दशा ठीक वैसी ही है, जो कभी मॉरीसश, सूरीनाम एवं फिजी गए मज़दूरों की थी. 180 वर्ष पहले इन देशों के गन्ना खेतों में काम कराने के लिए अंग्रेज बड़ी संख्या में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से मज़दूरों को ले गए थे. आम बोलचाल की भाषा में इन मज़दूरों को गिरमिटिया मज़दूर कहा जाता था. गिरमिटिया मज़दूर एक ऐसा शब्द है, जिससे वर्षों की दासता परिलक्षित होती है. कई दशक पहले मॉरीसश गए इन मज़दूरों की मौजूदा पीढ़ी अब वहां की स्थायी नागरिक है. मॉरीसश के नागरिक हज़ारों मील की भौगोलिक दूरी एवं कई पुश्तों बाद भी भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं. वर्ष 1968 में मॉरीसश एक आज़ाद देश बना और वहां की राजनीति में बिहार मूल के उन्हीं लोगों का वर्चस्व क़ायम हुआ, जिनके पूर्वज कभी गिरमिटिया मज़दूर बनकर मॉरीसश आए थे. सड़सठ साल पहले मराठवाड़ा हैदराबाद के निज़ाम की हुकूमत के अधीन था. देश को आज़ादी भले ही 15 अगस्त, 1947 को मिली, लेकिन मराठवाड़ा 17 सितंबर, 1948 को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना. इन बीते वर्षों में मराठवाड़ा का उतना विकास नहीं हो पाया, जितना महाराष्ट्र के बाक़ी हिस्सों का हुआ. ज़िला कलेक्टर कार्यालय बीड से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है निपानी जवलका. गेवराई तहसील के इस गांव की कुल आबादी 4,000 है. यहां गन्ना मज़दूरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है. चौथी दुनिया का यह संवाददाता पिछले दिनों निपानी जवलका गांव में था. एक पेड़ के नीचे क़रीब दस-पंद्रह लोग बैठे हुए थे. सामने एक घर से महिलाओं के रोने की आवाज़ आ रही थी. यह घर शिवाजी बलिराम काकड़े का था, जिसने 23 अप्रैल, 2015 को अपने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. पचपन वर्षीय शिवाजी की दो पत्नियां और चार बच्चे हैं. पहली पत्नी का नाम कल्पना और दूसरी पत्नी का नाम शांता बाई है. कैलाश, विलास, मनोहर और लता की उम्र पच्चीस वर्ष से अधिक है. लता की शादी नज़दीक के पिंपलगांव में हुई है. जिस घर में दो दिन पहले मौत हुई हो, वहां इस विषय में कोई सवाल पूछना एक पत्रकार के लिए सहज नहीं था.

ग्रामीणों ने बताया कि शिवाजी के पास कुल 12 एकड़ ज़मीन थी. पहले वह गांव में रहकर ही खेती-बाड़ी का काम करते थे, लेकिन लगातार सूखे की वजह से खेती में नुक़सान होने लगा. नतीजतन, शिवाजी सतारा ज़िले की एक चीनी मिल में पलटन (मेठ) का काम करने लगे. दिसंबर, 2014 में शिवाजी अपने गांव के 18 गन्ना मज़दूरों को सदाशिव नगर, सतारा ले गए. वहां चीनी मिलों के लिए गन्ना की ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्टर दादा हरिभाऊ धाईगुरे ने मज़दूर मुहैया कराने के एवज़ में शिवाजी को सात लाख रुपये एडवांस दिए थे. गन्ना पेराई का सीजन ख़त्म होने से पहले शिवाजी पांच लाख रुपये का व्यवसाय कर चुके थे. उनके ऊपर ट्रांसपोर्टर के महज दो लाख रुपये ही बकाया थे. ट्रांसपोर्टर हरिभाऊ को शायद शिवाजी पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए उसने शिवाजी और उनकी पत्नियों के साथ मारपीट की. इतना ही नहीं, शिवाजी जिन 18 मज़दूरों को सदाशिव नगर ले गए थे, उन सबको, उनकी बैलगाड़ियों और 29 जोड़ी बैलों को भी ट्रांसपोर्टर ने बंधक बना लिया. किसी तरह एक लाख पंद्रह हज़ार रुपये का इंतज़ाम कर शिवाजी ने ट्रांसपोर्टर को दिया और बंधक बने मज़दूरों को छुड़ाया. शेष पैंसठ हज़ार रुपये का इंतज़ाम करने के लिए शिवाजी अपने गांव आ गए. गांव वालों का कहना है कि आत्महत्या करने से एक दिन पहले (22 अप्रैल, 2015) शिवाजी ने अपनी पत्नी कल्पना से टेलीफोन पर बात की थी. शिवाजी गांव तो आ गए, लेकिन रुपये का इंतज़ाम न होने की वजह से वह तनावग्रस्त रहने लगे. देर रात ख़बर मिली कि शिवाजी ने अपने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

बंधक बनाए गए मज़दूर गिरिराम भगवान काकड़े ने बताया कि शिवाजी के ऊपर ट्रांसपोर्टर का बहुत बड़ा क़र्ज़ नहीं था, जिस वजह से वह आत्महत्या करते. उनके मुताबिक़, ट्रांसपोर्टर हरिभाऊ एक दबंग किस्म का व्यक्ति है, जिसने स्टांप पेपर पर शिवाजी से एक लिखित एग्रीमेंट बनवा लिया था. संभवत: यही दबाव शिवाजी की ज़िंदगी पर भारी पड़ गया. निपानी जवलका की सरपंच द्वारिका बाई बांगड़ के मुताबिक़, गेवराई पुलिस ने शिवाजी की मौत के बाद ट्रांसपोर्टर हरिभाऊ के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज़ कर ली है, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. ग़ौरतलब है कि आत्महत्या करने वाले मज़दूर शिवाजी के परिवारीजनों को बीड ज़िला प्रशासन की ओर से कोई मुआवज़ा नहीं मिला है, क्योंकि सरकारी नियमों के तहत वह मुआवज़ा पाने के हक़दार नहीं हैं. पिछले पांच वर्षों से गन्ना काटने का काम कर रहे संजय गिरधारी लोनकर ने बताया कि वह हर साल दिसंबर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सतारा जाते हैं. एक टन गन्ना काटने और उसे लोड करने के एवज़ में 212 रुपये मिलते हैं. एक मज़दूर औसतन डेढ़ टन गन्ना प्रतिदिन काटता और लोड करता है. सतारा ज़िले के गन्ना खेतों में काम करने वाले राम किशन काकड़े बताते हैं कि पश्चिम महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा मज़दूर जाते हैं. अकेले बीड ज़िले में यह संख्या क़रीब पांच लाख से अधिक है. कृष्णा भापकर की मानें, तो गन्ना मज़दूरों की इस बढ़ती संख्या की मूल वजह है, इलाक़े में लगातार तीन वर्षों से सूखा पड़ना. यही कारण है कि शिवाजी बलिराम काकड़े जैसे किसान भी दूसरों के खेतों में मज़दूरी करने को विवश हो रहे हैं. निपानी जवलका में इससे पहले भी किसान आत्महत्या की घटनाएं हो चुकी है. 8 अगस्त, 2014 को साठ वर्षीय बुजर्ग किसान सर्जे राव बापू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. उनके पास 11 एकड़ ज़मीन थी. महाराष्ट्र बैंक से तीन साल पहले सर्जे राव ने चालीस हज़ार रुपये का क़र्ज़ लिया था. सूखे और ओलावृष्टि की वजह से उनकी फ़सल नाक़ाम हो गई. बैंक के बढ़ते क़र्ज़ और तगादे से आजिज होकर उन्होंने अपनी जान दे दी.

मराठवाड़ा जाने से पहले दिल्ली के एक पत्रकार साथी ने बताया कि अक्षय तृतीया के समय बीड ज़िले के गांवों में चहल-पहल बढ़ जाती है, क्योंकि बाहर काम करने वाले मज़दूर इस दौरान अपने गांव लौट आते हैं. अक्षय तृतीया के बाद शादी के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं. वैसे चौथी दुनिया संवाददाता को निपानी जवलका में उत्सवी माहौल नहीं दिखा. इस बारे में किरण लोनकर बताते हैं कि पहले अक्षय तृतीया के मौक़े पर काफ़ी संख्या में बाहर गए मज़दूर वापस लौटते थे, लेकिन पिछले तीन वर्षों से मज़दूरों की हालत काफ़ी ख़राब है. चूंकि पहले के मुक़ाबले शादियां अब महंगी हो गई हैं, इसलिए मज़दूर और किसान अपने बच्चों की शादी देर से करने लगे हैं. मराठवाड़ा में निपानी जवलका जैसे हज़ारों गांव हैं, जहां शिवाजी जैसे कई लाचार मज़दूर और किसान क़र्ज़ से परेशान हैं. ऐसा नहीं है कि सरकार एवं प्रशासन को इन मज़दूरों की दयनीय स्थिति के बारे में जानकारी न हो. दरअसल, प्रशासन जीते जी इन मज़दूरों की ख़ोज-ख़बर नहीं लेती. और, जब आर्थिक तंगी एवं शोषण के चलते कोई मज़दूर आत्महत्या करता है, तब जाकर प्रशासनिक अमला इलाके का दौरा करता है तथा अगले दिन अख़बारों में उसकी ख़बर-तस्वीर छपती है. यह मालूम होने पर कि मरने वाला शख्स किसी दूसरे ज़िले में मज़दूरी करता था और उसके पास कोई ज़मीन नहीं थी, उसे सरकारी मुआवज़े से वंचित कर दिया जाता है.

बीड ज़िले का निपानी जवलका गांव : गन्ना मज़दूर बलिराम काकड़े का शोकाकुल परिवार.

बीड ज़िले का भेंडटाकली गांव : स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र धर्मराज ने फ़सल नाक़ाम होने के कारण आत्महत्या कर ली.

सूखाग्रस्त मराठवाड़ा में पलायन की ऐसी तस्वीर प्रायः देखी जा सकती है.

ज़मीन नहीं, तो मुआवज़ा नहीं

भूमिहीन मज़दूरों के लिए महाराष्ट्र सरकार की कोई मुआवज़ा नीति नहीं है. भूमिहीन मज़दूरों एवं किसानों के साथ यह भेदभाव पूरे देश में हो रहा है, लेकिन सरकार इस समस्या के प्रति तनिक भी गंभीर नहीं दिखती. चौथी दुनिया के इस संवाददाता ने भूमिहीन मज़दूरों एवं किसानों के आत्महत्या करने और उसके बाबत मुआवज़े के बारे में मराठवाड़ा क्षेत्र के छह ज़िला कलेक्टरों से सवाल पूछे, लेकिन सभी कलेक्टर इस मुद्दे पर ख़ामोश रहे. भूमिहीन किसानों और मज़दूरों के साथ हो रहे इस अन्याय के प्रति सिर्फ़ महाराष्ट्र सरकार ही जवाबदेह नहीं है, बल्कि इसके लिए सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जवाबदेह हैं. देश के मूल किसानों की उपेक्षा सभी सरकारें करती आई हैं. किसानों की मौत और मुआवज़े को लेकर भेदभाव एक बड़ा प्रश्न बन चुका है. केंद्र सरकार को चाहिए कि वह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके उनसे पूछे कि उनके यहां ऐसे किसानों की संख्या कितनी है, जो भूमिहीन हैं.

स्वतंत्रता सेनानी के किसान बेटे ने की आत्महत्या

गेवराई तहसील में ही एक गांव है भेंडटाकली. निपानी जवलका की तुलना में यहां की आबादी ज़्यादा है. बीते 17 फरवरी को महा-शिवरात्रि के दिन चौवन वर्षीय किसान धर्मराज पांडुरंग शिंदे ने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. चौथी दुनिया का यह संवाददाता जब धर्मराज के घर पहुंचा, तो उसकी मां हौसा बाई अपने पोते और पोतियों के साथ आंगन में बैठी थी. बातचीत में उन्होंने बताया कि धर्मराज के पास 30 एकड़ ज़मीन थी. इन खेतों में धर्मराज ने सोयाबीन, कपास और अरहर की खेती की थी, लेकिन सूखे की वजह से फ़सल बर्बाद हो गई. धर्मराज ने खेती के लिए बैंक से डेढ़ लाख रुपये बतौर क़र्ज़ लिए थे. लगातार तगादे की वजह से उसने अपनी गाय और बैल को भी बेच दिया, लेकिन क़र्ज़ से मुक्ति नहीं मिली. धर्मराज की मां ने बताया कि उनके पति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें सम्मान-पत्र भी दिया था. उनकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वह भावुक हो गईं. उन्होंने कहा कि हमारे परिवार ने देश की आज़ादी के लिए इतने कष्ट सहे, लेकिन सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया. धर्मराज की दो पत्नियां हैं शारदा और जयश्री. ये दोनों बीड में रहती हैं, क्योंकि सूखे की वजह से खेती का काम बंद है. नतीजतन, धर्मराज के चारों बेटे वहां रहकर छोटा-मोटा काम करते हैं.

स्कूलों में होती है अघोषित छुट्टी

निपानी जवलका की ग़रीबी और पिछड़ापन मराठवाड़ा के बाकी गांवों की तरह ही है. गांव में ज़िला परिषद के प्राइमरी स्कूल पर नज़र पड़ी. विभागीय रजिस्टर में स्कूल खुला ज़रूर था, लेकिन वहां न तो शिक्षक थे और न छात्र. स्कूल के बाहर खड़े एक युवक ने कहा कि सभी बच्चे पानी लाने गए हैं, क्योंकि अभी-अभी एक टैंकर आया है. टैंकर आने पर यहां के स्कूलों में अघोषित छुट्टी कर दी जाती है. स्कूल के बगल में ही एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है. वहां न तो कोई डॉक्टर दिखा और न कोई मरीज. गांव वालों ने बताया कि अगर किसी दिन कोई डॉक्टर पहुंच भी जाए, तो उसके पास मरीज को देने के लिए दवा नहीं होती.

मज़दूर महिलाओं की आबरू सुरक्षित नहीं

गन्ना खेतों में काम करने वाले मज़दूरों के शोषण की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती. खेतों में काम करने वाली महिलाओं एवं बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की कई घटनाएं सामने आई हैं. ज़्यादातर मज़दूर डर की वजह से इसकी शिकायत नहीं करते. गन्ना खेतों में काम करने वाली उन महिला मज़दूरों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं. मज़दूर अमूल शिंदे बताते हैं कि गन्ना खेतों में कई प्रकार के ज़हरीले सांप रहते हैं, लेकिन मज़दूरों को न तो जूता मुहैया कराया जाता है और न दस्ताने. सांप के काटने की वजह से कई मज़दूरों की मौत हो चुकी है, इस ओर न तो सरकार ध्यान देती है और न नियोजक. ■

arsingh@chauthiduniya.com

राजधानी दिल्ली में आए दिन भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध करने एवं उसे रद्द करने की मांग को लेकर किसान और राजनीतिक संगठन जुट रहे हैं. हर तरफ़ एक आवाज़ सुनाई दे रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार कॉरपोरेट्स के लिए काम कर रही है, किसान उसके विकास के एजेंडे में नहीं है. एक तरफ़ किसान सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ़ संसद में विपक्षी दल एकजुट होकर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं और सरकार से पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन–सा राष्ट्रवाद है, ऐसा कौन–सा विकास है, जो कि सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति लेना ग़ैर–ज़रूरी समझती है.

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के ख़िलाफ़

किसान गोलबंद हो रहे हैं

नवीन चौहान

बीते पांच मई को दिल्ली के संसद मार्ग पर देश भर से आए तीन सौ जन–संगठनों एवं राजनीतिक दलों ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में एक बार फिर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में मुख्य रूप से वामदलों के किसान एवं मज़दूर संगठनों ने शिरकत की और सरकार को चुनौती दी कि वह भले ही संसद में अध्यादेश किसी भी तरह पारित करा ले, लेकिन किसान किसी भी क़ीमत पर उसे देश में लागू नहीं होने देंगे. इस भूमि अधिकार संघर्ष रैली में शामिल होने महाराष्ट्र के रायगढ़ से आईं उल्का महाजन ने कहा कि कृषि भूमि और मुआवज़े के बीच कोई संबंध नहीं है. यदि आज किसान कमज़ोर है, तो उसकी वजह कृषि नीति है और किसानों के साथ हुए खिलवाड़ का परिणाम है. गुजरात के लोक संघर्ष मोर्चा की प्रतिभा शिंदे ने कहा कि सरकार को शुक्र मनाना चाहिए कि किसान अभी तक विरोध करने नहीं उतरे हैं. एक इंच ज़मीन को लेकर आमने–सामने की लड़ाई हो जाती है, लोग एक–दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं. इसलिए सरकार को किसानों के संयम की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए. उत्तर प्रदेश के कन्हर बांध का विरोध कर रहीं सुकालो देवी गौड़ ने कहा कि ज़मीन हमारे पुरखों की है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे और किसी को छीनने नहीं देंगे. हमें अपनी लड़ाई के लिए किसी नेता की ज़रूरत नहीं है, हम दिखा देंगे कि हमारे अंदर कितना दम है. यदि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमआईडीसी) के आंकड़ों पर ग़ौर करें, तो महाराष्ट्र में अधिग्रहीत की जा चुकी ज़मीन का 50 प्रतिशत हिस्सा अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है. सरकार के पास पहले से ही हज़ारों एकड़ अधिग्रहीत ज़मीन है. बावजूद इसके, यदि सरकार कोई सख्त फ़ैसला लेती है, तो वह क़ानून संभालेगी, लोग अपनी ज़मीन संभालेंगे. दरअसल, किसान कृषि से नहीं, कृषि नीतियों से परेशान हैं. किसानों का कहना है कि सरकार भले ही चार गुना मुआवज़ा देने की बात कह रही है, लेकिन रुपये की क़ीमत में भी तो लगातार गिरावट आ रही है. राजधानी दिल्ली में आएदिन भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध करने एवं उसे रद्द करने की मांग को लेकर किसान और राजनीतिक संगठन जुट रहे हैं. हर तरफ़ एक आवाज़ सुनाई दे रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार कॉरपोरेट्स के लिए काम कर रही है, किसान उसके विकास के एजेंडे में नहीं है. एक तरफ़ किसान सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ़ संसद में विपक्षी दल एकजुट होकर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं और सरकार से पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन–सा राष्ट्रवाद है, ऐसा कौन–सा विकास है, जो कि सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति लेना ग़ैर–ज़रूरी समझती है.

राजधानी दिल्ली में आएदिन भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध करने एवं उसे रद्द करने की मांग को लेकर किसान और राजनीतिक संगठन जुट रहे हैं. हर तरफ़ एक आवाज़ सुनाई दे रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार कॉरपोरेट्स के लिए काम कर रही है, किसान उसके विकास के एजेंडे में नहीं है. एक तरफ़ किसान सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ़ संसद में विपक्षी दल एकजुट होकर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं और सरकार से पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन-सा राष्ट्रवाद है, ऐसा कौन-सा विकास है, जो कि सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति लेना ग़ैर-ज़रूरी समझती है.

गत 24 फरवरी को देश के कई किसान–मज़दूर और जन संगठनों ने साथ मिलकर दिल्ली में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के ख़िलाफ़ लड़ाई का शंखनाद किया था. अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में बजट सत्र की शुरुआत में आयोजित इस रैली का असर संसद के अंदर भी दिखाई पड़ा था. सरकार ने अपने क़दम थोड़े पीछे खींचे थे और 31 दिसंबर के अध्यादेश को नौ संशोधनों के साथ लोकसभा में पारित किया था. एक मुख्य संशोधन करते हुए सरकार ने रेल एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण के लिए ली जा रही तीन किलोमीटर ज़मीन के प्रावधान में संशोधन कर उसे एक किलोमीटर कर दिया. सरकार भी जानती है कि ज़मीन किसान को दो वक्त की रोटी के साथ–साथ पीढ़ी दर पीढ़ी आजीविका मुहैया कराती है. सरकार किसानों की ज़मीन तो ले सकती है, लेकिन वह उनके परिवार को स्थायी समाधान देने में सक्षम नहीं है. यही इस भूमि अधिग्रहण के मसले की मूल जड़ है. सरकार भले ही किसानों को उनकी ज़मीन के बदले बाज़ार मूल्य का चार गुना मुआवज़ा देने की बात कह रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाजपा शासित राज्यों में सरकारें किसानों की उपजाऊ ज़मीन का अधिग्रहण कर उन्हें महज दो से ढाई गुना मुआवज़ा दे रही हैं. हालांकि, अध्यादेश का विरोध करने वालों पर आरोप लग रहे हैं कि जिन्हें अपने खेतों के नंबर तक नहीं मालूम हैं, वे किसानों के हितों की बात कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं. ऐसे में अंदाज़ा हो जाता है कि यह आंदोलन कितनी दूर तक जाएगा.

अधिकांश किसान एवं राजनीतिक संगठनों का कहना है कि 2013 का क़ानून चूंकि सबकी राय लेकर बनाया गया था, इसलिए मजबूरी में उसे स्वीकार करना पड़ा. तब लोगों ने सोचा था कि आने वाले समय में इसमें सकारात्मक बदलाव होंगे, लेकिन अच्छे दिन लाने का वादा करने वाली मोदी सरकार ने किसानों की सहमति जैसा प्रावधान भी क़ानून से बाहर कर दिया. ग़ौरतलब है कि 2013 का क़ानून एक दशक तक चले देशव्यापी परामर्श और संसद में भाजपा के नेतृत्व वाली दो स्थायी समितियों में बड़े पैमाने पर हुई बहस के बाद बना था. उस वक्त वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन संसद की स्थायी समिति की अध्यक्ष थीं और उस क़ानून की समर्थक थीं. लेकिन, सत्ता में आते ही भाजपा की विचारधारा बदल गई और वह लोकतांत्रिक ढांचे की अनदेखी करके 1894 वाले क़ानून की ओर लौट रही है. सरकार ज़मीन अधिग्रहण अध्यादेश को यह कहकर देशहित में ज़रूरी बता रही है कि इसका मकसद धीमी पड़ी विकास दर तेज करना और वे परियोजनाएं शुरू करना है, जो रुकी हुई हैं. लेकिन, सूचना का अधिकार क़ानून के अंतर्गत प्राप्त जानकारी के अनुसार, फिलहाल कुल 804 परियोजनाएं रुकी हुई हैं, जिनमें से 78 प्रतिशत निजी परियोजनाएं हैं. इनमें केवल आठ प्रतिशत यानी 66 परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण की वजह से रुकी हैं, जबकि अधिकांश परियोजनाएं फंड की कमी या अन्य कारणों की वजह से बंद हैं. ऐसे में, ज़रूरी परियोजनाओं के लिए रास्ता बनाने की बात कहकर देश के ग़रीबों, किसानों एवं मज़दूरों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? सरकार यह अध्यादेश पारित करने में रुचि तो दिखा रही है, लेकिन लोगों तक अपनी बात सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रही है. जबकि विरोधी दल अपनी बात किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश शहरी क्षेत्रों तक सीमित है या उन क्षेत्रों में, जहां लोग पहले से भूमि अधिग्रहण से पीड़ित हैं. विरोधी दल उन किसानों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जो सरकार की भविष्य की योजनाओं से प्रभावित होने वाले हैं. ऐसे में, आंदोलन का दायरा बढ़ता नहीं दिख रहा, बल्कि घूम–फिर कर गिने–चुने लोगों के बीच सिमट गया है. सरकार देश की ग़ैर सरकारी संस्थाओं को मिलने वाले विदेशी अनुदान पर भी नकेल कस रही है, उसका असर भी आंदोलन पर दिखाई पड़ रहा है. आंदोलन से जुड़े लोग इसे सरकार की सोची–समझी रणनीति बता रहे हैं. जाहिर है, बिना अनुदान कोई आंदोलन नहीं चल सकता. यदि संस्थाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता ही बंद हो जाएगी, तो वे बिना पानी की मछली की तरह हो जाएंगी.

रैली को संबोधित करते हुए वाम नेता अतुल अंजान ने कहा कि अपनी जड़ों और ज़मीन से उखड़ा आदमी दोबारा नहीं बस पाता है. उन्होंने भाजपा के सांसदों का आह्वान करते हुए कहा कि वे अंतर्आत्मा की आवाज़ सुनें और संसद में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पारित न होने दें. जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के पवन वर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में और किसानों के साथ है. जिस देश के साठ प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हों, वहां की तरक्की किसानों को नज़रअंदाज़ करके कैसे हो सकती है. सीपीआई के डी राजा ने कहा कि मोदी सरकार केवल संघर्ष की भाषा सुनेगी. हम साझा मोर्चा बनाकर भूमि अधिग्रहण का विरोध करेंगे. मेधा पाटकर ने कहा कि देश का संविधान जीने का अधिकार देता है, लेकिन यदि किसानों से आजीविका का अधिकार छीन लिया जाएगा, तो वे जी नहीं पाएंगे. गुजरात मॉडल ग़रीबों, किसानों, मज़दूरों के ख़िलाफ़ है, हम उसे देश में नहीं लागू होने देंगे. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल सिर्फ़ अध्यादेश का विरोध न करें, बल्कि किसानों–मज़दूरों के साथ खड़े भी हों.■

navinonline2003@gmail.com

फोटो : सुनील मल्होत्रा

भूमि अधिकार आंदोलन के लिए बनी कमेटी

मेधा पाटकर, हनन मौला, अतुल अंजान, डॉ सुनीलम, अशोक चौधरी, प्रफुल्ला सामंतरा, राकेश रफीक, दयामनी बरला, उल्का महाजन, दर्शन पाल सिंह, मंजीत सिंह, रोमा, हरपाल सिंह राणा, अनिल चौधरी, विनोद सिंह, रजनीश गंभीर, प्रतिभा शिंदे, अक्षय, वीरेंद्र विद्रोही, सत्यवान, कैलाश मीना, महावीर गुलिया, अमूल्य नायक, आलोक शुक्ला, त्रिलोचन पूंजी, राजिम, उमेश तिवारी, ईश्वर चंद्र त्रिपाठी, एमएस सेल्वाराज, एम इलांगो, रामकृष्ण राजू, हंसराज धेवरा, भूपिंदर सिंह रावत, सागर रबारी, जसबीर सिंह, विजू कृष्णन, मधुरेश कुमार, श्वेता त्रिपाठी, सत्यम श्रीवास्तव, राघीव असीम, संजीव कुमार, प्रताप चौधरी.

वामदल और तृणमूल एक साथ

कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता. बीते पांच मई को संसद मार्ग पर यह बात साबित हो गई. पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव में रिकॉर्ड सफलता हासिल करने के बाद विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर कमर कस ली है. सत्ता पर बने रहने के लिए उसे अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ मंच साझा करने से भी गुरेज नहीं है. नंदीग्राम के भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ आंदोलन करके राज्य की सत्ता पर काबिज हुई तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर वापसी करती दिख रही है. उसके सांसद पहले ही भूमि अधिग्रहण का कभी संसद में काले छाते ले जाकर, तो कभी मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध कर चुके हैं. वामदलों और जन संगठनों के इस कार्यक्रम में तृणमूल सांसद डोला सेन ने कहा कि हम सभी को ममता बनर्जी का कृतज्ञ होना चाहिए. यदि सिंगुर और नंदीग्राम न हुआ होता, तो 2013 का भूमि अधिग्रहण क़ानून न बना होता. तृणमूल कांग्रेस सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के ख़िलाफ़ है. हम हमेशा इस मुद्दे पर किसानों के साथ हैं. दूसरी ओर निकाय चुनाव परिणाम की वजह से अधिकांश वामदल एक साथ नज़र आए. सीपीआई (एम) के नवनियुक्त महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि यह हमारी प्रतिज्ञा है, संकल्प है कि हम किसी भी सूरत में इस बिल को पास नहीं होने देंगे. ज़मीन पर हो रही लड़ाई से हमें ताकत मिलती है. आप ज़मीनी स्तर पर ज़मीन की लड़ाई लड़ते रहिए, हम संसद में आपकी ताकत दिखाते रहेंगे.

किसान हित से खिलवाड़

24–25 फरवरी को दिल्ली के जंतर–मंतर से समाजसेवी अन्ना हजारे ने मोदी सरकार के ख़िलाफ़ हुंकार भरी थी. उन्होंने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लेने की मांग करते हुए कहा था कि यदि सरकार अपने क़दम पीछे नहीं खींचेगी और किसानों के साथ अन्याय करेगी, तो वह देश भर में पदयात्रा करेंगे और जेल भरो आंदोलन चलाएंगे. उन्हें किसानों की लड़ाई का चेहरा बनाने वाले जन संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली के संसद मार्ग पर प्रदर्शन करके सरकार को चुनौती दी, लेकिन अन्ना मौन नज़र आए. उनकी तरफ़ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. अन्ना ने वर्धा से पीवी राजगोपाल के साथ शुरू की गई पदयात्रा स्थगित करने केबाद सिर्फ़ इस विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया है और उनसे कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं. दो अप्रैल को दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में जन संगठनों एवं राजनीतिक दलों के बीच हुए विमर्श के बाद अन्ना ने पुणे में एक बैठक भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलन चलाने के लिए बुलाई. बैठक में कई तरह की चर्चाएं हुईं, लेकिन जब बात नया संगठन बनाने को लेकर हुई, तो अन्ना ने मना कर दिया. बैठक में शामिल हुए कुछ लोगों का कहना है कि अन्ना को डर है कि लोग उन्हें धोखा देकर अपने–अपने राजनीतिक हित साधेंगे और वह ऐसा नहीं चाहते. दरअसल, बार–बार बिना कोई स्पष्ट वजह के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर देने से अन्ना की विश्वसनीयता कम हो रही है. राजनीतिक लोगों के साथ मंच साझा न करने की बात करने वाले अन्ना ने 24–25 फरवरी के कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मंच साझा किया, तब जन संगठनों ने इसका विरोध किया था. इसी वजह से अन्ना को आगे के कार्यक्रमों में शामिल न करने का निर्णय जन संगठनों ने किया. आंदोलन के किसी भी व्यक्ति ने खुलकर भले अपनी बात नहीं रखी, लेकिन अन्ना को धीरे से आंदोलन से सोची–समझी रणनीति के तहत अलग कर दिया गया. पीवी राजगोपाल का आरएसएस के गोविंदाचार्य केसाथ काम करना भी जन संगठनों को रास नहीं आया. इसलिए उन्हें भी भूमि अधिग्रहण आंदोलन से अलग कर दिया गया. राजगोपाल ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 26 से 29 अप्रैल तक भूख हड़ताल का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें चंद लोगों ने भागीदारी की, लेकिन उनकी आवाज़ भोपाल से दिल्ली नहीं पहुंची. गुजरात से आई एक महिला ने कहा कि अन्ना ने राहुल गांधी के लिए माहौल बनाया है. ऐसा न होता, तो राहुल गांधी के अज्ञातवास से लौटने के बाद अन्ना अचानक शांत न हो जाते. अन्ना 23 मार्च को पंजाब के हुसैनीवाला स्थित भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की समाधि पर गए थे. उसी दौरान किसानों के लिए उनकी एक रैली होनी थी, लेकिन उसे भी बिना कोई कारण बताए स्थगित कर दिया गया. आंदोलनों से लंबे समय तक जुड़े रहे स्वामी अग्निवेश जैसे लोग मंच के आस–पास भटकते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें अपनी बात रखने का मौक़ा नहीं दिया.

बिहार में कमाने के लिए परदेस जाने का इतिहास बहुत पुराना है. इसकी झलक यहां के लोक गीतों में भी मिल जाती है. पहले अपना गांव–शहर छोड़कर बाहर कमाने जाने वालों में समाज के पिछड़े वर्ग के लोग ज़्यादा थे. लेकिन, सवर्ण आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले कुछ दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों की अगड़ी जातियों में कमाने के लिए बाहर जाने का चलन बढ़ा है. ग्रामीण इलाकों में रोज़गार या रोज़गार के बेहतर अवसर के लिए 85.8 फ़ीसद हिंदू और 90.5 फ़ीसद मुसलमान बाहर जाते हैं. शहरों की कहानी में बहुत ज़्यादा फ़र्क़ नहीं है, संख्या कुछ कम ज़रूर है.

सवर्ण आयोग ने खोला अगड़ी जातियों का ज़मीनी सच

रोटी और रोज़गार के लाले

बिहार की ऊंची जातियों में शिक्षा की सच्चाई यह है कि उनके बीच साक्षरता दर सबसे अधिक होने के बावजूद शिक्षा का स्तर नीचे है. दूसरी ओर ग्रामीण बिहार में ग़रीबी के चलते हिंदुओं की ऊंची जातियों के 49 फ़ीसद और मुसलमानों के 61.8 फ़ीसद बच्चे स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते. दोनों धर्मों में ऊंची जातियों के कुल 55.8 फ़ीसद बच्चे स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते और उसकी वजह ग़रीबी है. शहरों में स्कूल-कॉलेज न जाने वाले ऐसे बच्चों की तादाद 55.6 फ़ीसद है. ऊंची जातियों के बीच हायर सेकेंड्री और स्नातक से ज़्यादा शिक्षित लोगों की संख्या कम है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच हायर सेकेंड्री करने वाली आबादी महज 31.2 फ़ीसद है, जबकि शहरी इलाकों में 52.1 फ़ीसद. इसका मतलब यह है कि ऊंची जातियों के बीच उच्च शिक्षा की पहुंच नहीं बन पाई है.

सरोज सिंह

मोटे तौर पर अभी तक यह माना जाता है कि अगर आप अगड़ी जाति के हैं, तो कम से कम आपको खाने और पीने की दिक्कत नहीं होगी, रहन-सहन का स्तर ठीक होगा और परिवार के लोगों की पढ़ाई-लिखाई अच्छी होगी. सरकार की नीतियां भी इसी सोच से प्रभावित होती रही हैं और इसलिए कल्याणाकारी योजनाओं का जो लाभ दलितों एवं अति पिछड़ों को मिलता आया है, उससे अगड़ी जातियों को यह सोचकर वंचित रखा गया कि उन्हें उनकी ज़रूरत नहीं है. छात्रवृत्ति से लेकर नौकरियों में आरक्षण तक में अगड़ी जातियों को हिस्सेदारी नहीं दी गई. लेकिन, अगड़ी जातियों की आर्थिक एवं शैक्षणिक हक़ीक़त से जब पर्दा धीरे-धीरे उठने लगा, तो सरकारी सोच पर ही प्रश्नचिन्ह लग गया. इस सच को उजागर करने में एस-4 जैसे संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अब जब सवर्ण आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो यह साफ़ हो गया कि अगड़े केवल नाम के ही अगड़े हैं, हक़ीक़त में उनकी बड़ी आबादी तो रोटी और रोज़गार के लिए तरस रही है. एस-4 के अगुवा राम बिहारी सिंह कहते हैं, वर्षों से जो बात मैं कह रहा था, आज वह सच साबित हुई. अगड़ी जातियों में जो पिछड़ापन है, उसे देखने की इच्छाशक्ति राजनेताओं को पैदा करनी होगी. दलितों और अति पिछड़ों की तरह अगड़ी जातियों के लोग भी बहुत सारी दिक्कतों से रोज़ाना रूबरू हो रहे हैं. एस-4 के माध्यम से मैंने इस ओर सरकार का ध्यान खींचने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय उसका ग़लत अर्थ निकाल लिया गया. अब जब सवर्ण आयोग की रिपोर्ट आ गई है, तो सरकार को जल्द से जल्द उसकी सिफारिशें अमल में लानी चाहिए, ताकि यह तबका भी सम्मान के साथ जीने का हक़ हासिल कर सके.

ग़ौरतलब है कि हिंदुओं एवं मुसलमानों में अगड़ी जातियों की शैक्षणिक व आर्थिक स्थितियों का पता लगाने के लिए नीतीश सरकार ने 27 जनवरी, 2011 को सवर्ण आयोग का गठन किया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश डीके त्रिवेदी इस आयोग के अध्यक्ष थे. जानकारी के अनुसार, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐतिहासिक कारणों से ऊंची जाति के लोगों के बीच जो प्रतिकूल हालात हैं, उस पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है. इसलिए अब उस पर मन बदलने की ज़रूरत है. प्रतिकूल स्थितियों में रह रहे लोगों पर कल्याणकारी योजनाओं के ज़रिये विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है और उसकी कमाई के रास्ते कम होते जा रहे हैं. हिंदू एवं मुसलमानों की अगड़ी जातियों में काम करने वाली कुल आबादी के एक चौथाई यानी 25 फ़ीसद हिस्से के पास रोज़गार नहीं है. हिंदुओं में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी भूमिहारों में है. इस जाति के औसतन 11.8 फ़ीसद लोगों के पास रोज़गार नहीं है. रोज़गार के मौक़े न पैदा होने की वजह से अगड़ी जातियों के कई परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है.

राज्य सवर्ण आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगड़ी जातियों में काम करने वाली आबादी (रोज़गार एवं बेरोज़गारों को मिलाकर) हिंदुओं में 46.6 फ़ीसद और मुसलमानों में 43 फ़ीसद है. यह आंकड़ा वर्ष 2011 की जनगणना में काम करने वाली कुल आबादी 44.9 फ़ीसद के क़रीब है. रिपोर्ट में शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच बेरोज़गारी का स्तर क़रीब-क़रीब एक समान बताया गया है. शहरी इलाकों में बसने वाली हिंदुओं की कायस्थ जाति में बेरोज़गारी का स्तर 14.1 फ़ीसद है, जो अन्य अगड़ी जातियों की तुलना में सर्वाधिक है. मुसलमानों में सैयद सबसे ज़्यादा (11.3 फ़ीसद) बेरोज़गार हैं. लेकिन, इन दोनों जातियों में शिक्षा का स्तर दूसरी जातियों की तुलना में कहीं ज़्यादा है. शहरी इलाके की ऊंची जातियों में शिक्षित बेरोज़गारों की तादाद सबसे ज़्यादा बताई गई है, खासकर कायस्थ और सैयद में. भूमिहार ग्रामीण इलाकों में 13.2 फ़ीसद और शहरी इलाकों में 10.4 फ़ीसद बेरोज़गार हैं. 2011 की जनगणना के मुताबिक, ग्रामीण इलाकों में कामकाजी महिलाओं की आबादी 20.2 फ़ीसद है. लेकिन, हिंदुओं और मुसलमानों की ऊंची जातियों में कामकाजी महिलाओं की आबादी महज 2.6 फ़ीसद है. इसका मतलब है कि सामाजिक चलन के हिसाब से ऊंची जातियों की महिलाओं द्वारा काम करना अच्छा नहीं माना जाता है. रिपोर्ट के अनुसार, बेरोज़गारी के चलते ऊंची जातियों को आर्थिक नुक़सान उठाना पड़ रहा है. शहरी इलाकों में ऊंची जातियों में कामकाजी महिलाओं की आबादी हिंदुओं में 7.6 फ़ीसद और मुसलमानों में 7.4 फ़ीसद है.

ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ऊंची जाति के परिवारों के पास औसतन कृषि योग्य भूमि का रकबा 1.91 एकड़ (हिंदू) और 0.45 एकड़ (मुस्लिम) है. अगर हिंदुओं की ऊंची जातियों के बीच देखें, तो भूमिहार ऐसी बिरादरी है, जिसके पास कृषि योग्य भूमि औसतन प्रति परिवार 2.96 एकड़ है. राजपूतों में 1.99 एकड़, ब्राह्मणों में 1.40 एकड़ और कायस्थों में 1.01 एकड़ प्रति परिवार का औसत है. दूसरी ओर मुसलमानों की ऊंची जातियों में पठान के पास प्रति परिवार औसतन कृषि योग्य ज़मीन 0.48 एकड़ है, जबकि शेख के पास 0.46 और सैयद के पास 0.37 एकड़ ज़मीन प्रति परिवार है.

बिहार की ऊंची जातियों में शिक्षा की सच्चाई यह है कि उनके बीच साक्षरता दर सबसे अधिक होने के बावजूद शिक्षा का स्तर नीचे है. दूसरी ओर ग्रामीण बिहार में ग़रीबी के चलते हिंदुओं की ऊंची जातियों के 49 फ़ीसद और मुसलमानों के 61.8 फ़ीसद बच्चे स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते. दोनों धर्मों में ऊंची जातियों के कुल 55.8 फ़ीसद बच्चे स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते और उसकी वजह ग़रीबी है. शहरों में स्कूल-कॉलेज न जाने वाले ऐसे बच्चों की तादाद 55.6 फ़ीसद है. ऊंची जातियों के बीच हायर सेकेंड्री और स्नातक से ज़्यादा शिक्षित लोगों की संख्या कम है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के बीच हायर सेकेंड्री करने वाली आबादी महज 31.2 फ़ीसद है, जबकि शहरी इलाकों में 52.1 फ़ीसद. इसका मतलब यह कि ऊंची जातियों के बीच उच्च शिक्षा की पहुंच नहीं बन पाई है. ऊंची जातियों के हिंदुओं और मुसलमानों के पास ज़मीन तो है, लेकिन इतनी नहीं कि उन्हें पूर्ण रूप से रोज़गार मुहैया करा सके. उन्हें जीवनयापन के लिए अन्य कार्यों पर निर्भर रहना पड़ता है. यह हक़ीक़त ग्रामीण के साथ-साथ शहरी इलाकों की भी है. राज्य सवर्ण आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में ऊंची जातियों के पास ज़मीन तो है, लेकिन वह इतनी ज़्यादा नहीं है कि सभी को काम मिल सके.

ग्रामीण इलाकों में 18.1 फ़ीसद ऊंची जाति के हिंदुओं को पूर्ण रोज़गार की श्रेणी में रखने के लिए खेती के इतर दूसरे सहायक काम करने की ज़रूरत है. ऊंची जाति के मुसलमानों में ऐसे लोग 11.8 फ़ीसद हैं. शहरी इलाकों की दास्तां इससे भिन्न नहीं है. शहरों में भी ऊंची जाति के लोग अपने पुश्तैनी या परंपरागत रोज़गार से इतर अन्य कार्यों से संबद्ध हैं. आम धारणा है कि बिहार की ऊंची जातियों के पास ही ज़मीन का रकबा ज़्यादा है, लेकिन सवर्ण आयोग की रिपोर्ट इस धारणा को खंडित करती है. हिंदुओं की ऊंची जाति के 55.1 फ़ीसद और मुसलमानों की ऊंची जाति के 86.1 फ़ीसद परिवारों के पास ज़मीन का मामूली टुकड़ा है. ये ऐसे परिवार हैं, जिनके पास एक एकड़ से भी कम ज़मीन है. इसका अर्थ है कि हिंदुओं और मुसलमानों की अत्यंत छोटी आबादी का ज़मीन के बड़े भाग पर एकाधिकार है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पांच एकड़ तक कृषि योग्य भूमि रखने वाले ऊंची जाति के हिंदू परिवार मात्र 8.6 फ़ीसद और मुसलमान परिवार 1.1 फ़ीसद हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 50 फ़ीसद परिवारों के पास ज़मीन नहीं है यानी यह आबादी भूमिहीन है. ऐसे परिवारों में अगड़े-पिछड़े सभी शामिल हैं.

ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ऊंची जाति के परिवारों के पास औसतन कृषि योग्य भूमि का रकबा 1.91 एकड़ (हिंदू) और 0.45 एकड़ (मुस्लिम) है. अगर हिंदुओं की ऊंची जातियों के बीच देखें, तो भूमिहार ऐसी बिरादरी है, जिसके पास कृषि योग्य भूमि औसतन प्रति परिवार 2.96 एकड़ है. राजपूतों में 1.99 एकड़, ब्राह्मणों में 1.40 एकड़ और कायस्थों में 1.01 एकड़ प्रति परिवार का औसत है. दूसरी ओर मुसलमानों की ऊंची जातियों में पठान के पास प्रति परिवार औसतन कृषि योग्य ज़मीन 0.48 एकड़ है, जबकि शेख के पास 0.46 और सैयद के पास 0.37 एकड़ ज़मीन प्रति परिवार है. दिलचस्प तथ्य यह है कि ग्रामीण इलाकों में हिंदुओं और मुसलमानों की ऊंची जातियों के हाथ से ज़मीन का टुकड़ा निकल रहा है. ज़मीन खरीद-बिक्री के रुझानों पर ग़ौर करें, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों की ऊंची जातियों के 6.5 फ़ीसद परिवारों ने ज़मीन का टुकड़ा बेच दिया, जबकि ज़मीन खरीदने वाले परिवार महज 1.1 फ़ीसद रहे. इसमें भी देखें, तो हिंदुओं की ऊंची जाति के 7.5 फ़ीसद परिवारों को अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा, जबकि मुसलमानों की ऊंची जाति के 3.4 फ़ीसद परिवारों के हाथ से ज़मीन का टुकड़ा निकल गया. दोबारा ज़मीन खरीदने वाले लोगों में हिंदू 1.2 फ़ीसद और मुसलमान 1.0 फ़ीसद रहे.

बिहार में कमाने के लिए परदेस जाने का इतिहास बहुत पुराना है. इसकी झलक यहां के लोक गीतों में भी मिल जाती है. पहले अपना गांव-शहर छोड़कर बाहर कमाने जाने वालों में समाज के पिछड़े वर्ग के लोग ज़्यादा थे. लेकिन, सवर्ण आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले कुछ दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों की अगड़ी जातियों में कमाने के लिए बाहर जाने का चलन बढ़ा है. ग्रामीण इलाकों में रोज़गार या रोज़गार के बेहतर अवसर के लिए 85.8 फ़ीसद हिंदू और 90.5 फ़ीसद मुसलमान बाहर जाते हैं. शहरों की कहानी में बहुत ज़्यादा फ़र्क़ नहीं है, संख्या कुछ कम ज़रूर है. शहरों में अगड़ी जाति के 68.0 फ़ीसद हिंदू और 78.2 फ़ीसद मुसलमान रोज़गार या रोज़गार के बेहतर अवसर के लिए बाहर जाते हैं. लेकिन, रोज़गार पाने वालों की तुलना में रोज़गार के बेहतर अवसर पाने वाले अगड़ी जातियों (हिंदू-मुस्लिम दोनों में) के लोगों की तादाद कम है. इसका सीधा अर्थ यह है कि ज़्यादातर लोग उस श्रेणी में शामिल हैं, जो बाहर जाकर किसी प्रकार जीवन का निर्वाह कर पाते हैं. जाति के लिहाज से देखा जाए, तो ग्रामीण इलाकों से पलायन करने वाले कायस्थों को सबसे ज़्यादा 24.8 फ़ीसद बेहतर मौक़े मिले. जबकि ब्राह्मण, भूमिहार एवं राजपूत जाति के लोगों को कायस्थों की तुलना में रोज़गार के बेहतर मौक़े कम मिले. मुसलमानों में बेहतर अवसर पाने वालों में सैयद 23.1 फ़ीसद हैं, जो शेख और पठान की तुलना में कहीं ज़्यादा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

नेपाल प्रशासन की संवेदनहीनता से कराहती रही मानवता

नेपाल में पूर्वी व पश्चिमी चम्पारण के बीस हजार से अधिक लोग वहां फंसे रहे और घर वापस लौटने के लिए छटपटाते रहे. नेपाली यात्री बस संचालकों की मनमानी भी सिर चढ़कर बोलती रही और पांच सौ के बदले दो हजार रुपये के अनुपात में किराया भारतीयों से वसूला जाता रहा. भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा राहत एवं बचाव के लिए भेजे गए सरकारी वाहन कम पड़ रहे थे और नेपाल में फंसे लोगों को इसकी सही जानकारी भी नहीं मिल पा रही थी. लोग किसी प्रकार निजी वाहनों से भारी रकम चुकता कर नेपाल के सेमरा तक पहुंचते रहे, तो फिर सेमरा से छोटे वाहनों से रक्सौल तक लाने के लिए प्रतिव्यक्ति एक से दो हजार रुपये किराये वसूला जाता रहा.

रक्सौल के हजारीमल उच्च विद्यालय में संचालित सरकारी शिविर में रोज बड़ी संख्या में पीड़ित नेपाल से वापस यहां पहुंच रहे थे, जिन्हें भोजन, विश्राम और उनके गंतव्य तक जाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा कराई जा रही थी. घायलों को प्रशासन द्वारा रक्सौल के अलावा मोतिहारी के सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराये जा रहे थे.

इन्तेजारूल हक

पड़ोसी देश नेपाल में आई भीषण प्राकृतिक आपदा में फंसे कई भारतीय नागरिकों का न केवल अस्पतालों में शोषण होता रहा है, बल्कि घायलों व मृतकों को यहां लाने के लिए की गई सारी घोषणाएं नाकाफी साबित हुईं. घायल भारतीय मरीज नेपाली अस्पतालों में भर्ती तो हुए, लेकिन जिस तरह से इस आपदा की घड़ी में उनका शोषण हुआ, वह शायद कभी नहीं हुआ था. न तो नेपाल सरकार और न ही भारत सरकार की ओर से उन तक जरूरी सहायताएं समय पर पहुंच सकीं. नेपाल में पूर्वी व पश्चिमी चम्पारण के बीस हजार से अधिक लोग वहां फंसे रहे और घर वापस लौटने के लिए छटपटाते रहे. नेपाली यात्री बस संचालकों की मनमानी भी सिर चढ़कर बोलती रही और पांच सौ के बदले दो हजार रुपये के अनुपात में किराया भारतीयों से वसूला जाता रहा. भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा राहत एवं बचाव के लिए भेजे गए सरकारी वाहन कम पड़ रहे थे और नेपाल में फंसे लोगों को इसकी सही जानकारी भी नहीं मिल पा रही थी.

लोग किसी प्रकार निजी वाहनों से भारी रकम चुकता कर नेपाल के सेमरा तक पहुंचते रहे, तो फिर सेमरा से छोटे वाहनों से रक्सौल तक लाने के लिए प्रतिव्यक्ति एक से दो हजार रुपये किराये वसूला जाता रहा. पोखरा से सेमरा तक का किराया दांत खट्टा करने वाला था. मात्र पांच सौ के बदले तीन से पांच हजार रुपये प्रति व्यक्ति किराया वसूला गया. एक तरफ प्रकृति की मार, तो दूसरी ओर नेपाली प्रशासन की संवेदनहीनता लोगों को परेशान करती रही. ढाका थाना के रूपौलिया गोपी गांव निवासी नन्दलाल चौधरी का पांच वर्षीय नाती 25 अप्रैल की भूकम्प में मौत के मुंह में समा गया, तो उसकी बेटी व दामाद जान बचाकर किसी तरह अपने गांव लौटे हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक सौ से अधिक चम्पारण के लोग इस प्राकृतिक विपदा में काल के गाल में समा गए हैं तो सैकड़ों घायल अस्पतालों में अपनी जान बचाने में जुटे हुए हैं. मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती हुआ राज किशोर प्रसाद ने जिस सच का खुलासा किया है, उससे न केवल नेपाल की व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि भारत सरकार और बिहार सरकार की कोशिशें असरदार साबित नहीं हो सकी है. पूर्वी चम्पारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के नारायण चौक पकड़िया निवासी चन्द्रिका प्रसाद का पुत्र राज किशोर प्रसाद किसी प्रकार जान बचाकर मोतिहारी पहुंचा है, जहां सदर अस्पताल में भर्ती होकर वह अपना इलाज करा रहा है. उसके बायें हाथ में गंभीर चोटें हैं और शरीर के विभिन्न अंगों में जख्म देखे गए हैं. प्रसाद बताते हैं कि 25 तारीख के भूकम्प में ही वह नेपाल की राजधानी काठमांडू के काली माटी मुहल्ला में तब बुरी तरह घायल हुआ था, जब वहां एक तीन मंजिली इमारत में बढ़ईगिरी का काम कर रहा था. वह अपने तीन भाई व एक भतीजा के साथ वहां काम कर रहा था. भूकम्प में वह गिरा और मलबे में दब गया. उसके भाई और भतीजा ने उसे मलबे से बाहर निकाला और नजदीक के बढ़ोदा अस्पताल में भर्ती कराया. डॉ. ने उसका इलाज तो किया, लेकिन तीन दिनों में उससे 28 हजार पांच सौ नेपाली रुपये इलाज के नाम पर ऐंठ लिए. श्री प्रसाद यहां से किसी प्रकार रक्सौल पहुंचे, जहां उन्हें चार गुणा से ज्यादा किराया देना पड़ा. वे मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती किए गए.

भूकम्प पीड़ित

उन्होंने बताया कि ऐसे सैकड़ों भारतीय मरीज विभिन्न अस्पतालों में कराह रहे हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए अभी तक कोई सरकारी साधन नहीं पहुंच सका है. यदि श्री राजकिशोर प्रसाद की बातों को सच माना जाए, तो अभी तक भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा नेपाल में फंसे, मरे व घायल लोगों की मदद के लिए की गई तमाम घोषणाएं केवल व केवल लफ्फाजी साबित हो रही हैं. बसें अगर नेपाल में गई हैं तो वह कहां हैं और किसको लेकर लौट रही हैं. चिकित्सकों के दल के नेपाल जाने की घोषणाएं की गईं, वे किन अस्पतालों में हैं. इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है. हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर राज्य सरकार ने परिवहन निगम की बसें रक्सौल मार्ग से नेपाल भेजा, जहां से फंसे हुए बिहारियों व भारतीय को लाया गया. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 34 हजार लोगों को नेपाल से भारत के विभिन्न सीमावर्ती इलाकों पर लाया गया है. बिहार सरकार ने बिहार और नेपाल की सीमा के मुख्य पारगमन स्थल रक्सौल के अलावा बैरगिनिया, जोगबनी एवं बेतिया में राहत एवं बचाव शिविर स्थापित किए हैं, जो मानवता की सेवा में एक मजबूत पहल मानी जा रही है. रक्सौल के हजारीमल उच्च विद्यालय में संचालित सरकारी शिविर में रोज बड़ी संख्या में पीड़ित नेपाल से वापस यहां पहुंच रहे थे, जिन्हें भोजन, विश्राम और उनके गंतव्य तक जाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा कराई जा रही थी. घायलों को प्रशासन द्वारा रक्सौल के अलावा मोतिहारी के सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराये जा रहे थे.

रक्सौल के शिविर में चिकित्सा व्यवस्था भी की गई है और विशेष जिला पदाधिकारी श्रीधर अपनी कमान यहां संभाले रहे. गौरतलब है कि सीमावर्ती चम्पारण के लोग बड़ी संख्या में वर्षों से नेपाल में अपना कारोबार करते रहे हैं. प्राय: सभी प्रकार के कारोबार से यहां के लोग जुड़े रहे हैं, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू महानगर के अलावा पोखरा, बीरगंज, रउतहट, पर्सा, जाजरपुर, साल्याण, चंदन निगाह पुर समेत नेपाल के विभिन्न पर्यटक स्थलों एवं प्रमुख बाजारों में रहते रहे हैं. 25 और 26 अप्रैल के भीषण भूकम्प से उन सभी का कारोबार चौपट हो गया है. उसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं तो करीब एक सौ से अधिक चम्पारणवासी वहां मौत के मुंह में समा गए हैं, जिनका अभी तक कोई अता–पता नहीं है. उनके परिजन, जो यहां भागकर पहुंच रहे हैं, उनसे मरने वालों की जानकारियां मिल रही हैं. हालांकि जिला प्रशासन अभी तक इस तरह का कोई आधिकारिक आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर सका है. कपड़ा, सब्जी, कबाड़, होटल, कारोबार के अलावा यहां के लोग बढ़ईगिरी, चमड़ा कारखानों एवं अन्य कारोबारों में नौकरी भी करने वहां जाते रहे हैं.

अब उन्हें इस हादसे ने तोड़ कर रख दिया है और वे सब अपना सबकुछ गवां कर खाली हाथ वापस लौट रहे हैं. इस हादसे ने नेपाल की राजधानी काठमांडू, वीरों की धरती गोरखा को तहस–नहस कर दिया है और एक अनुमान के अनुसार, दस हजार से अधिक लोग इस दुर्घटना में काल के गाल में समा गए हैं तो हजारों की संख्या में इमारतें ध्वस्त हो गईं और लोग घायल हो गए हैं. भूख और प्यास से लोग छटपटा रहे हैं और खाद्य सामग्रियों के साथ–साथ पीने का पानी भी आसानी से नहीं मिल पा रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा विधायक की नज़र में भाजपा दलित विरोधी

राजकुमार शर्मा

प्रदेश भाजपा ने अमित शाह के कार्यक्रम का खुलेआम बहिष्कार करने वाले घनसाली के विधायक भीमलाल आर्य को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है. लंबे समय से पार्टी नेतृत्व को आंख दिखा रहे और मुख्यमंत्री हरीश रावत की तारीफ करने वाले विधायक आर्य को आखिरकार भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखा ही दिया. आर्य पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के अलावा पार्टी विधानमंडल दल से भी निलंबित रहेंगे. तीन मई को जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की बैठक में नहीं पहुंचे तो मामला बिगड़ गया.

इस मामले में पार्टी आर्य के जवाब का इंतजार कर रही थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ही टीका–टिप्पणी कर दी. आर्य की नज़र इस कदर हरीश रावत पर मेहरबान है कि उनकी नज़र में भाजपा के नायक नरेन्द्र मोदी छोटे लगने लगे हैं. हरीश के इस जादू से सूबे की राजनीति के मर्मज्ञ भी इस बात से हैरान हैं कि आर्य आखिर किस दबाव में मोदी को धत्ता बताने पर तुले हैं. आर्य का आरोप है कि भाजपा के दलित विरोधी आचरण से वे तंग आ चुके हैं.

प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि विधायक आर्य को एक माह के अंदर जवाब देने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा की अनुशासन समिति पूरे मामले की पड़ताल करेगी. बीते दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपने एक दिवसीय दौरे पर देहरादून आए थे. इस दौरान आर्य ने पार्टी द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया के प्रेक्षागृह में आयोजित बैठक का बहिष्कार किया था. इस कारण प्रदेश भाजपा ने आर्य को निलंबित करने का निर्णय लिया. वैसे भी घनसाली के विधायक आर्य प्रदेश भाजपा की निगाह पर काफी लंबे समय से चढ़े हुए थे. प्रदेश भाजपा भी ऐसे मौके की तलाश में थी कि कब आर्य के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए. प्रदेश भाजपा के नेता आर्य पर काफी लंबे समय से नाराज चल रहे थे. आर्य कई बार राज्य सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री हरीश रावत की तारीफ कर चुके हैं. आर्य ने बीते दिनों कई बार कहा है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत जमीनी नेता हैं और प्रदेश के विकास में लगे हुए हैं.प्रदेश की नौकरशाही मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने पर तुली हुई है. धरना प्रदर्शन करने में सबसे अव्वल रहे घनसाली के विधायक आर्य को जब भी सदन में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का मौका मिला, उन्होंने इसमें रूचि दिखाने के बजाय सदन के अंदर व बाहर धरना–प्रदर्शन करने में ही दिलचस्पी दिखाई. कभी मुख्यमंत्री आवास तो कभी राजभवन के सामने अक्सर ही आर्य को धरना देते देखा गया. प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक आर्य को मनाने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को भी जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन आर्य नहीं माने. समय–समय पर संगठन के खिलाफ अपनी आवाज भी बुलंद करते रहे. उन पर आफत तब आई, जब उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कार्यक्रम का भी विरोध कर डाला.■

बीच में बैठे भाजपा विधायक भीमलाल आर्य

उत्तराखंड

भाजपा के बुरे दिनों की शुरुआत–भीमलाल

अनुशासनहीनता के आरोप में भाजपा से निलंबित विधायक भीमलाल आर्य ने निलंबन की इस कार्रवाई को एकतरफा बताया. उन्होंने कहा कि उनका पक्ष जाने बगैर ही निलंबन किया जाना भाजपा संविधान के विपरीत है. भाजपा अति आत्मविश्वास की शिकार हो गई है और यह अति आत्मविश्वास पार्टी को ले डूबेगा. उनका कहना है कि भाजपा के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है. इसका दलित विरोधी चेहरा भी सामने आ गया है. मुख्यमंत्री हरीश रावत उनके क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण में सराहनीय काम कर रहे हैं, तो वे क्यों मुख्यमंत्री की तारीफ न करें. हालांकि, उन्हें अब तक निलंबन का पत्र नहीं मिला है, जब भाजपा के कुछ नेता उनके विरुद्ध मन बना ही चुके हैं, तो वे जो करना चाहते हैं कर लें.

feedback@chauthiduniya.com

बालश्रम का दंश झेल रहा बचपन

अमृतांज इंदीवर

जिस उम्र में बच्चों को माता–पिता का प्यार, समाज से संस्कार और स्कूल से अक्षर ज्ञान मिलना चाहिए, उस में देश का बचपन अपने और परिवार के पेट की खातिर ज़ोखिम भरे काम कर रहा है. ऐसे बच्चों को ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंटों एवं रेलवे स्टेशन पर देखा जा सकता है. कमरतोड़ मेहनत के बाद दो वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से नसीब हो पाती है. ढेर सारे बच्चे फटेहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, वे सड़क के किनारे, बस एवं रेलवे स्टेशन के आस–पास कूड़े–कचरे के ढेरों में अपना जीवन तलाश रहे हैं. सड़क पर जीवन बिताने वाले बच्चों की संख्या देश में लाखों में है, लेकिन शासन–प्रशासन और नीति नियंताओं द्वारा कहा जाता है कि बाल श्रमिक अब न के

बराबर हैं. यूनिसेफ की मानें, तो भारत में सड़कों पर जीवन बसर करने वाले बच्चों की संख्या दो करोड़ से भी अधिक है, जो भुखमरी के साथ–साथ उपेक्षा, उत्पीड़न और शोषण के शिकार हैं. उनसे भीख मांगने, चोरी, जेबकतरी और अवैध शराब बेचने जैसे अनैतिक कार्य कराए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी नारकीय बनती जा रही है.

देश भर में असामाजिक तत्वों एवं एजेंटों के ज़रिये पैसा कमाने के लिए बच्चों का सौदा बेरोकटोक किया जा रहा है. ऐसे बच्चे परिस्थितियोंवश शराब, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी आदि का सेवन करने लगते हैं. बाल मज़दूरी निषेधाज्ञा एवं विनियमन क़ानून बने ढाई दशक हो गए, पर बाल मज़दूरी के ग्राफ में कमी आने के बजाय 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. सरकार के कुछ प्रभावी प्रोजेक्ट बने और चले भी, पर भ्रष्टाचार की गंगोत्री में आकंठ डूबी सरकारी और ग़ैर–सरकारी संस्थाओं ने बच्चों का निवाला भी छीन लिया. इसमें प्रमुख रूप से बाल श्रमिक विशेष विद्यालय और एनजीआरपी जैसी योजनाएं शामिल हैं, जिनके तहत बाल श्रमिकों को देश–समाज की मुख्य धारा में लाकर उन्हें तीन वर्षीय ब्रिज कोर्स, पांच रुपये में दोपहर का भोजन, सौ रुपये बतौर छात्रवृत्ति, नियमित स्वास्थ्य जांच एवं रोज़गारपरक प्रशिक्षण (वोकेशनल ट्रेनिंग) आदि सुविधाएं दी जानी थीं. इसके अलावा सरकार ने अभियान चलाया कि ढाबों, होटलों, मनोरंजन केंद्रों अन्य धंधों में बच्चों को नौकरी देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी. कुछ दिनों तक धरपकड़ का अभियान ज़ोरों पर रहा, लेकिन बाद में वह भी बंद हो गया.

बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के हुस्सेपुर, चांदकेवारी पंचायत के दलित–महादलित एवं पिछड़े टोले के नन्हें हाथ महानगरों की चकाचौंध में जोखिम भरे काम कर रहे हैं. सरयुग, अर्जुन, टुन्नी, दरोगा (काल्पनिक नाम) आदि बच्चे सूरत (गुजरात), दिल्ली, कोलकाता, असम आदि जगहों पर आधी मज़दूरी में काम करने को मजबूर हैं. सरयुग प्राथमिक स्कूल में पढ़ता था, जो अब घर की माली हालत सुधारने के लिए सूरत स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में नौकरी करता है. दो साल बाद जब वह घर आया, तो आसपास के अपने साथियों के बीच जींस और टी–शर्ट में किसी हीरो से कम नहीं दिख रहा था. एक साथी ने जींस पर लिखा अंग्रेजी का शब्द पढ़ा, तो सरयुग अवाक रह गया. अरे, तुम्हें दो साल में अंग्रेजी भी पढ़नी आ गई! मैं तो एबीसीडी के अलावा कुछ नहीं जानता. साथी बोला, तुम पैसे कमा रहे हो और मैं पढ़ाई कर रहा हूं. सरयुग घर का इकलौता कमाने वाला है, उसी की कमाई से घर चलता है. पढ़ाई से नाता टूटते ही सरयुग समाज, संस्कार, नैतिकता, मां की ममता आदि से वंचित हो गया. आज वह 13 साल का है और महीने में पांच हज़ार रुपये कमाता है.

बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के हुस्सेपुर, चांदकेवारी पंचायत के दलित–महादलित एवं पिछड़े टोले के नन्हें हाथ महानगरों की चकाचौंध में जोखिम भरे काम कर रहे हैं. सरयुग, अर्जुन, टुन्नी, दरोगा (काल्पनिक नाम) आदि बच्चे सूरत (गुजरात), दिल्ली, कोलकाता, असम आदि जगहों पर आधी मज़दूरी में काम करने को मजबूर हैं. सरयुग प्राथमिक स्कूल में पढ़ता था, जो अब घर की माली हालत सुधारने के लिए सूरत स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में नौकरी करता है.

सरयुग सूरत में ग़लत लोगों की संगति में आकर शराब, सिगरेट और वयस्क फिल्में देखने का भी आदी हो चुका है. हाथ में क़ीमती मोबाइल पर फूहड़ गीत बजाते हुए जब वह गांव में निकलता है, तो लोग गालियां देते नहीं थकते. पर, भला इसमें सरयुग का क्या दोष? जब उसकी माली हालत खराब थी, तो कोई मदद के लिए आगे नहीं आया. किसी ने परिवार वालों को नहीं समझाया कि अभी यह बच्चा है, इसे परदेस कमाने के लिए मत भेजो. सरयुग जैसे अनपढ़ ही देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बाधक बनते हैं.

ग़ौरतलब है कि अधिकांश बाल श्रमिक कुपोषित पाए जाते हैं. आज भी देश में महिलाएं, खास तौर से ग़रीब तबके की महिलाएं खून की कमी का शिकार पाई जाती हैं, तो उनके गर्भ में पल रहे बच्चे भला स्वस्थ कैसे होंगे? आंकड़े बताते हैं कि 85 से 90 प्रतिशत तक बच्चे छह वर्ष से कम उम्र में काल के गाल में समा जाते हैं. सबसे आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि खाद्य सुरक्षा एवं बाल विकास परियोजना के तहत देश भर में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार समेत अन्य सामग्रियां सिर्फ़ नाम मात्र के लिए मिलती हैं. बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए आने वाली सामग्री बाज़ार में बेच दी जाती है और फिर कागज़ी खानापूर्ति कर दी जाती है. ऐसे में ग़रीब, झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले परिवारों के बच्चों को खाद्य सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, कहना मुश्किल है. मौजूदा हालात में ऐसे परिवार अपने बच्चों को पेट की खातिर मज़दूरी करने के लिए नहीं भेजेंगे, तो आख़िर क्या करेंगे?

ज़्यादातर बाल मज़दूर दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं. ग़रीब, आदिवासी, दलित एवं पिछड़ी जातियों के हज़ारों बच्चे दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता आदि में आधी मज़दूरी में काम करने को मजबूर हैं. सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है. दूसरी ओर मज़दूरी कर रहे अधिकांश बच्चे अशिक्षित हैं या फिर वे बीच में पढ़ाई छोड़कर पेट की आग बुझाने को विवश हैं. ग़रीब के भूखे बच्चों को उनके हाथ से काम छीनकर जबरदस्ती किताब पकड़ाने से अच्छा होता कि शिक्षा को श्रम से जोड़कर एक नई परिभाषा गढ़ी जाती. रोटी के बगैर किताब भला किस काम की? किसी शायर ने ठीक ही कहा है–जब चली ठंडी हवा, बच्चा ठंड से ठिठुर गया. मां ने अपने लाल की तख्ती (स्लेट) जला दी रात को. ■ *(चरखा)*

उत्तर प्रदेश

वाल्मीकि विवेक

जिस समय पूरे उत्तर प्रदेश में तरक्की में भी आरक्षण दिए जाने के लिए सिर फुटौव्वल हो रहा हो और योग्यता एवं मेधा को आरक्षण के ज़रिये चबा डालने का कुचक्र रचा जा रहा हो, ऐसे में सरिता की आत्महत्या देश और समाज को एक गहरा संदेश देती है. लेकिन, हमारी संवेदनहीन व्यवस्था सरिता को मानसिक अवसाद का शिकार बताने का शाश्वत संवाद दोहरा कर उस संदेश को कूड़ेदान में डाल देगी. सरिता का सुसाइड नोट पढ़ेंगे, तो आप दहल उठेंगे. बीए तृतीय वर्ष की छात्रा सरिता द्विवेदी एनसीसी की तेजतर्रार कैडेट थी. उसका सपना था कि वह पुलिस में भर्ती हो. लेकिन जब उसने देखा कि पुलिस की भर्ती में यादवों की भरमार है, तो वह टूट गई. वह इतनी निराश हो गई कि उसने बाग में पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर लेना बेहतर समझा.

लखनऊ शहर के मशहूर काकोरी इलाके के मलाहां गांव में सरिता द्विवेदी की लाश पेड़ में लटकी पाई गई. सरिता के घर वालों ने पुलिस को ख़बर की. पुलिस ने लाश उतारने और उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने की औपचारिकता पूरी की. पुलिस को मौक़े पर सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें सरिता ने आरक्षण के कारण पुलिस की नौकरी न मिलने से क्षुब्ध होकर आत्महत्या करने की बात लिखी है. लखनऊ के खुनखुनजी गर्ल्स कॉलेज की छात्रा सरिता द्विवेदी (22) ने पुलिस भर्ती की परीक्षा दी थी, जिसमें वह असफल हो गई. सरिता ने पुलिस भर्ती बोर्ड 2014–15 की शारीरिक परीक्षा में सफलता हासिल की थी, लेकिन अंतिम तौर पर उसका चयन नहीं हो सका. शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने के बाद उसके अंतिम चयन में आरक्षण व्यवस्था रोड़ा बन गई. घर वालों के मुताबिक, सरिता पुलिस भर्ती घोटाले से परेशान थी.

पुलिस कहती है कि वह सरिता के सुसाइड नोट में लिखी बातों की छानबीन करेगी. लेकिन, सुसाइड नोट में लिखी बातें आप पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि पुलिस किस साहस और हैसियत से मामले की छानबीन करेगी. जब कई अख़बार वालों ने सुसाइड नोट छापने से परहेज कर लिया, तो सरकारी तंत्र क्या कर लेगा. सुसाइड नोट में सरिता ने उत्तर प्रदेश सरकार और आरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. सरिता ने सुसाइड नोट में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर अपनी हत्या का आरोप लगाया और लिखा है कि सामान्य वर्ग में जन्म लेने का यह अभिशाप या सजा है. सभी जगह आरक्षण–अभिशाप. यदि हम कोई फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए पैसे कहां से लाएं? उसने लिखा कि पापा, आपके पास भी तो इतनी ताकत नहीं रही. कॉलेज की कॉपी पर लिखे गए सुसाइड नोट में सरिता कहती है कि अखिलेश के घराने में लालू यादव की बिटिया की आलीशान शादी का जश्न देश भर में प्रमुखता से छपता है, लेकिन कोई नहीं लिखता कि इस जश्न में पैसा किसका खर्च होता है. सरिता कहती है कि ग़रीबों का खून चूसकर ही ये लोग जश्न मनाते हैं.

सरिता को बहुत तकलीफ थी कि सारे पदों पर यादव ही भरे हुए हैं. वह लिखती है, पापा, मैंने हार नहीं मानी, पर हमें सामान्य जाति के होने का अभिशाप था. कहीं लंबाई, कहीं पढ़ाई, कहीं आरक्षण. तो क्या करें जीकर? ज़्यादा पढ़ाई या प्रोफेशनल कोर्स करना या कराना हम लोगों की क्षमता से बाहर है. पापा, मैं तो जा रही. इन हत्यारों से यह पूछना कि जब सामान्य वर्ग वालों के लिए कहीं जगह नहीं है, तो हर हॉस्पिटल में बोर्ड लगवा दें कि सामान्य वर्ग की स्त्री के शिशु जन्म लेने से पहले ही मार डालें. सब जातिवाद फैला रहे हैं. पापा, मैंने हार नहीं मानी थी. बस आरक्षण–अभिशाप की वजह से जीना नहीं चाहती. हर जगह अपनीअपनी जाति–बिरादरी के लोगों की तैनाती की जा रही है. सरिता ने अपनी मां को लिखा कि आप परेशान मत होना, मैं आपके सुखों में बहुत खुश थी. वर्दी का सपना इस हालात में ले आया. मैं पुलिस की वर्दी तो नहीं पहन सकी, लेकिन एनसीसी की वर्दी घर में रखी है, जिसे मेरी चिता के पास रख देना. मम्मी, मेरा सपना था वर्दी पहनने और इंसाफ की लड़ाई लडऩे का. इसलिए मैं दौड़–दौड़कर पेट की मरीज बन गई. सरिता आख़िर में लिखती है, जय भारत, जय धरती माता की, मुझे अपनी गोद में स्थान दो.

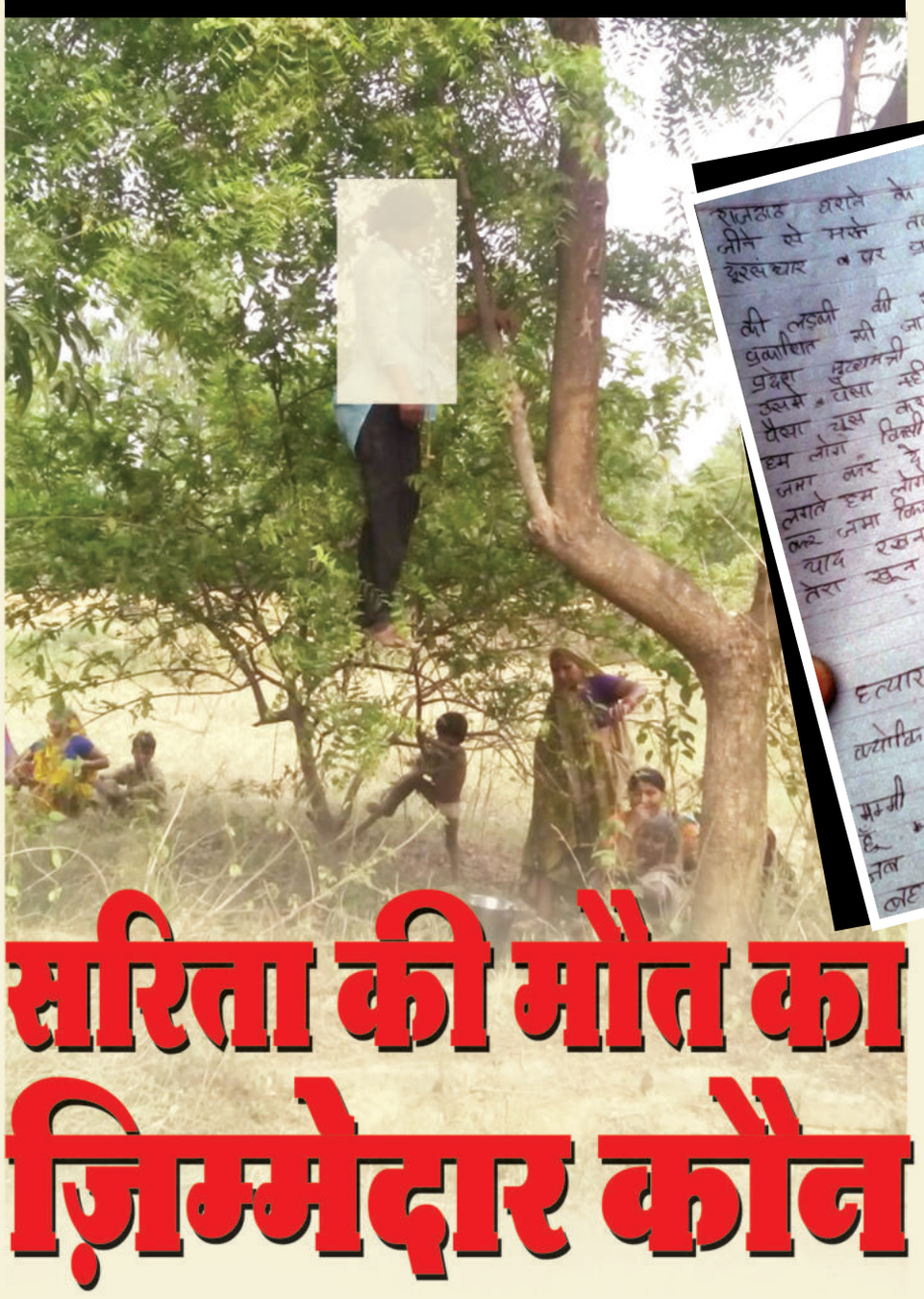

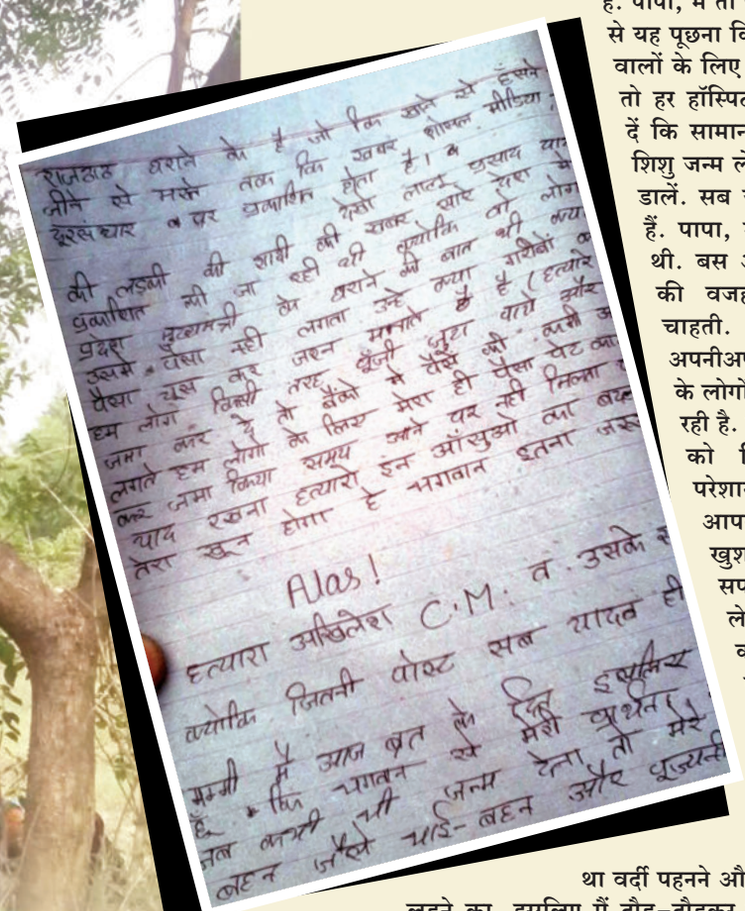

काकोरी थाने के स्टेशन अफसर अनिल सिंह कहते हैं कि सरिता के घर वालों ने पुलिस को सुसाइड नोट की फोटो कॉपी दी है. सुसाइड नोट क़रीब नौ पन्ने का है. पुलिस कहती है कि फोटो कॉपी पर वह छानबीन नहीं कर सकती, उसे तो मूल कॉपी चाहिए. सरिता के रिश्तेदारों का कहना है कि असल सुसाइड नोट दे दो, तो वह गायब हो जाएगा, पड़ताल थोड़े होगी. वे उसे सीधे अदालत के समक्ष पेश करने की सोच रहे हैं. सरिता के गांव वाले और रिश्तेदार इतने नाराज़ थे कि वे पुलिस को लाश नहीं उतारने दे रहे थे. मलिहाबाद के एसडीएम नंदलाल कुमार और डीएसपी एएन त्रिपाठी द्वारा समझाने–बुझाने के बाद सरिता की लाश पेड़ से उतारी जा सकी. देश की आज़ादी में अहम भागीदारी करने वाले काकोरी के मलाहां गांव में बेहद ग़रीब परिवार में पैदा हुई गिरीश द्विवेदी की पुत्री सरिता बहुत मेधावी और साहसी थी. पुलिस में भर्ती होकर वर्दी पहनने के बाद उसका सपना इंसाफ की लड़ाई लड़ने का था, लेकिन आरक्षण और सरकारी संवेदनहीनता के आगे उसकी एक नहीं चली और पुरस्कार में उसे मौत मिली. आहत सरिता ने सुसाइड नोट में अपनी आत्महत्या के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव, कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव और कुछ सचिवों को ज़िम्मेदार ठहराया. उसने सुसाइड नोट में अखिलेश यादव को हत्यारा तक लिखा. सरिता ने लिखा कि सामान्य वर्ग में जन्म लेना अभिशाप और सजा है. सब जगह आरक्षण का अभिशाप. ■

सरिता की मौत का ज़िम्मेदार कौन

धांधली का शिकार हुई सरिता

पुलिस भर्ती परीक्षा में सरिता द्विवेदी को मेरिट लिस्ट में 188वें स्थान से घटाकर 288वें स्थान पर कर दिए जाने की बात सामने आई है. सरिता ने दौड़ की प्रतियोगिता में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए थे. जाहिर है, उसका मेरिट में ऊंचा स्थान अवश्य रहा होगा. लिहाजा, इस बात की गहराई से जांच की जानी चाहिए कि मेरिट लिस्ट के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई? मेरिट लिस्ट में छेड़छाड़ और रिश्वत लेकर स्थान ऊपर–नीचे किए जाने की अनगिनत शिकायतें मिली हैं. एक पुलिस अधिकारी ने खुद कहा कि अगर मामले की गहराई और निष्पक्षता से जांच हो, तो सरिता की आत्महत्या हत्या साबित हो जाएगी, क्योंकि सरिता धांधली और भ्रष्टाचार का शिकार बनी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

चुनाव में अभी चार साल का वक्त है. मौजूदा वक्त मतदाता का ध्यान अपनी तरफ़ आकर्षित करने का नहीं है. अगले चुनाव में मतदाता इस आधार पर मतदान करेगा कि 2018-19 में देश की हालत क्या रहती है. जितनी जल्दी सरकार यह समझ लेती है, उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि टकराव से सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होता. विपक्ष की तो बात ही मत कीजिए. छोटे व्यापारियों और कॉरपोरेट हलकों, जो भाजपा के मुख्य मतदाता हैं, के बीच आम चर्चा है कि सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है. मैं नहीं मानता कि ऐसी बातें उचित हैं या निष्पक्ष हैं.

टकराव से सरकार को फ़ायदा नहीं होगा

अभी संसद सत्र समाप्त हुआ. सरकार अब एक वर्ष पूरा कर रही है, लेकिन इस दौरान एक बात स्पष्ट हुई कि अभी तक वह संसद में सरकारी कार्य ठीक तरीके से करा पाने के लिए एक सही रणनीति बनाने में सक्षम नहीं हो सकी है. अमेरिका सहित दुनिया भर में जहां राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, वहां राष्ट्रपति खुद अपने या दूसरे पक्ष के सीनेटरों और कांग्रेसियों को लुभाने का काम करते हैं. इसी तरह ब्रिटेन में बिल पास कराने के लिए द्वि-दलीय चर्चा होती है. भारत में भी ऐसी परंपरा रही है. जब कांग्रेस सत्ता में होती थी और पूर्ण बहुमत होता था, तब भी वह हमेशा विपक्ष के साथ खुला संवाद करती थी. समस्या अभी शुरू होती प्रतीत होती है, जहां लगता है कि एक व्यक्ति है, जो कांग्रेस के साथ सही ढंग से संबंध स्थापित करने में सक्षम नहीं है.

श्री वेंकैया नायडू की प्रतिभा संसदीय मामलों के मंत्री होने के रूप में कम हो जाती है. भूमि अधिग्रहण अधिनियम की बात करें, तो पिछला अधिनियम भाजपा की सहमति से पारित किया गया था. सुमित्रा महाजन, जो अब लोकसभा अध्यक्ष हैं, तब स्थायी समिति की अध्यक्ष थीं. उन्होंने अद्भुत काम किया और सभी दलों के साथ आम सहमति बनाकर बिल को अंतिम रूप दिया था. अब सवाल है कि एक नए बिल की ज़रूरत क्या थी? यदि पुराने बिल में कुछ परिवर्तन की ज़रूरत थी, तो उस पर संसद में बहस होनी चाहिए या उसे स्थायी समिति को भेजना चाहिए. और, यदि सब लोग मानते थे कि नए बिल की ज़रूरत है, तो पुराने बिल में संशोधन के लिए एक नया बिल लाया जाना चाहिए और फिर उसे पास कराना चाहिए. उसकी जगह सरकार एक बिल्कुल नया बिल लेकर आ गई और उससे न केवल संसद बाधित हुई, बल्कि सरकार और विपक्ष दोनों को संसदीय काम पूरा करने की जगह अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए लोगों के पास जाना पड़ रहा है. सरकार के पहले साल में इस सबकी ज़रूरत नहीं थी.

चुनाव में अभी चार साल का वक्त है. मौजूदा वक्त मतदाता का ध्यान अपनी तरफ़ आकर्षित करने का नहीं है. अगले चुनाव में मतदाता इस आधार पर मतदान करेगा कि 2018-19 में देश की हालत क्या रहती है. जितनी जल्दी सरकार यह समझ लेती है, उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि टकराव से सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होता. विपक्ष की तो बात ही मत कीजिए. छोटे व्यापारियों और कॉरपोरेट हलकों, जो भाजपा के मुख्य मतदाता हैं, के बीच आम चर्चा है कि सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है. मैं नहीं मानता कि ऐसी बातें उचित हैं या निष्पक्ष हैं. वे सरकार से क्या करने की उम्मीद करते हैं? जितना संभव है, सरकार नियंत्रण को ढीला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नौकरशाही एक हद से आगे नहीं बढ़ने देती. शायद कुछ बेहतर किया जा सकता है. सरकार एक छोटी-सी समिति का गठन कर सकती है, जो सरकारी नियमों, विनियमों एवं प्रक्रियाओं को देखे और बताए कि इसमें क्या कटौती की जा सकती है. पिछले दो बजट ठीक ही रहे हैं. यह कहा जा सकता है कि बजट बेहतर हो सकता था, लेकिन कुछ नकारात्मक नहीं रहा. हां, एक नकारात्मक काम यह हुआ है कि मौजूदा सरकार पिछली सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स ख़त्म नहीं कर रही है, उलटे वह एमएटी टैक्स लगाने जा रही है. मैं नहीं जानता, इस सबके लिए सरकार के पास कोई नीतिगत दृष्टिकोण है या वित्त मंत्री खुद यह सब कर रहे हैं. लेकिन तथ्य यह है कि सरकार का इरादा विदेशी निवेश लाने, कॉरपोरेट सेक्टर को बढ़ावा देने और संगठित अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का है. पर, वह सही दिशा में काम नहीं कर रही है. फियर फैक्टर मदद नहीं करता है. वर्ष 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने फेरा क़ानून पारित किया था. उससे क्या हुआ? लोगों को उसे समझने में लंबा समय लगा और प्रवर्तन

निदेशालय एक भ्रष्ट संगठन बन गया, जो व्यवसायियों को धमकाता रहता था. अब फिर से वित्त मंत्री काला धन, विदेशी पैसे और 10 वर्ष के कारावास की बात कर रहे हैं. इस सब बयानबाजी से क्या होगा? चुनावों के लिए की जाने वाली इन सब बातों पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब बात मुद्दे की हो, तो यह सब ठीक नहीं है. इससे कोई मदद नहीं मिलती. इस सबसे केवल ईमानदार आदमी डरता है. बेईमान इन सब चीजों से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि कुछ नहीं होने वाला. इसलिए मैं समझता हूं कि इस सब पर पुनर्विचार ज़रूरी है. अरुण शौरी ने कुछ टिप्पणियां की हैं, जिनसे पार्टी के लोग गुस्सा हैं. सच कहूं, तो उन्होंने कुछ भी कठोर बात नहीं की. उन्होंने सिर्फ़ यह कहा कि सरकार ग़लत दिशा में जा रही है. अगर सरकार उनकी बात सुनती है, तो उससे सरकार को ही फ़ायदा है. अरुण शौरी और अरुण जेटली के बीच एक व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता है, इसलिए मैं दोनों ओर से की जा रही टिप्पणियों को समझ सकता हूं. लेकिन, गेंद सरकार और श्री जेटली के पाले में है. तो श्री शौरी ने जिन ग़लतियों की ओर इशारा किया है, उन्हें सही किया जाना चाहिए. यह सरकार के खुद के हित में है.

अब कश्मीर का सवाल आता है. कश्मीर में दो अलग ध्रुवों पर रहीं पीडीपी और भाजपा एक साथ आ गईं और अब बार-बार खुद को शर्मनाक स्थिति में पा रही हैं. कभी मसर्रत आलम, तो कभी सैयद अली शाह गिलानी उन्हें शर्मिंदा कर रहे हैं. यदि अभी भी भाजपा यह प्रयोग जारी रखने की इच्छुक है, तो उसे मुफ्ती को शांति से छोड़ देना चाहिए. मुफ्ती जानते हैं कि कश्मीर को कैसे संभालना है. वह अपने लोगों को जानते हैं. लेकिन, मुफ्ती और भाजपा विधायकों की राय में अंतर है.

क्रिकेट की ख़बर. अब सभी एन श्रीनिवासन के पीछे पड़े हुए हैं. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी है. कोई श्रीनिवासन के बारे में जो भी कहे, लेकिन वह एक ज़िम्मेदार कॉरपोरेट नेता हैं. इसकी बहुत कम संभावना है कि वह कोई निहायत ग़लत काम करें और आप उनकी ग़लती पकड़ें. उनके द्वारा सीएसके पर बोली लगाने से पहले बीसीसीआई अध्यक्ष शरद पवार ने साफ़ किया था कि इसमें हितों का टकराव नहीं है. उसके बाद ही श्रीनिवासन ने बोली लगाई थी. अब कोई उन्हें बिना किसी उचित कारण के परेशान करना चाहता है, तो फिर यह उसकी मर्ज़ी है. मेरे ख्याल में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी खुद को नहीं रोक सका और कमेटी गठित करके उसने एक बहुत छोटे-से मसले को तूल दे दिया. ठीक है कि इसमें बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए उचित नहीं है कि वह क्रिकेट के आम मामलों का संज्ञान ले.

अभी मैं मुंबई में हूं और मैंने सलमान खान पर सड़क दुर्घटना के मामले में कोर्ट का फ़ैसला देखा. इसमें एक बात साफ़ होनी चाहिए कि दुर्घटना तो दुर्घटना होती है, वह कोई हत्या या ग़ैर इरादतन हत्या नहीं होती. लेकिन, बदकिस्मती से पुलिस ने धारा 4-ए का इस्तेमाल कर इस मामले को ग़ैर इरादतन हत्या का मामला बताया और फिर जज ने इसे आधी हत्या मान लिया. एक दुर्घटना केवल दुर्घटना होती है, उसके लिए छह महीने की सजा काफी है. हां, अगर दुर्घटना में किसी की मौत होती है, तो सरकार की तरफ़ से या अगर दुर्घटना करने वाला व्यक्ति कोई सेलेब्रिटी है, तो उसकी तरफ़ से पीड़ित के आश्रितों के पुनर्वास के लिए मुआवज़ा ज़रूर दिया जाना चाहिए. यह हक़ीक़त है कि किसी मृत व्यक्ति का जीवन आप वापस नहीं कर सकते. लेकिन, पीड़ित परिवार की रोज़ाना की ज़रूरतें पूरा करने और उसके बच्चों की शिक्षा के लिए पर्याप्त मुआवज़ा दिया जाना चाहिए. बहरहाल, किसी व्यक्ति को पांच साल की सजा देना, जैसे उसने किसी की हत्या की हो और एक ऐसे शख्स की, जिसे वह जानता तक नहीं, तर्कसंगत नहीं लगता. यहां तक कि इस तरह के पिछले मामलों में, दिल्ली एवं मुंबई में छह-सात लोगों की मौत हुई और दोषियों को सिर्फ़ दो साल की सजा हुई है. इस मामले में केवल एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसके लिए सलमान खान को पांच साल की सजा सुना दी गई. यह ज़रूरत से अधिक सजा है. इस तरह के मामलों के लिए कुछ उसूल बनाने चाहिए, जिनके अनुरूप फ़ैसला होना चाहिए. सलमान एक लोकप्रिय इंसान हैं, उन्होंने दूसरों के लिए बहुत सारे परोपकार के काम किए हैं. यह सही है कि ग़लती तो ग़लती होती है और गुनाह भी गुनाह होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सजा न तो इस समस्या का समाधान है और न ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकने में मददगार साबित होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक औघड़ लीक से हटकर-4

प्रत्यक्षदर्शी का अनुभव

एक दिन बसंत की नवरात्रि में चित्रकूट के आवास-काल में कालिंजर की भैरवी के आग्रह पर बाबा घोरा देवी के यहां अनुष्ठान में जा रहे थे. मुझे जब इसका पता लगा, तो मैंने भी साथ चलने की अनुमति मांगी. उन्होंने मना किया, पर अंत में मान गए. हम लोग घोरा देवी के मंदिर की ओर चले. अवधूतिन ग़ौर-वदना एवं जटिल केश वाली थीं. उनके हाथ में नारियल का एक कमंडल था.

मंदिर तक पहुंचने में क़रीब तीन-चार घंटे का समय लगा. घोरा देवी के मंदिर से सटे पश्चिम की विस्तृत चट्टानों पर साधना एवं पूजन की व्यवस्था होने लगी. शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी और आकाश में चांदनी छिटक रही थी. सरभंगा के साधु के यहां से आवश्यक पात्र मंगवाए गए. उस साधु ने बताया कि यहां पर बाघ आ सकते हैं. इस पर चरण पादुका के पुजारी ने डपट कर कहा, बाबा को बाघ का डर नहीं है. प्रसाद बनने लगा और अवधूतिन स्नान आदि से निवृत्त हो भगवती का शृंगार करने लगीं. भैरवी ने घोरा देवी का अद्भुत शृंगार किया, जो देखते ही बनता था. इधर औघड़ बाबा बैठे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और उनके बगल में बैठे भरत मिलाप के महंत सुपारी आदि काटकर बाबा को दे रहे थे. इतने में घोड़े पर सवार एक वयोवृद्ध तेजस्वी महात्मा वहां

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

वे कब और कैसे आईं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं. उनकी वेशभूषा बड़ी विचित्र थी. वस्त्र नीला था, गले में स्फटिक की चमकती माला थी और हाथ में नारियल का कमंडल था. मैंने उन्हें काफी नज़दीक से देखा था. रात्रि में भरत मिलाप के महंत कह रहे थे कि ये भैरवियां आकाशगामिनी हैं.

उपस्थित हुए. बाबा, भरत मिलाप के महंत एवं भैरवी सभी ने उस वृद्ध महात्मा अघोराचार्य सोमेश्वर राम जी का सादर अभिवादन किया. भगवान राम ने कहा, आपने बड़ी देर कर दी, महाराज. अघोराचार्य एक अद्भुत मुस्कान के साथ बोले, मैंने स्वयं कुछ विलंब से अपने आश्रम से प्रस्थान किया. चिकनी के पुजारी ने अघोराचार्य के घोड़े को एक स्थान पर बांध दिया और पानी पिलाया. मैंने इसी बीच टार्च जलाकर घड़ी देखी, 11 बजे थे.

कुछ देर बाद मैंने देखा कि अघोराचार्य एवं अवधूत भगवान राम सहित सभी साधक हवन की व्यवस्था कर रहे थे. एक मिट्टी की हांडी में कुछ छोटी-छोटी मछलियां थीं और एक कलश में दुधुवा भरा था. मछलियों को दुधुवा में भिगोकर साधक मंडल हवन कर रहा था. पूरा वातावरण रहस्यमय एवं रोमांचकारी हो चला था. इतने में एक बड़ी विचित्र और रोमांचकारी घटना घटी. हो सकता है कि मेरे नेत्र धोखा खा गए हों या फिर अत्यधिक थकान के कारण ऐसा अनुभव हुआ हो. मैंने देखा कि घोरा देवी से एक अद्भुत तेजपुंज निकला और सभी साधकों के हृदय को स्पर्श करता हुआ अग्निकुंड में प्रविष्ट हो गया. इसी समय साधक मंडल ने एक अजीब ठहाका लगाया, जो निर्जन जंगल में दूर-दूर तक व्याप्त हो गया. मुझे यह सब बड़ा विचित्र लगा और मैं अपना झोला लेकर सरभंगा आश्रम की ओर चल दिया. इसी बीच साधक मंडल ने फट्-फट् मंत्र का उच्चारण प्रारंभ कर दिया. दूसरे ही क्षण सारा वातावरण शिवोऽहं, भैरवोऽहं, गुरुपदरतांऽहं की गंभीर वाणी से गूंज उठा.

दूसरे दिन सुबह जब मेरी मुलाकात पुजारी से हुई, तो मैंने रात्रि की साधना के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करनी चाही. पुजारी ने बताया कि रात्रि में मेरे (लेखक के) जाने के बाद हवन कुंड से एक अद्भुत और तेजमय लपट उठी, जो क़रीब 40-50 फुट तक आकाश की ओर गई. कुछ देर बाद यह अद्भुत ज्योति पुनः हवन कुंड की ओर वापस आकर भूमिगत हो गई. इस ज्योति के नीचे आते ही उसमें से दिव्य रूप वाली भैरवियां उपस्थित हुईं. हो सकता है कि वे जंगल में कहीं पहले से ही रही हों और हवन कुंड के प्रकाश के कारण इधर आकृष्ट हो गई हों. वे कब और कैसे आईं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं. उनकी वेशभूषा बड़ी विचित्र थी. वस्त्र नीला था, गले में स्फटिक की चमकती माला थी और हाथ में नारियल का कमंडल था. मैंने उन्हें काफी नज़दीक से देखा था. रात्रि में भरत मिलाप के महंत कह रहे थे कि ये भैरवियां आकाशगामिनी हैं. ये भैरवियां भी चकार्चन के साथ-साथ पान-पात्र ग्रहण कर रही थीं. साधना के उपरांत लोगों ने घोरा देवी को प्रणाम किया और थोड़ा विश्राम करते ही कालिंजर की भैरवी के साथ भैरवियां कब और किस मार्ग से चली गईं, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उस समय मैं अत्यधिक थका था, आंखें भारी हो रही थीं और मुझे नींद आ रही थी. ■

क्रमशः

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

ज़फर सरेशवाला का ज़हरीला बयान

“ज़फर सरेशवाला का वाक्य छोटा है, लेकिन ज़फर सरेशवाला के रिश्ते, जफर सरेशवाला की हैसियत और ज़फर सरेशवाला के क़दम इस वाक्य को बहुत बड़ा बना देते हैं. देश के मुस्लिम संगठनों को जफर सरेशवाला की इस बात का विरोध करना चाहिए और कहना चाहिए कि ज़फर सरेशवाला को न भारत के संविधान की समझ है, न भारत के क़ानून की समझ है, न भारत के सोशल फैब्रिक की समझ है, न भारत में जीने के अंदाज़ की समझ है. हिंदुस्तान में हम सिर्फ़ पूजा पद्धति को लेकर अलग हैं, लेकिन देश के सवालों पर इस देश में रहने वाला हर आदमी एक साथ है, संविधान के सामने या क़ानून के सामने उसकी बराबर की हैसियत है.”

वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की जाए कि वह अपने साथियों को या तो समझाएं या फिर उन्हें खुद से अलग करें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक साथी हैं, ज़फर सरेशवाला. वह विदेशी बिजनेसमैनों की तरफ़ से हिंदुस्तानी मुसलमानों के बीच नरेंद्र मोदी का पक्ष लेने की कोशिश का नेतृत्व करने वालों के नेता हैं और लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि अच्छी बनाने की काफी कोशिश की. यह ज़फर सरेशवाला का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एहसान है और शायद नरेंद्र मोदी इस एहसान को मानते भी हैं. इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के बीच अपना राजदूत भेज दिया है, जो नरेंद्र मोदी की अच्छाइयां मुसलमानों को बता रहा है. हालांकि, मुसलमानों के बीच अभी तक ज़फर सरेशवाला पूरी तरह स्वीकार्य नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम नेता, जिन्हें लगता है कि अगले दस सालों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहने वाले हैं, वे ज़फर सरेशवाला के साथ छिपा हुआ हाथ बढ़ा रहे हैं, ताकि वे उनकी गुडबुक में आ सकें.

ज़फर सरेशवाला ने एक ख़तरनाक काम किया है. सलमान खान के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि सलमान खान को सजा इसलिए हुई, क्योंकि सलमान खान मुसलमान हैं. सलमान खान सलमान खान हैं, यह अगर कोई कट्टरपंथी संगठन कहता, तो बात समझ में आती. कोई ऐसा जाहिल कहता, जिसे भारतीय संविधान की समझ नहीं है, तो भी बात समझ में आती. लेकिन, यह बात ज़फर सरेशवाला कह रहे हैं. इसका मतलब है कि या तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति से ऐसा कह रहे हैं या फिर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुसीबत में डालने के लिए यह बात कह रहे हैं. इस वाक्य का मतलब बहुत दूर तक जाता है.

क्या इस देश का संविधान अब अपराध करने वालों या अपराध का आरोप लगाने वालों को धर्म के आधार पर देखेगा या सबको एक नज़र से देखेगा? अदालतें दोषी व्यक्ति को संविधान सम्मत सजा, क़ानून सम्मत सजा देंगी या फिर धर्म के आधार पर सजा देंगी? ज़फर सरेशवाला जब यह कहते हैं कि सलमान खान को मुसलमान होने के नाते सजा मिली, तो वह इस तर्क को सही साबित करते हैं कि जो हिंदू उग्रवाद के नाम पर जेल में हैं, उन सारे लोगों को सजा इसलिए मिली, क्योंकि सरकार मुस्लिम अपीजमेंट करना चाहती है या मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए वह कुछ लोगों को जेल में डाल रही है.

क्या ज़फर सरेशवाला देश को यह संदेश दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश के नागरिकों को धर्म के आधार पर देखे जाने के पक्ष में हैं? क्या अब क़ानून अपराधी को हिंदू या मुसलमान में बांटकर देखेगा? सलमान खान ने अपराध किया है या नहीं किया है, इसका फ़ैसला अदालत करेगी, जहां मुक़दमा चल रहा है. सेशन कोर्ट ने पांच साल की सजा दी है. हाईकोर्ट में उसकी अपील होगी और हाईकोर्ट के बाद उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी तथा सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह अंतिम रूप से तय होगा कि जिस व्यक्ति के ऊपर यह मुक़दमा चल रहा है, वह दोषी है या नहीं है. संजय दत्त का मुक़दमा सुप्रीम कोर्ट तक चला, तब उन्हें सजा मिली. यही प्रक्रिया सलमान खान के केस में होगी या यही प्रक्रिया किसी के भी केस में होगी. बशर्ते, वह सुप्रीम कोर्ट जा सके, क्योंकि

क्या इस देश का संविधान अब अपराध करने वालों या अपराध का आरोप लगाने वालों को धर्म के आधार पर देखेगा या सबको एक नज़र से देखेगा? अदालतें दोषी व्यक्ति को संविधान सम्मत सजा, क़ानून सम्मत सजा देंगी या फिर धर्म के आधार पर सजा देंगी? ज़फर सरेशवाला जब यह कहते हैं कि सलमान खान को मुसलमान होने के नाते सजा मिली, तो वह इस तर्क को सही साबित करते हैं कि जो हिंदू उग्रवाद के नाम पर जेल में हैं, उन सारे लोगों को सजा इसलिए मिली, क्योंकि सरकार मुस्लिम अपीजमेंट करना चाहती है या मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए वह कुछ लोगों को जेल में डाल रही है.

हर एक को 20 लाख रुपये प्रति पेशी चार्ज करने वाला वकील नहीं मिल सकता और यह बात इस देश में जो भी क़ानूनी प्रक्रिया से गुज़रता है, उसे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में मुक़दमा लड़ने वाले वकीलों की फीस प्रति पेशी कितनी है, चाहे सुनवाई हो या न हो.

अब ज़फर सरेशवाला कह रहे हैं कि अपराधी को हिंदू और मुसलमान की नज़र से देखना चाहिए और वह व्यक्ति एक बड़ी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है. वह व्यक्ति इस देश में नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के नाते या भाजपा के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि के नाते घूम भी रहा है. लोगों को आश्वासन भी दे रहा है और उनसे नरेंद्र मोदी के साथ आने की बात भी कर रहा है. क्या इसके पीछे भाजपा खड़ी है? अगर खड़ी है, तो इस देश में बहुत जल्दी संविधान या क़ानून की यह बात ग़लत साबित करने की कोशिश होगी कि क़ानून के सामने सब बराबर हैं या संविधान के सामने सब बराबर हैं. इस देश में कोई दोयम दर्जे का नागरिक नहीं है और क़ानून यह कहता है कि सौ अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए. ये सारे वाक्य अर्थहीन साबित हो जाएंगे.

ज़फर सरेशवाला अगर तत्काल माफी नहीं मांगते और भाजपा उन्हें अलग नहीं करती तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़फर सरेश वाला पर सख्त एक्शन नहीं लेते, तो देश में यह ग़लत संदेश जाएगा कि ज़फर सरेशवाला के माध्यम से इस देश में हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की एक नई कोशिश होने वाली है. ज़फर सरेशवाला ने यह वाक्य बिल्कुल उसी अंदाज़ में कहा है, जिस अंदाज़ में या तो कट्टरपंथी या अलगाववादी या देश में दहशतगर्दी फैलाने वाला व्यक्ति कह सकता है. इस बयान को सुनते ही भविष्य का दृश्य सामने आता है.

ज़फर सरेशवाला का वाक्य छोटा है, लेकिन ज़फर सरेशवाला के रिश्ते, जफर सरेशवाला की हैसियत और ज़फर सरेशवाला के क़दम इस वाक्य को बहुत बड़ा बना देते हैं. देश के मुस्लिम संगठनों को जफर सरेशवाला की इस बात का विरोध करना चाहिए और कहना चाहिए कि ज़फर सरेशवाला को न भारत के संविधान की समझ है, न भारत के क़ानून की समझ है, न भारत के सोशल फैब्रिक की समझ है, न भारत में जीने के अंदाज़ की समझ है. हिंदुस्तान में हम सिर्फ़ पूजा पद्धति को लेकर अलग हैं, लेकिन देश के सवालों पर इस देश में रहने वाला हर आदमी एक साथ है, संविधान के सामने या क़ानून के सामने उसकी बराबर की हैसियत है. उसे धर्म के आधार पर आज अगर ज़फर सरेशवाला बांटने की बात करेंगे, तो कल कोई यह भी कह सकता है कि उसे सजा इसलिए मिली या उसके ऊपर मुक़दमा इसलिए चला, क्योंकि वह दलित है, वह निर्बल है, वह वंचित है, वह आदिवासी है, वह अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता. पद्धति में असमानताएं हो सकती हैं, लेकिन सिद्धांत में असमानताएं नहीं हो सकतीं और इसीलिए ज़फर सरेशवाला के इस वाक्य का विरोध होना चाहिए. और, इसमें छिपी हुई भावना का न केवल खंडन होना चाहिए, बल्कि उसकी लानत-मलामत भी होनी चाहिए. इस देश का संविधान इस देश में रहने वालों को समान अधिकार देता है, समान दृष्टि देता है और क़ानून के सामने हर एक की हैसियत इंसान की हैसियत होती है. किसी धर्म के नाते विशेष या कमजोर स्थिति नहीं होती.

बहरहाल, इस फ़ैसले के बाद क्या अब इस पर बहस होगी कि देश में उन लोगों को भी, जो 20 लाख रुपये का वकील अपने लिए कोर्ट में खड़ा नहीं कर सकते, इसी तरह से न्याय मिलेगा? क्या आज के बाद उन सारे लोगों को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया जाएगा और उन सबको जमानत मिल जाएगी, जो छोटे-मोटे अपराधों में जेल में बंद हैं और जिनके केस की सुनवाई जारी है? देश में इस समय ढाई लाख विचाराधीन कैदी जेल में हैं. क्या ऐसे लोगों को सर्वोच्च अदालत से अंतिम फ़ैसला आने तक जेल से बाहर रहने का मौक़ा मिलेगा या फिर क़ानून के सामने सब एक हैं, वाली बात सिर्फ़ जुमला बनकर रह जाएगी? ■

editor@chauthiduniya.com

किसानों की समस्या एक राष्ट्रीय संकट है

सरकार की तरफ़ से कृषि क्षेत्र की अनदेखी किसानों (खास तौर पर जीवनयापन के लिए कृषि करने वाले किसान) की परेशानी का कारण है. पचास के दशक में अर्थशास्त्र का छात्र होने के नाते हमें भारत की आर्थिक समस्या पर एक पेपर पढ़ना पड़ता था. जहां तक किसानों की परेशानी का सवाल है, तो ऐसा लगता है कि पिछले 60 वर्षों में कुछ भी नहीं बदला है. जीवनयापन के लिए की जाने वाली कृषि आज भी वैसी है, जैसी उस जमाने में थी यानी छोटे-छोटे अलाभकारी खेत, ग्रामीण ऋण व्यवस्था का अभाव और अधिकारियों एवं राजनेताओं द्वारा बड़े किसानों की सहायता.

मेघनाद देसाई

भारत को यमन में बचाव कार्य के लिए जो तारीफ़ मिली, उसका वह हक़दार था. दुनिया के कई देश यमन में फंसे अपने नागरिकों की मदद के लिए भारत की ओर देख रहे थे. भारत ने नेपाल में भूकंप की भयानक त्रासदी के बाद बचाव कार्य में एक बार फिर अनुकरणीय भूमिका निभाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सच्चा नेता होने का सुबूत देते हुए तात्कालिक ज़रूरत के तहत नेपाल को सहायता पहुंचाई. वस्तुतः यह एक शासनात्मक ज़िम्मेदारी थी, जिसे लेकर प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसे अनुभवों से गुज़र चुके थे, तैयार थे और उन्हें पता था कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए. फिलहाल सरकार राजनीतिक और वैधानिक समस्याओं में उलझी हुई है. इन समस्याओं का हल संसाधन मुहैया कराकर नहीं किया जा सकता है. यहां लक्ष्य जरा अनिश्चित है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम में सहयोग करने के लिए विपक्ष को कोई प्रलोभन नहीं है. जबकि इसके उलट सरकारी काम को संसद में बाधित करने से उसे फ़ायदा मिलेगा. यही विपक्ष-धर्म है. ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रहित की अपील का भी कोई असर नहीं होता है.

सरकार की तरफ़ से कृषि क्षेत्र की अनदेखी किसानों (खास तौर पर जीवनयापन के लिए कृषि करने वाले किसान) की परेशानी का कारण है. पचास के दशक में अर्थशास्त्र का छात्र होने के नाते हमें भारत की आर्थिक समस्या पर एक पेपर पढ़ना पड़ता था. जहां तक किसानों की परेशानी का सवाल है, तो ऐसा लगता है कि पिछले 60 वर्षों में कुछ भी नहीं बदला है. जीवनयापन के लिए की जाने वाली कृषि आज भी वैसी है, जैसी उस जमाने में थी यानी छोटे-छोटे अलाभकारी खेत, ग्रामीण ऋण व्यवस्था का अभाव और अधिकारियों एवं राजनेताओं द्वारा बड़े किसानों की सहायता. अब घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं, जबकि यह समस्या आज विपक्ष में बैठी पार्टियों की नीतियों का ही नतीजा है. दरअसल, यह कोई बहाना नहीं है कि इसकी वजह से सरकारी कामकाज में कोई प्रगति नहीं हो रही है. ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार किसानों की परेशानियां कम करने के लिए कुछ करती नज़र नहीं आ रही है. हालांकि, यह राज्यों का विषय है, लेकिन फिर भी यह एक राष्ट्रीय संकट है. कृषि मंत्री को न हम किसी टीवी चैनल की स्क्रीन पर देख पाते हैं और न उनका नाम याद आता है. बेशक, वह अपनी तरफ़ से कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन पिछले तीन महीनों में राहत का कौन-सा काम हुआ है, किसी को नहीं मालूम. ट्वीटर पर मीडिया की ख़बरें और अख़बारों में विज्ञापन कहां हैं? हम केवल विपक्ष को देख और सुन रहे हैं, जिसके पास विरोध करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है.

अमेरिका में 1930 के दशक की महा-मंदी ने छोटे और मझोले किसानों को शहरी क्षेत्रों में जाने पर मजबूर किया था. यह बहुत ही पीड़ादायक त्रासदी थी, जिसका बेहतरीन चित्रण अंग्रेजी के उपन्यासकार जॉन स्टेनबेक ने अपने उपन्यास-दि ग्रेप्स आफ रॉथ में किया है. भारत अब ऐसे ही मुश्किल दौर में पहुंच गया है. 67 वर्षों से छोटे किसानों की अनदेखी अब अपनी अंतिम हद पर पहुंच गई है. प्रधानमंत्री मोदी को इस समस्या का संज्ञान वैसे ही लेना चाहिए, जैसे उन्होंने यमन और नेपाल की समस्या के संबंध में लिया था. उन्हें किसानों के लिए एक नेशनल फार्मर्स रिलीफ इनिशिएटिव गठित करना चाहिए. ज़ाहिर है, पैसा कोई समस्या नहीं है. लेकिन जो समस्या है, वह है इस व्यापक त्रासदी से निपटने के लिए गंभीर सोच की. नेहरू के जमाने में जो बड़ी चिंता थी,

वह यह थी कि शहरी आबादी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न (जिसे बिक्री योग्य अतिरिक्त पैदावार कहा जाता था) नहीं थी. बड़े एवं उपजाऊ खेतों में खेती करके हरित क्रांति ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया. अब भारत में खाद्यान्न की इतनी बहुतायत हो गई है कि जगह-जगह अनाज सड़ रहा है. बहरहाल अभी जो मुद्दा है, वह है छोटे-छोटे अलाभकारी खेतों में धीरे-धीरे खेती बंद करने की और किसानों को स्थायी विकल्प उपलब्ध कराने की. किसान शब्द सुनकर भावुक हो जाना कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि इससे अच्छा यह है कि कठोर बनकर किसान और उसके परिवार को अच्छा भविष्य दिया जाए. ऐसे में बुनियादी सुविधाओं के विकास की योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं. उद्योग-धंधों को बहुत तेजी से स्थापित करना होगा. श्रम क़ानूनों में बदलाव के सिलसिले में बरती जा रही सावधानी छोड़नी होगी. लोगों का जीवन, खासकर आने वाले पीढ़ी का जीवन दांव पर है. लिहाज़ा, इसे केवल राष्ट्रीय संकट घोषित करके ही चीज़ों को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है. सरकार एक अग्नि परीक्षा से गुज़र रही है. उसके लिए अच्छा यह है कि उसका इस परीक्षा से सामना बहुत पहले हो गया है. प्रधानमंत्री मोदी के पास अभी अपनी शक्ति एकत्र करने, अपने कैबिनेट में फेरबदल करने और पिछली बेंच पर बैठने वाले अपने सदस्यों को फटकार लगाने का समय है कि उन्हें काम करना होगा और काम करते दिखना होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

हाई ब्लड प्रेशर हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है. इसके कारण हृदयाघात, मानसिक आघात, गुर्दा संबंधी बीमारी और अंधेपन की समस्या हो सकती है. लेकिन, रक्तचाप अगर सामान्य से कम हो, तो वह भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता. इसलिए किसी भी उपचार को करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें. बीपी की समस्या होने पर ऐगुलर दवाई का सेवन करना पड़ता है. लेकिन ऐगुलर मेडिसिन के बाद भी अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं होता तो दवाई के अलावा कई चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है.

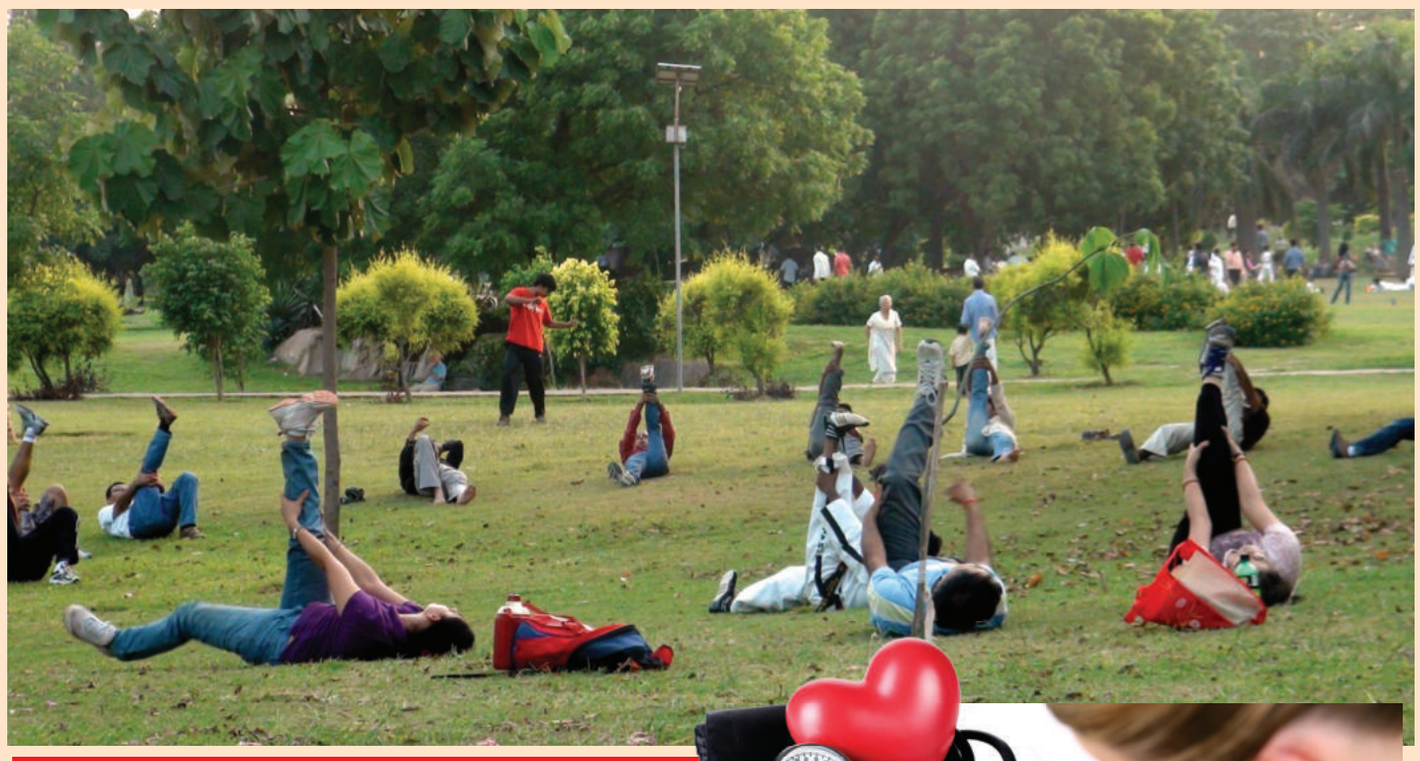

हाई ब्लड प्रेशर से बचें

मोनिशा भटनागर

ब्लड प्रेशर या रक्तचाप, आजकल होने वाली सबसे आम बीमारी है. आधुनिक जीवनशैली के कारण उच्च रक्तचाप की समस्या पहले से कई गुना बढ़ गई है. पहले रक्तचाप को केवल बुजुर्गों की या बुढ़ापे की बीमारी समझा जाता था और ऐसा माना जाता था कि युवाओं को यह रोग नहीं हो सकता, लेकिन आज मोटापे और बदली हुई जीवनशैली के कारण युवा भी उच्च रक्तचाप के शिकार हो रहे हैं. इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते. इसलिए इसकी नियमित निगरानी जरूरी होती है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि बीपी होता क्या है? जब हार्ट की धमनियों में प्रेशर बढ़ जाता है, तब ब्लड को ऑर्गन तक सप्लाई करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना होता है, इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं. दिल को तंदरुस्त बनाए रखने के लिए ब्लड प्रेशर का नियंत्रित रहना बहुत जरूरी है. हृदय स्वास्थ्य और ब्लड प्रेशर एक–दूसरे से जुड़े हैं. हाई ब्लड प्रेशर होने पर हृदय संबंधी परेशानियां होने की आशंका ज्यादा होती है. आमतौर पर सिरदर्द, चक्कर आना और धड़कन बढ़ना बीपी के लक्षण माने जाते हैं. बीमारी न होने पर भी अपना बीपी लेवल समय–समय पर जांच कराते रहना चाहिए और कभी भी जांच में बीपी बढ़ा हुआ आये तो इसकी सही वजह पता करनी चाहिए. आइडियल या नॉर्मल बीपी लेवल 120/80 माना जाता है. अगर इससे कम आता है तो इसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है और इससे ज्यादा होता है तो इसे हाई बीपी कहा जाता है.

आज की जीवनशैली में मशीनों पर बढ़ती निर्भरता बढ़ते तनाव और चिंताओं के कारण उच्च रक्तचाप बहुत आम बीमारी बन गई है. आम होने की वजह से यह बीमारी भले ही छोटी लगती हो, लेकिन हृदयाघात और अन्य हृदय रोग होने का यह प्रमुख कारण है. ऐसे में जरूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखा जाए. बीपी बढ़ने पर आमतौर पर चक्कर आने लगते हैं, सिर घूमने लगता है, रोगी का किसी काम में मन नहीं लगता. उसमें शारीरिक काम करने की क्षमता नहीं रहती और रोगी अनिद्रा का शिकार रहता है. इनमें से कोई भी लक्षण महसूस होने पर फ़ौरन बीपी की जांच करवानी चाहिए. यदि आपके परिवार या नजदीकी संबंधी में से किसी को उच्च रक्तरचाप की शिकायत है, तो आपको भी यह बीमारी होने का खतरा होता है. ऐसे में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है.

हाई ब्लड प्रेशर हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है. इसके कारण हृदयाघात, मानसिक आघात, गुर्दा संबंधी बीमारी और अंधेपन की समस्या हो सकती है. लेकिन, रक्तचाप अगर सामान्य से कम हो, तो वह भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता. इसलिए किसी भी उपचार को करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें. बीपी की समस्या होने पर रेगुलर दवाई का सेवन करना पड़ता है. लेकिन रेगुलर मेडिसिन के बाद भी अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं होता तो दवाई के अलावा कई चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है. नमक ब्लड प्रेशर बढाने वाला प्रमुख कारक है, इसलिए हाई बीपी वाले लोगों को नमक का प्रयोग कम या डॉक्टर के बताए अनुसार बंद कर देना चाहिए. साथ ही लाइफ स्टाइल बदलने और स्मोकिंग या अल्कोहल से परहेज़ करने पर भी बीपी पर नियंत्रण पाया जा सकता है. नियमित वॉक और एक्सरसाइज, तली चीजों और जंक फूड से दूरी भी बीपी को नियंत्रित रखने और हाई ब्लड प्रेशर से निदान के लिए जरूरी है. इसके अलावा ब्लड प्रेशर की नियमित जांच अति आवश्यक है.

बीपी की समस्या से बचने के लिए अथवा बीपी को नियंत्रित रखने के लिए सबसे ज़रूरी है रोज़मर्रा के खाने–पीने में नमक का सेवन कम मात्रा में करना. इससे बीपी की समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है. अधिक मात्रा में नमक का सेवन, हृदय समस्याओं के खतरे को बढ़ाता है. इसके अलावा ऐसा खाना, जिससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है, अधिक मात्रा में और नियमित रूप से नहीं खाना चाहिए. कोलेस्ट्राल का स्तर बढ़ने से रक्तचाप भी बढ़ता है और इसका असर सीधा हार्ट पर भी पड़ता है. खान–पान के सिवा अपने गुस्से पर भी नियंत्रण करना चाहिए. अक्सर देखा जाता है कि जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनका रक्तचाप का स्तर भी अधिक होता है. गुस्से से तनाव बढ़ता है और तनाव हाई बीपी का एक प्रमुख कारण है. तनाव दूर करने और बीपी नियंत्रित करने के लिए मेडिटेशन और योग का सहारा भी लिया जा सकता है. विशेषज्ञों के मुताबिक, ज्यादा मात्रा में एल्कोहल का सेवन भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है. एल्कोहल के सेवन से वजन भी बढ़ता है, जो सेहत के लिए और भी नुकसानदेह है. इन सबसे अहम है नियमित व्यायाम. प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट का व्यायाम अवश्य करना चाहिए. यदि आप किसी रोग या समस्या से ग्रस्त हैं तो डॉक्टर से सलाह लें कि किस तरह का व्यायाम आपके लिए सही रहेगा. व्यायाम से न केवल आपका शरीर चुस्त रहता है, बल्कि इससे वजन भी नियंत्रित रहता है. सामान्य से ज्यादा वजन भी हाई ब्लड प्रेशर का कारण होता है. अधिक वजन वाले लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने की ज्यादा आशंका होती है. इसके लिए पॉवर वॉक करना बेहतर उपाय है. तेज गति से चलने से न केवल आपकी फिटनेस में सुधार होता है, बल्कि इससे बीपी को भी नियंत्रित करने में मदद मिलती है. साथ ही इससे हमारे दिल की कार्यक्षमता में भी इजाफा होता है.

हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए आज कई दवायें मौजूद हैं. डॉक्टर की सलाह से इन दवाओं के नियमित सेवन से बीपी पर नियंत्रण रखा जा सकता है, लेकिन दवाओं के साथ–साथ जीवनशैली में ठोस बदलाव को अपनाये बिना बीपी से पूरी तरह नहीं निपटा जा सकता.■

feedback@chauthiduniya.com

एक फ्रांसीसी खुफिया एजेंट

डेनिस मैडेलिन ब्लोच

डेनिस के तेवरों से जीम यह बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि जिम्मेदारियों को निभाने में डेनिस का कोई सानी नहीं होगा. डेनिस को लियोन में जासूसी एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी गई. उन्होंने जर्मनी के विरोध के लिए बनाई गई फ्रेंच रेजिस्टेंस आर्मी के लिए काम करना शुरू किया. और वे फ्रेंच रेजिस्टेंस के लिए तब तक काम करती रहीं, जब तक कि उन्हें जर्मन सैनिकों द्वारा गिरफ्तार नहीं कर लिया गया.

अरूण तिवारी

डेनिस मैडेलिन ब्लोच एक फ्रांसीसी खुफिया एजेंट थीं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश स्पेशल ऑपरेशन एक्जीक्यूटिव के साथ काम करती थीं. उनका जन्म 1916 में एक यहूदी परिवार में हुआ था. ब्लोच के तीन भाई थे. द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले उन्होंने पेरिस में ही कुछ दूसरी जगहों पर नौकरी की. इस तरह की एक कंपनी सीट्रोइन, जिसमें वह लेफ्टिनेंट जीन मैक्सिम एरोन की सेक्रेटरी थीं.

जीन मैक्सिम एरोन की सेक्रटरी बनने की कहानी भी दिलचस्प है. डेनिस पेरिस में ही एक प्राइवेट कंपनी रिसेप्शनिस्ट काम किया करती थीं. वहां जीन मैक्सिम किसी काम से आए थे. उन्होंने रिसेप्शनिस्ट डेनिस से बातचीत कर कंपनी के एक अधिकारी से मिलवाने के लिए कहा. डेनिस ने उस अधिकारी की अप्वाइंटमेंट लिस्ट देखी, जिसमें जीन मैक्सिम का नाम नहीं था. डेनिस ने जीन मैक्सिम से कहा कि आपका तो आज का अप्वाइंटमेंट ही नहीं है, मैं कैसे आपको उस अधिकारी से मिलवा सकती हूं. जीन को अपने वीआईपी होने का एहसास था. उन्होंने डेनिस पर इस बात का दबाव डाला कि उन्हें अधिकारी से मिलने दें लेकिन डेनिस लगातार इस बात डटी रहीं कि जब तक अप्वाइंटमेंट न हो, वह उन्हें उस अधिकारी से मिलने नहीं दे सकतीं. जीम वहां से वापस लौट गए, लेकिन उन्हें डेनिस के व्यवहार ने काफी प्रभावित किया था. उन्होंने डेनिस से एक बार फिर मुलाकात की और कहा कि मैं तुम्हे देश सेवा का मौका देना चाहता हूं. ऐसा कहा जाता है कि डेनिस को मौका दिए जाने के पीछे एक और भी कारण मौजूद था. वह कारण था डेनिस का यहूदी होना. दरअसल, जीन भी एक यहूदी ही थे और उस समय हिटलर की सेनाएं यहूदियों का नरसंहार चरम पर जाकर कर रही थीं. जर्मनी और आसपास के इलाकों में यहूदियों की निर्मम हत्याएं की जा रही थीं. पूरी दुनिया में इसकी निंदा हो रही थी. शायद यह भी एक वजह थी कि जीम चाहते थे कि डेनिस उनके साथ काम करें और यहूदियों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध एक आवाज बन सकें.

डेनिस के तेवरों से जीम यह बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि जिम्मेदारियों को निभाने में डेनिस का कोई सानी नहीं होगा. डेनिस को लियोन में जासूसी एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी गई. उन्होंने जर्मनी के विरोध के लिए बनाई गई फ्रेंच रेजिस्टेंस आर्मी के लिए काम करना शुरू किया. और वे फ्रेंच रेजिस्टेंस के लिए तब तक काम करती रहीं, जब तक कि उन्हें जर्मन सैनिकों द्वारा गिरफ्तार नहीं कर लिया गया.

गिरफ्तार किए जाने के बाद वे दो ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क में रहती थीं. उन्होंने दक्षिण फ्रांस जासूसी के ब्रिटिश नेटवर्क को संचालित करना शुरू कर दिया. उन्हें भले ही जर्मन सैनिकों ने नजरबंद कर रखा था, लेकिन वो इस दौरान भी सभी ब्रिटिश एजेंटों के साथ कॉर्डिनेशन का काम करती थीं. नजरबंद रहने के दौरान ही एक दिन नाजी सैनिकों की सुरक्षा में चूक का फायदा उठाते हुए डेनिस भागने में कामयाब हो गईं. कई स्रोतों से यह जानकारी मिलती है कि डेनिस ने करीब 400 किलोमीटर तक की यात्रा पैदल ही की थी. इस यात्रा के बाद वह दक्षिणी फ्रांस पहुंचीं, जहां फ्रेंच रेजिस्टेंस आर्मी के सैनिकों ने उनके ब्रिटेन जाने का प्रबंध किया. अपनी सेना का बेस मिलते ही डेनिस ने कुछ महत्वपूर्ण गुप्त सुचनाएं सेना को दीं और अधिकारियों को यह बताया कि कई जगहों पर जर्मन सैनिक हमला करने वाले हैं, इसलिए ब्रिटिश सेनाओं को सतर्क हो जाने की जरूरत है. डेनिस की इस जानकारी की वजह न सिर्फ कई ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाने में कामयाबी मिली थी, बल्कि फ्रांस में काम कर रहे एसओई के कई जासूसों को बचाया जा सका था. इसके तुरंत बाद डेनिस को लंदन वापस भेज दिया गया, जहां पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अधिकारियों द्वारा उन्हें रेडियो ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी जाने लगी. जब वे रेडियो ऑपरेटर के काम में पूरी तरह निपुण हो गईं और ब्रिटिश अधिकारियों को इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि डेनिस अब आसानी से फ्रांस में एक रेडियो ऑपरेटर के तौर पर काम कर सकती हैं तो उन्हें एक बार फिर जर्मनी अधिकृत फ्रांस भेज दिया गया.

डेनिस ने एक बार फिर नये तरीके से काम करना शुरू किया. पेरिस के कई इलाकों में जर्मन अधिकारियों के साथ घुल मिल कर डेनिस ने जानकारियां निकालनी शुरू कर दीं. इन जानकारियों के जरिये ब्रिटिश अधिकारी जर्मन सैनिकों को काफी परेशान किया करते थे. रेडियो ऑपरेटर के तौर पर काम करते हुए डेनिस से एक चूक हो गई. वे एक जानकारी ब्रिटिश अधिकारियों को दे रही थीं, जिसकी भनक जर्मन सैनिकों को लग गई. उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. जर्मनी के प्रताड़ना गृह ले जाकर उन्हें तरह–तरह से प्रताड़ना दी गई. जर्मन अधिकारियों ने उन्हें गोली मार दी. इस तरह मानवता के लिए काम करने वाली एक महिला की बेरहम मौत हो गई. डेनिस की भले ही मौत हो गई हो, लेकिन वे दुनियाभर में अपने साहसिक कार्यों के लिए याद की जाएंगी.■

feedback@chauthiduniya.com

यमन संकट

पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय नीति पर ग्रहण

शफीक आलम

पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय नीति एक बार फिर इस देश के लिए परेशानी का सबब बनती दिख रही है. मामला है यमन में ईरान समर्थित शिया हौती विद्रोहियों के विरुद्ध सऊदी अरब की तरफ से फौजी करवाई का. इस कार्रवाई में सऊदी अरब पाकिस्तान से फौजी मदद की उम्मीद कर रहा था. शुरू-शुरू में पाकिस्तान की तरफ से सकारात्मक रुख का भी पता चला, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने इस मामले में हस्तक्षेप न करने का फैसला लिया. ज़ाहिर है, इस फैसले से सऊदी अरब और इस क्षेत्र में उसके सहयोगी देश नाखुश हैं. कई देशों ने तो खुल कर अपनी नाराज़गी भी ज़ाहिर की है. ऐसे में पाकिस्तान के सामने जहां एक तरफ सऊदी अरब जैसे मित्र देश हैं, वहीं इस मामले का एक पक्ष ईरान जैसा एक पड़ोसी भी है, जिसे वह नाराज़ करने की जोखिम नहीं उठा सकता. पाकिस्तान की अफ़ग़ानिस्तान नीति में बुरी तरह नाकामी भी उसके समक्ष है. ऐसे में यह मसला पाकिस्तान के लिए सांप और छुछुंदर का खेल बन गया है.

यमन के मौजूदा संकट के दौरान जो मुख्य लड़ाई है, वह राष्ट्रपति अबद रब्बुह मंसूर हादी की हिमायती फौजों और शिया हौती लड़कों के बीच की है, लेकिन इनके साथ-साथ अल-काएदा और आईएसआईएस से जुड़ा संगठन भी समय-समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं. कुल मिला कर देश में गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन बुनियादी तौर पर यह लड़ाई एक बार फिर शिया-सुन्नी के सत्ता के संघर्ष की लड़ाई है, जो इराक और सीरिया में पहले से ही चल रही थी. अरब देशों में शिया-सुन्नी के दरमयान वर्चस्व की दौड़ में क्षेत्र के दो बड़े देश ईरान और सऊदी अरब अब खुल कर सामने आ गए हैं.

हालांकि अमेरिका ने ईरान को यमन के मामले में हस्तक्षेप न करने की हिदायत दी है, लेकिन यह माना जा रहा है कि ईरान हौती विद्रोहियों की छुपे तौर पर मदद कर रहा है. वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब हौती विद्रोहियों के खिलाफ यमन के मौजूदा राष्ट्रपति अबद रब्बुह मंसूर हादी का समर्थन कर रहा है. सऊदी अरब ने हौती विद्रोहियों के खिलाफ अभी तक केवल हवाई हमले ही किए हैं. जहां तक इन हमलों के प्रभाव का सवाल है, तो ज़मीनी हकीक़त यह बताती है कि इसका कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है. संयुक्त राष्ट्र संघ में यमन के राजदूत खलील अल-यमनी ने हौती विद्रोहियों खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई करने की मांग की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यमन की मदद की गुहार भी लगाई है. इन्हीं खबरों के बीच से यह खबर भी आई कि सऊदी अरब ने 5 दिन के सशर्त युद्ध विराम की घोषणा कर दी है. अब इस युद्ध विराम का क्या अंजाम होता है, यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान बुरी तरह से उलझा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से आधिकारिक तौर पर उसकी ज़मीनी फ़ौज, लड़ाकू जहाज़ और टैंक इत्यादि की सहायती मांगी. पाकिस्तान ने इस आग्रह पर कुछ सकारात्मक संकेत दिए थे, लेकिन अभी सऊदी आग्रह पर विचार चल ही रहा था कि ईरान के विदेश मंत्री मुहम्मद जावेद ज़रीफ़ पाकिस्तान के दौरे पर आए. उसके बाद पाकिस्तानी सीनेट ने एकमत से यह फैसला किया कि पाकिस्तान यमन के मामले में तटस्थ रहेगा, लेकिन सऊदी अरब की सुरक्षा खतरे में पड़ी तो पाकिस्तान उसकी हर मुमकिन सहायता करेगा.

अब सवाल यह उठता है कि आखिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से इतने हक से फौजी मदद क्यों मांगी? तो इसका साधारण सा जवाब यह है कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल समय में पाकिस्तान की मदद की है. अब वह पाकिस्तान से बदला चाहता है. पाकिस्तान द्वारा 1998 के परमाणु हथियारों के परीक्षण के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिया था. ऐसे समय में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता के साथ-साथ 5 लाख बैरल पेट्रोल मुफ्त मुहय्या करवाया था. सऊदी सरकार ने अभी हाल ही में पाकिस्तान को 1.5 अरब डॉलर की सहयता दी है. इसके अलावा कई लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं, जो अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा अपने घर भेजते हैं. आर्थिक तंगी से गुज़र रहे इस देश के लिए यह पैसा बहुत ही अहम है. साथ ही पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ अपने निर्वासन के दौरान सऊदी में ही पनाह ली थी. अतीत में पाकिस्तान ने कई मौकों पर सऊदी अरब की सहायता की है, जिसमें 1969 में हौती विद्रोहियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई के दौरान और 1980 में इस देश के यमन से लगे सीमा को सुरक्षित करने में अपनी सहायता दी थी. इसलिए सऊदी अरब को इस बार भी पाकिस्तान से मदद की उम्मीद थी.

अमेरिका ने ईरान को यमन के मामले में हस्तक्षेप न करने की हिदायत दी है, लेकिन यह माना जा रहा है कि ईरान हौती विद्रोहियों की छुपे तौर पर मदद कर रहा है. वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब हौती विद्रोहियों के खिलाफ यमन के मौजूदा राष्ट्रपति अबद रब्बुह मंसूर हादी का समर्थन कर रहा है. सऊदी अरब ने हौती विद्रोहियों के खिलाफ अभी तक केवल हवाई हमले ही किए हैं.

ज़ाहिर है यह फैसला सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों को खुश करने वाला फैसला नहीं था. जहां सऊदी अरब ने इस फैसले पर अपनी निराशा व्यक्त की वहीं यूनाइटेड अरब अमिरात (युएई) ने खुल कर पाकिस्तान को जता दिया कि इस फैसले का पाकिस्तान पर क्या असर होगा. युएई के विदेश मंत्री डॉ. अनवर मुहम्मद गारगश ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि उसे इस फैलसे की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी. अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान ने यह फैसला क्यों लिया? चूंकि वह पहले भी यमन के मामले में सऊदी अरब की सहायता कर चुका है तो अभी क्यों नहीं? पाकिस्तान आखिर अपने मित्र देशों की नाराज़गी उठाने के लिए क्यों तैयार हो गया? दरअसल, पिछले दशक में पाकिस्तान और क्षेत्र की भू-राजनीति में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया है. अफ़ग़ानिस्तान में पाकिस्तान ने पहले तालिबान को खड़ा किया, फिर 9/11 के बाद तालिबान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के सहयोगी की भूमिका निभाई. बीच-बीच में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान पर तालिबान और अल-कायदा की मदद के आरोप भी लगे. नतीजा यह हुआ पाकिस्तान पर अब न तो अमेरिका भरोसा कर सकता है और न ही तालिबान या अफ़ग़ानिस्तान सरकार. वहीं पाकिस्तानी तालिबान देश में लगातार आत्मघाती हमले कर रहे हैं. साथ में देश के कई क्षेत्रों में गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई है. कहने का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान की विदेश नीति बुरी तरह से नाकाम रही है. इसलिए अब वह फूंक-फूंक कर क़दम उठा रहा है. पाकिस्तान का इस मामले से पीछे हटने की और बलुचिस्तान प्रान्त में चल रहा बलूच राष्ट्रवादीयों का अलगाववादी आन्दोलन भी है. पाकिस्तान पहले भी भारत और अफगानिस्तान पर बलुचिस्तान प्रान्त में अलगाववादियों के समर्थन का आरोप लगाता रहा है. अब चूंकि ईरान से बलुचिस्तान की सीमा मिलती है और ईरान शिया हौती विद्रोहियों का समर्थन कर रहा है, लिहाज़ा पाकिस्तान ईरान को नाराज़ करने का जोखिम नहीं उठा सकता. साथ में देश में शियाओं की आबादी तकरीबन 20 फिसद के आसपास है. देश में पहले से ही आए दिन शियाओं पर हमले होते रहते हैं. लिहाज़ा, एक बार फिर पाकिस्तान किसी और देश की समस्या की वजह से मैदान-ए-जंग बन सकता है. दरअसल, पाकिस्तान मध्य एशिया के वर्चस्व की लड़ाई में बुरी तरह से उलझा हुआ नज़र आ रहा है. वह न तो किसी का पक्ष ले सकता है और न ही तटस्थ ही रह सकता है. मज़े की बात यह है कि यह समस्या उसके द्वारा पैदा नहीं की गई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सऊदी अरब में नेतृत्व परिवर्तन

विकास की तलाश या सत्ता की भूख

वलीम अहमद

हाल के दिनों में सऊदी सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है. यह ऐसा परिवर्तन है, जिसकी अपेक्षा किसी को नहीं थी. शाह फैसल के बेटे सऊद फैसल, जो 40 वर्षों से विदेश मंत्री थे और दुनिया भर में उन्हें सऊदी अरब के लिए आईकॉन की तरह देखा जाता था, उन्हें हटाकर आदिल अलजबीर को यह पद दे दिया गया है. आदिल अलजबीर अमेरिका में सऊदी राजदूत के रूप में कार्यरत थे. दूसरा बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि अब्दुल अज़ीज़ के अंतिम बेटे और उत्तराधिकारी 70 वर्षीय मुकरिन बिन अब्दुल अज़ीज़ को उनके पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह 55 वर्षीय मोहम्मद बिन नाइफ़ को उत्तराधिकारी और वर्तमान बादशाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के 30 वर्षीय बेटे मोहम्मद बिन सलमान को उत्तराधिकारी बनाया गया है. यहां तक कि पेट्रोलियम मंत्री हशाम नज़र को हटाकर उनकी जगह अली बिन इब्राहिम अलनइमी को नया तेल मंत्री बनाया गया है. इसके अलावा भी कुछ परिवर्तन हुए हैं. उदाहरणस्वरूप अब्दुल्लाह के दो बेटों को उनके पद से हटा दिया गया है. इनमें से एक मक्का के गवर्नर शहज़ादा मशअल हैं और दूसरे रियाज़ के गवर्नर शहज़ादा तुर्की हैं.

जनवरी 2015 को सुल्तान की हैसियत से पद संभालने के बाद सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सरकार में कई बड़े परिवर्तन किए हैं. सऊदी इतिहास में इससे पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर परिवर्तन नहीं हुए थे. सऊदी अरब की परंपरा रही है कि जब भी कोई नया सुल्तान बनता है तो अपने पहले सुल्तान की परंपरा से अलग नहीं हटते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सलमान के आते ही केवल चार माह के अन्दर देश के महत्वपूर्ण पदों पर इतने बड़े स्तर पर परिवर्तन कर दिए गए. क्या इसका कारण देश की व्यवस्था को बेहतर करना, शाही परिवार में जारी विवाद को ख़त्म करना या कुछ और है?

संभव है कि इस परिवर्तन के पीछे सुल्तान का मक़सद देश की व्यवस्था को बेहतर करना हो या फिर यह मक़सद हो कि सभी महत्वपूर्ण विभागों पर अपना नियंत्रण मज़बूत करके आंतरिक व बाहरी फूट पर नियंत्रण पाया जाए. दरअसल, सऊदी अरब को इस समय कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना है. एक ओर पूरा मध्य पूर्व गृहयुद्ध की परिस्थितियों से दो-चार है. स्वयं सऊदी अरब यमन के साथ जंग में फंसा हुआ है और दूसरी ओर वैश्विक मंडी में तेल की घटती कीमत ने इसकी अर्थव्यवस्था को लड़खड़ा दिया है. इसके अलावा देश में पढ़े-लिखे नौजवानों की एक बड़ी खेप रोज़गार के इंतजार में है. इनके लिए रोज़गार के अवसर पैदा करना एक बड़ी समस्या है. ये सभी परिस्थितियां ऐसी हैं, जिसको

नई नस्ल के टेक्नोक्रेट ही सही तरीक़े से अंजाम दे सकते हैं. यही वजह है कि शाह सलमान में बादशाहत के इस सिलसिले को अब्दुल अज़ीज़ के बेटों से, जो कि बूढ़े हो चुके हैं और सबसे छोटे बेटे मुक़रिन हैं, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, उनके पोतों में यानी दूसरी नस्ल में हस्तांतरित करने का आग़ाज़ कर दिया है, लेकिन इस हस्तांतरण में जो ख़ास बात है, वह यह है कि शाह सलमान ने देश के सभी महत्वपूर्ण पदों पर अपने सगे रिश्तेदारों को नियुक्त करके अन्य शहज़ादों में निराशा पैदा कर दी है. यह स्थिति आने वाले दिनों में समस्याएं खड़ी कर सकती है.

दरअसल, शहज़ादों की ओर से लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि देश की व्यवस्था अब अब्दुल अज़ीज़ के बेटों के बजाए पोतों में हस्तांतरित होना चाहिए. इसी मांग को लेकर मार्च 2014 में इन शहज़ादों पर आधारित एक कमेटी बेअत कॉन्सिल गठित की गई थी, लेकिन सभी शहज़ादों के बीच किसी एक नाम पर सहमति न होने की वजह से नतीजा सामने नहीं आ सका. सर्वसम्मति न होने का कारण यह रहा कि शाही परिवार के शहज़ादे दो समूहों में बंटे हुए थे. एक अब्दुल्लाह समूह और दूसरा सुदैरी ग्रुप. अब्दुल्लाह समूह 61 वर्षीय मतअब अब्दुल्लाह के समर्थन में था, तो दूसरे समूह का समर्थन 55 वर्षीय मोहम्मद बिन नाईफ़ को प्राप्त था. इनमें बिन नाईफ़ का वॉशिंगटन से गहरा संबंध है, जबकि मतअब को सऊदी अरब के महत्वपूर्ण और संवेदनशील पदों पर काम करने का अनुभव है.

वर्तमान सुल्तान सलमान इस बात को महसूस कर रहे थे कि जब सऊदी की सत्ता दूसरी नस्ल में हस्तांतरित होगी तो इन दोनों समूहों में कड़े मतभेद उत्पन्न होंगे और इससे देश को नुक़सान पहुंचेगा. इस मतभेद को ख़त्म करने का बेहतर तरीक़ा यही है कि वह स्वयं ही देश का भविष्य किसी एक समूह के हवाले करने का निर्णय करें. चूंकि मौजूदा सुल्तान का संबंध भी सुदैरी समूह से है. लिहाज़ा, उनका झुकाव इसी समूह की ओर था और इसी झुकाव के कारण उन्होंने दूसरे समूह का ज़ोर कम करने के लिए पूर्व सुल्तान अब्दुल्लाह के दो बेटों को रियाज़ और मक्का की गवर्नरी से हटा दिया. इसके बाद उन्होंने अपने सगे बड़े भाई नाईफ़ के बेटे को देश का अगला बादशाह और उनका उप सुल्तान अपने 30 वर्षीय बेटे मोहम्मद बिन सलमान को नियुक्त करके देश की बागडोर को सुदैरी परिवार के लिए सुरक्षित कर दिया.

सुल्तान सलमान के इस नये परिवर्तन से खुले रूप से ऐसा लगता है कि सुल्तान सलमान ने देश की बागडोर अपने भतीजे और बेटे को देकर भविष्य का शासक सुदैरी समूह को सौंप दिया है, लेकिन थोड़ी और गहराई में जाएं तो अनुमान होगा कि हालिया सुल्तान ने अपने इस अमल से सऊदी अरब सरकार को सुदैरी समूह नहीं, बल्कि अपनी औलाद में हस्तांतरित करने का रास्ता साफ़ किया है. वह इस प्रकार कि सऊदी परंपरा के अनुसार, उनके बाद मोहम्मद बिन नाईफ़ बादशाह होंगे. नवनियुक्त सुल्तान मोहम्मद बिन नाईफ़ को कोई पुत्र नहीं है, उनकी केवल दो बेटियां हैं और आले सऊद जैसे बेहद रूढ़ीवादी कल्चर में ज़ाहिर है इस बात की कोई संभावना नहीं है कि निकट भविष्य में कोई महिला सऊदी अरब की बागडोर संभालेगी. अर्थात् इसी बुनियाद पर सऊदी के सुल्तान संतुष्ट होंगे कि नाईफ़ के बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन सुलेमान, जिसको उप सुल्तान नियुक्त किया गया है, के रास्ते में मोहम्मद बिन नाईफ़ कोई रुकावट खड़ी नहीं करेंगे और इस प्रकार से सऊदी अरब की सरकार शाह सलमान की संतानों में सीमित हो जाएगी.

यह भी हो सकता है कि इन महत्वपूर्ण पदों में फेरबदल सुरक्षा की दृष्टि से की गई हो. मुकरिन बिन अब्दुल अज़ीज़ देश के संवेदनशील पदों पर बैठे थे. संयोग से मुकरिन की माता बराका का संबंध यमन से है और मुक़रिन की परवरिश यमनी माहौल में हुई है. इस समय सऊदी अरब और यमन के बीच जंग जारी है. ऐसी स्थिति में मुक़रिन यमन के प्रति नरम रवैया रख सकते थे. ज़ाहिर है युद्ध परिस्थितियों में यह बात ठीक नहीं है. शाह सलमान कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उनको पद से हटाकर उनकी जगह बिन नाईफ़ को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है. जहां तक सऊद फैसल की बात है, तो उनको पदच्यूत करने का कारण भी यही हो सकता है कि जब यमन के ख़िलाफ़ युद्ध शुरू करने की बात कही जा रही तो इस समय सैन्य कार्रवाई का विरोध करने वाले अन्य शहज़ादों में सऊद फैसल भी शामिल थे. अब जबकि सऊदी अरब यमन में हवाई हमले कर रहा है तो वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को महत्वपूर्ण पदों पर बनाए रखना नहीं चाहते हैं, जो इस हमले के ख़िलाफ़ रहा है.

बहरहाल, इस परिवर्तन ने सऊदी अरब की आंतरिक राजनीति को अधिक उलझाकर रख दिया है. एक ओर शाह सलमान के अपने सगे भाई अहमद बिन अब्दुल अज़ीज़ नाराज़ हैं. मुक़रिन के पद से हटाये जाने के बाद उन्हें विश्वास हो चुका है कि उन्हें तख़्त की ओर जाने वाले रास्ते से हटाकर किनारे कर दिया गया है. दूसरी ओर शाह अब्दुल्लाह के बेटे मोतअब शाही परिवार की सुरक्षा करने वाली सेना नैशनल गार्ड्स के मुखिया नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया है. उनके साथ अब्दुल्लाह समूह के शहज़ादों की बड़ी संख्या है. यह आंतरिक रूप से इस पर नियुक्ति के विरोधी हैं और इसकी वजह से शाही परिवार में मतभेद की जो चिंगारी दबी हुई है, वह कभी भी भड़क सकती है. शाही परिवार के अन्य बुज़ुर्गों ने भी नाक-भौं चढ़ा रखी है कि अचानक शहज़ादों की दूसरी नस्ल को तख़्त की सीढ़ी पर क्यों चढ़ाना शुरू कर दिया गया है. सुदैरी समूह कभी सात सगे भाइयों का एक संयुक्त समूह होता था और अब इस समूह में भी आंतरिक मतभेद पैदा हो चुका है. क्यों मोहम्मद को उप सुल्तान बनाए जाने के बाद सुदैरी के अन्य शहज़ादों को भी विश्वास हो गया है कि अब देश की सत्ता कभी भी वह या उनकी संतानों के हिस्से में नहीं आएगी. इन बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सऊदी अरब न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि आंतरिक स्तर पर भी युद्ध स्थिति से दो-चार है और नये परिवर्तन ने इस समस्या को और भी उलझाकर रख दिया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय के बीच केदारनाथ धाम भगवान शिव के सर्वश्रेष्ठ ज्योर्तिलिंगों में एक बाबा केदारनाथ का अतिप्राचीन मंदिर है. पूरी दुनिया में बद्रीनाथ और केदारनाथ दो पावन तीर्थ स्थान विख्यात है, दोनों के दर्शन का महत्व बड़ा है. ऐसी मान्यता है कि जो भक्त केदारनाथ के दर्शन के बिना नारायण के मोक्षधाम बद्रीनाथ जी का दर्शन करता है उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती. शिव के वृषभ रूप धारण करने के बाद भी पाप से मुक्ति पाने के लिए पाडवों ने शिव के दर्शन का मोह नहीं त्यागा.

साईं समस्त प्राणियों में विराजमान हैं

चौथी दुनिया ब्यूरो

माया के कारण जीव के हृदय में घोर अंधकार भरा रहता है. घने अंधकार के कारण जीव माया के बंधन की गांठ सुलझाने में अक्षम सिद्ध होता है. बंधन की गांठ खोलने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है. प्रकाश पाने के लिए हमें साई के चरणों में जाना चाहिए जो हमें इस माया से मुक्ति दिलाते हैं.

परम लक्ष्य की सिद्धि के लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान या भक्ति? गोस्वामी तुलसी दास का स्पष्ट मत है कि ज्ञान मार्ग की तुलना में भक्ति मार्ग अधिक सरल है, ऋजु है. अत: सामान्य साधक के लिए यही मार्ग वरेण्य है. मानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, जीव ईश्वर का ही निर्मल है, परंतु माया के बंधन में फंस कर उसकी गति पिंजरे में पड़े तोते और मदारी की डोर से बंधे बंदर जैसी हो गई है. अब प्रश्न यह है कि जीव माया के बंधन से छूटे कैसे? इसके लिए दो मार्ग हैं, ज्ञान और भक्ति. ज्ञान मार्ग अति दुर्गम एवं दुरुह है, भक्ति मार्ग अति सुगम है. ज्ञान और भक्ति मार्ग का अंतर स्पष्ट करने के लिए गोस्वामी जी एक लंबा रूपक बांधते हैं. माया के कारण जीव के हृदय में घोर अंधकार भरा रहता है. घने अंधकार के कारण जीव माया के बंधन की गांठ सुलझाने में अक्षम सिद्ध होता है. बंधन की गांठ खोलने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है. प्रकाश पाने के लिए हमें साई के चरणों में जाना चाहिए जो हमें इस माया से मुक्ति दिलाते हैं.

बाबा ने अपनी जीवन–रेखा पार करने का एक बार प्रयास किया था. मार्गशीर्ष को पूर्णिमा के दिन बाबा को कोदमा से अधिक पीड़ा हुई और इस व्याधि से छुटकारा पाने के लिये उन्होंने अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर समाधि लगाने का विचार किया. अतएव उन्होंने भगत म्हा–लसापति से कहा कि तुम मेरे शरीर की तीन दिन तक रक्षा करना और यदि मैं वापस लौट आया तो ठीक ही है, नहीं तो उस स्थान (एक स्थान को इंगित करते हुए) पर मी समाधि बना देना और दो ध्वजायें चिन्ह स्वरुप फहरा देना. ऐसा कहकर बाबा रात में लगभग दस बजे जमीन पर लेट गये. उनका श्वासोच्छवास बन्द हो गया और ऐसा दिखाई देने लगा कि जैसे उनके शरीर में प्राण ही न हो. सभी लोग, जिनमें ग्रामवासी भी थे, वहां एकत्रित हुए और शरीर परीक्षण के पश्चात शरीर को उनके द्वारा बताये हुए स्थान पर समाधिस्थ कर देने का निश्चय करने लगे. परन्तु भगत म्हालसापति ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनके शरीर को अपनी गोद में रखकर वे तीन दिन तक उसकी रक्षा करते रहे. तीन दिन

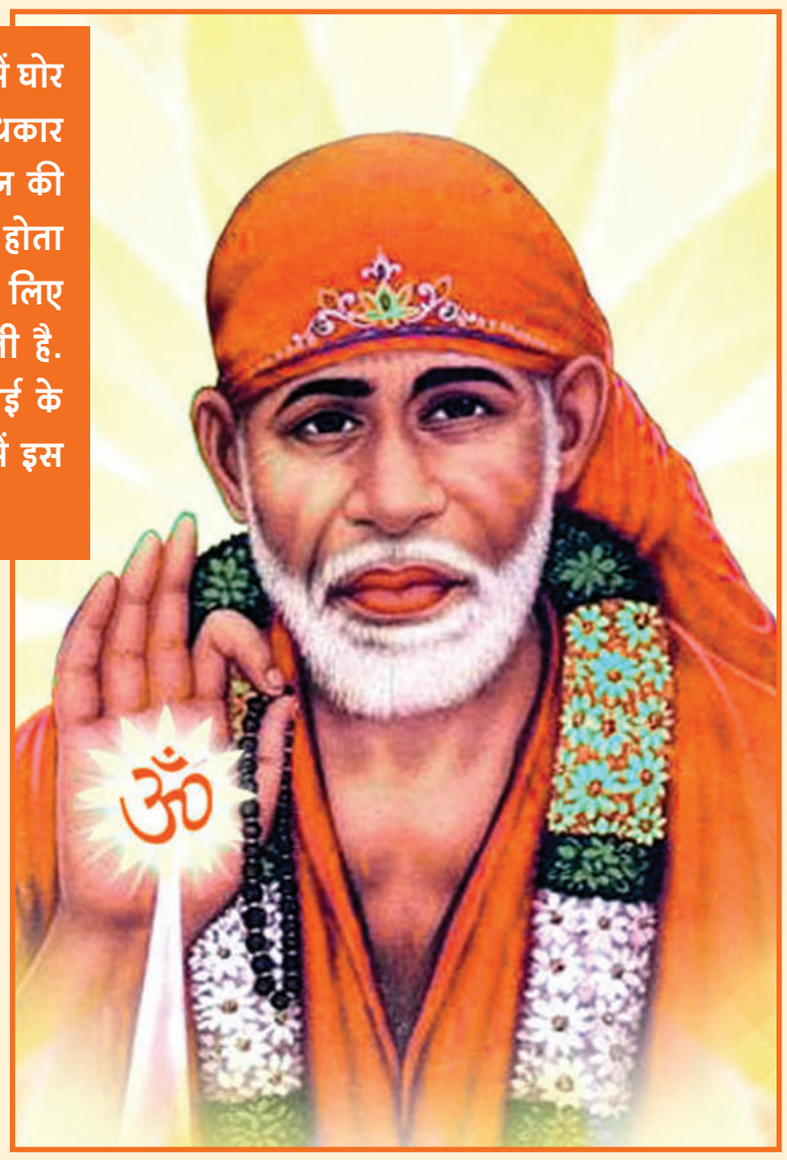

व्यतीत होने पर रात को लगभग तीन बजे प्राण लौटने के चिन्ह दिखलाई पड़ने लगे. श्वासोच्छवास पुन: चालू हो गया और उनके अंग–प्रत्यंग हिलने लगे. उन्होंने नेत्र खोल दिये और करवट लेते हुए वे पुन: चेतना में आ गये.

इस प्रसंग तथा अन्य प्रसंगों पर दृष्टिपात कर अब हम यह पाठकों पर छोड़ते है कि वे ही इसका निश्चय करें कि क्या बाबा अन्य लोगों की भांति ही साढ़े तीन हाथ लम्बे एक देहधारी मानव थे, जिस देह को उन्होंने कुछ वर्षों तक धारण करने के पश्चात छोड़ दिया, या वे स्वयं आत्मज्योतिस्वरुप थे, पंच महाभूतों से शरीर निर्मित होने के कारण उसका नाश और अन्त तो सुनिश्चित है, परन्तु जो (आत्मा) अन्त:करण में है, वही यथार्थ में सत्य है. उसका न रुप है, न अंत है और न नाश. यही शुद्ध चैतन्य घन या ब्रह्म–इन्द्रियों और मन पर शासन और नियंत्रण रखने वाला जो तत्व है, वही साई हैं, जो संसार के समस्त प्राणियों में विघमान हैं और जो सर्वव्यापी हैं. अपना अवतार–कार्य पूर्ण करने के लिये ही उन्होंने देह–धारण किया था और वह कार्यपूर्ण होने पर उन्होंने उसे त्याग कर पुन: अपना शाश्वत और अन्नत स्वरुप धारण कर लिया. श्री दत्तात्रेय के पूर्ण अवतार–गाणगापुर के श्रीनृसिंह सरस्वती के समान श्री साई भी सदैव वर्तमान हैं. उनका निर्वाण तो एक औपचारिक बात है. वे जड़ और चेतन सभी पदार्थों में व्याप्त हैं तथा सर्व भूतों के अन्त:करण के संचालक और नियंत्रणकर्ता है. इसका अभी भी अनुभव किया जा सकता है और अनेकों के अनुभव में आ भी चुका है, जो अनन्य भाव से उनके शरणागत हो चुके है और जो पूर्ण अंत:करण से उनके उपासक है.

यघपि बाबा का स्वरुप अब देखने को नहीं मिल सकता है, फिर भी यदि हमशिरडी को जाएं तो हमें वहां उनका जीवित–सदृश चित्र मस्जिद(द्वारकामाई) को शोभायमान करते हुए अब भी देखने में आयेगा. यह चित्र बाबा के एक प्रसिद्ध भक्त–कलाकार श्री. शामराव जयकर ने बनाया था. एक कल्पनाशील और भक्त दर्शक को यह चित्र अभी भी बाबा के दर्शन के समान ही सन्तोष और सुख पहुंचाता है. बाबा अब देह में स्थित नहीं है, परन्तु वे सर्वभूतों में व्याप्त है और भक्तों का कल्याण पूर्ववत ही करते रहे हैं, करते रहेंगे, जैसा कि वे सदेह रहकर किया करते थे. बाबा सन्तों के समान अमर है, चाहे वे नरदेह धारण कर ले, जो कि एक आवरण मात्र है, परन्तु वे तो स्वयं भगवान श्री हरि हैं, जो समय–समय पर भूतल पर अवतीर्ण होते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

साईं के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दु:ख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

राह से भटक गई है आप

आम आदमी पार्टी एक अराजक पार्टी बनकर रह गई है. आम आदमी पार्टी के पास एक सुनहरा मौका था जिसे उसने गंवा दिया. दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी से योगेन्द्र यादव, प्रशांत भूषण समेत अनेक उन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के कामकाज और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ उनके गलत रवैये को लेकर आवाज उठाई. केजरीवाल ने अपने खिलाफ बोलने वाले सभी लोगों को धीरे-धीरे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया. केजरीवाल एक तानाशाह हैं इसमें कोई दो राय नहीं है और उनकी पार्टी भी बाकी पार्टियों से अलग नहीं है. आम आदमी पार्टी के जंतर-मंतर पर किसान रैली में गजेन्द्र नामक किसान की पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या करना, कुमार विश्वास पर एक महिला के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगना और केजरीवाल के कानून मंत्री जितेन्द्र सिंह तोमर की फर्जी डिग्री का मामला पार्टी की गले की फांस बन गया है. आम आदमी पार्टी की सच्चाई जनता के सामने आ गई है और यह पार्टी भी एक व्यक्ति पर आधारित है और बाकी पार्टियों से अलग नहीं है.

-प्रभु नारायण सिंह, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

आजादी का दुरुपयोग

सुप्रीमकोर्ट ने अपने एतिहासिक निर्णय में धारा 66ए को रद्द कर दिया. इस लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की एक खुशी देखी गई, क्योंकि अब कोई अपने विचारों को निडर होकर सोशल मीडिया पर रख सकता है. लेकिन इससे सोशल साइट्स पर लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और अश्लील सामग्री शेयर करने का खतरा बढ़ गया है. जो विश्वकप के दौरान देखने को मिली. भारतीय टीम की सेमीफाइनल में हार के बाद अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के बारे में सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणी की गई. इन्टरनेट यूजर को मिली अभिव्यक्ति की आजादी के साथ अपने कर्तव्यों-दायित्वों का भी हमें बोध होना चाहिए.

-सत्य प्रकाश (शिक्षक), *लखीमपुर, उत्तर प्रदेश.*

कुछ सवालों के जवाब जरूरी हैं

कवर स्टोरी-कोयला खदानों की नीलामी कालिख ही कालिख(27 अप्रैल-03 मई 2015) का अंक पढ़ा. काफी प्रभावित किया. लेखक शशि शेखर ने सही कहा है कि कोयले की कालिख कोई कितना भी झुड़ा ले, लेकिन कहीं न कहीं दाग रह ही जाता है. कोयला घोटला यूपीए सरकार के दौरान का सबसे घोटला था. यूपीए सरकार के दौरान तो टूजी से लकर सीडब्ल्यूजी तक कई सारे घोटाले हुए, लेकिन कोयला घोटला एक ऐसा घोटला है जिसके दाग के छीटे सीधे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक पहुंचे. कोयला घोटला चौथी दुनिया ने सबसे पहले उजागर किया था, उसने बताया था कि कोयला घोटला 26 लाख करोड़ का है. मोदी सरकार ने इस बार हुए कोयला खदानों की नीलामी से करोड़ो रुपये मिलने की बात कह रही है और यह सही भी है, लेकिन चौथी दुनिया ने एनडीए सरकार के द्वारा किए कोयला खदान नीलामी को लेकर जो सवाल उठाएं हैं उसका जवाब सरकार को देना चाहिए.

-मनोज कुमार सिंह, *द्वारका, नई दिल्ली.*

जवाबदेह बनाने की जरूरत

जब तोप मुकाबिल हो-यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है (27 अप्रैल-03 मई 2015) का अंक पढ़ा. काफी विचारोत्तेजक है. संतोष भारतीय की इस बात से मैं सहमत हूं कि अब पुलिस तंत्र और न्याय व्यवस्था के बारे में बातीचीत की जानी चाहिए. क्योंकि पुलिस और न्याय व्यवस्था दोनों को जवाबदेह बनाने की जरुरत है. पुलिस के जवाबदेह न होने के कारण ही पुलिस बिना जांच के निर्दोषों को भी पकड़ कर जेल में डाल देती है. पुलिस के कई सारे ऐसे कांड हैं जिससे पुलिस के जवाबदेह न होने कारण, उसने निर्दोषों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है. कई ऐसे एनकाउंटर हैं जो गलत एनकाउंटर थे और उस एनकाउंटर में मारे जाने वाला निर्दोष. हाशिमपुरा कांड को देखे तो उसमें कई निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया और मौत के घाट उतारने वालों को आज तक कोई सजा नहीं हुई. कई सारे ऐसे मामले में हैं जिसमें पुलिस की स्थिति संदिग्ध रही है. इसलिए पुलिस और न्याय व्यवस्था को जवाबदेही बनाने की जरूरत है.

-रवि प्रकाश श्रीवास्तव, *वाराणसी, उत्तर प्रदेश.*

लड़की और तितली

रंग-बिरंगी तितलियां.
उड़ती फिरती इस फूल से उस फूल पर.
प्यारी- प्यारी लड़कियां.
चहकती फिरती इस घर से उस घर तक
लग गई है दोनों को किसकी नजर.
जाने क्यों है दुनिया इससे बेखबर.
तितलियों का वो रंगी नजारा भी दिखता है कम.
और लडकियों के क कम होने का है गम.
क्या कसूर है छोटी प्यारी तितलियों का.
गोद में अठ्ठखेलियां करती मासूम बच्चियों का.
क्यों नहीं लड़कियां घूम सकती है निर्भय होकर.
क्यों नहीं तितलियां उड़ सकती हैं बेखबर होकर.
निकलती हैं लड़कियां जब खलने को घर से.
सताता है इक भय अनहोनी का.
तितली भी उड़ जाती है, छोड़ फूलों का रस.
हल्की सी आहट पर.

-बबीता कुमारी, *समस्तीपुर, बिहार.*

अलौकिक समाचार पत्र

चौथी दुनिया समाचार पत्र एक ऐसा समाचार पत्र है, जिसे हर तबके लोग चाहे वे अमीर हों या गरीब, सब पढ़ते हैं. यह केवल आम लोगों का समाचार पत्र नहीं है. बल्कि इसमें प्रकाशित खबरें बड़े-बड़ों को सोचने और पढ़ने पर मजबूर कर देती हैं.■

- संजय कुमार झा, *दरभंगा, बिहार.*

तबाही में बचे रहे शिवधाम

रेणू शर्मा

विश्वनाथ जो शिव तत्व के द्योतक हैं, उन्हीं के एक रूप का भारत में और दूसरे रूप का नेपाल में स्थित है, जिसके कारण आदिकाल से भारत का नेपाल से मौलिक सम्बन्ध है. जिनके सन्दर्भ में प्रचलित है भावी मेटी सकै त्रिपुरारी. भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय के बीच केदारनाथ धाम भगवान शिव के सर्वश्रेष्ठ ज्योर्तिलिंगों में एक बाबा केदारनाथ का अतिप्राचीन मंदिर है. पूरी दुनिया में बद्रीनाथ और केदारनाथ दो पावन तीर्थ स्थान विख्यात है, दोनों के दर्शन का महत्व बड़ा है. ऐसी मान्यता है कि जो भक्त केदारनाथ के दर्शन के बिना नारायण के मोक्षधाम बद्रीनाथ जी का दर्शन करता है उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती. शिव के वृषभ रूप धारण करने के बाद भी पाप से मुक्ति पाने के लिए पाडवों ने शिव के दर्शन का मोह नहीं त्यागा. जब पांडवों ने भगवान शिव को वृषभ रूप में पहचान लिया, तो भीम वृषभ रूप में भगवान शिव को पकड़ना चाहा. लेकिन वृषभ रूपी भगवान शिव जमीन के अंदर अर्न्तध्यान होने लगे. भीम ने वृषभ रूपी भगवान के त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया. भगवान शिव पाण्डवों की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन दिया. भगवान शिव ने पांडवों को सभी पापों से मुक्ति का वरदान दिया. ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के वृषभ रूप धड़ के ऊपर का भाग पड़ोस के हिमालयी राज्य नेपाल के काठमाण्डू में प्रकट हुआ. जो पशुपति नाथ के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है. नेपाल की राजधानी काठमांडू के तीन किलोमीटर उत्तर–पश्चिम में देवपाटन गांव में बागमती पावन नदी के तट पर यह शिववालय (पशुपतिनाथ का मंदिर) स्थित है. पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के श्रेष्ठ पावन मंदिरों में माना जाता है. नेपाल के 15वीं शदी के राजा प्रताप मल्ल से शुरू हुई परम्परा है कि मंदिर के चार पुजारी भट्ट ब्राह्मण और एक मुख्यपुजारी भी दक्षिण भारत के भट्ट ब्राह्मण परिवार से रखे जाते हैं. मन्दिर नेपाल का, पुजारी हिन्दुस्तान का, भारत नेपाल के मजबूत रिस्ते को दर्शाता है.

जिस तरह केदारनाथ और पशुपतिनाथ दोनों का रिस्ता है. इसी तरह दोनो धामों में आयी दैवी आपदाओं ने शिव के रौद्ररूप का भी एक स्वरूप भी सबके सामने आया है. केदारनाथ में आई हिमालयी सुनामी एवं नेपाल में आया भीषण भूकंप में हुई तबाही और मौत ने मानव को शिव के सत्यम, शिवम, सुन्दरम स्वरूप से हट कर रौद्ररूप का परिचय दे दिया है. दोनों धामों में आई तबाही आई और सब कुछ नष्ट हो गया. लेकिन दोनों धाम के शिववालय पूरी तरह से सुरक्षित रहे इससे एक बात साफ हो गई कि विश्वनाथ शिव के धामों में उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता. शिव को प्रकृति के देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है, प्रकृति को सजाने, सवारने एवं विनिष्ट करने का दायित्व सनातन मत के अनुसार शिव ही निभाते हैं. जब स्वर्ग से गंगा धरती पर आई और उन्होंने तबाही मचाना शुरू किया तो देवताओं ने देवों के देव महादेव शिव ने विश्व के कल्याण के लिए गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और उसके बाद शिव के जटाओं से लोककल्याण के लिए गंगा का अवतरण हुआ.■

feedback@chauthiduniya.com

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

बौद्धिक बेईमानी से बढ़ी कट्टरता

अनंत विजय

इस्लाम धर्म को बहुत वैज्ञानिक धर्म माना जाता रहा है. कुरान के आधार पर संचालित होने वाले इस धर्म में कट्टरता की कोई गुंजाइश इसकी शुरुआत में नहीं थी, लेकिन कालांतर में कुरान की व्याख्या करने वाले मौलवियों ने इस धर्म को कट्टरता के गड्ढे में धकेल दिया. आज सही या ग़लत, लेकिन इस्लाम को लेकर पूरे विश्व में धारणा बन गई है कि यह बेहद कट्टर धर्म है और इसमें न तो सहिष्णुता है और न सहनशीलता. यह बहुत ही ख़तरनाक बात है और प्रवृत्ति भी. मशहूर इस्लामिक चिंतक असगर अली इंजीनियर ने अपनी किताब- इस्लाम का जन्म और विकास में लिखा था कि दुनिया भर के मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने आधुनिक समाज विज्ञानों की रौशनी में आरंभिक इस्लाम के विश्लेषण के आवश्यक, मगर कठिन कार्य को अनदेखा किया. असगर अली इंजीनियर की बात में यह भी जोड़ा जा सकता है कि जब चंद कठमुल्ले कुरान की ग़लत व्याख्या कर रहे थे, तो प्रगतिशील सोच के मुसलमान उनके ख़िलाफ़ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और उनकी खामोशी से इस्लामिक कट्टकपंथ को बढ़ावा मिला. हौसले तो बुलंद उनके उन मौलवियों ने भी किए, जो फतवे के नाम पर कुरान की आयतों की ग़लत व्याख्या करते रहे. फतवे की इस राजनीति ने सबसे ज़्यादा नुक़सान इस्लाम की छवि को पहुंचाया. मुस्लिम प्रगतिशील तबकों के अलावा अपनी प्रगतिशीलता का तमगा गले में लटकाए घूमने वाले और बात-बात पर धर्मनिरपेक्षता की दुंदुभि बजाने वाले लोग भी इस्लाम में बढ़ते कट्टरवाद पर खामोश रहे. हिंदू कट्टरतावाद, अव्वल तो यह शब्द ही ग़लत प्रचलित किया गया, के ख़िलाफ़ जो बयानवीर सामने आते थे, वे ऊलजुलूल के फतवों के ख़िलाफ़ खामोशी ओढ़ लेते थे. इसकी सबसे बड़ी मिसाल तस्लीमा नसरीन हैं. उन्हें पश्चिम बंगाल की प्रगतिशील सरकार ने ही सूबे से बाहर किया था. उस वक्त भी प्रगतिशील लेखकों ने आश्चर्यजनक ढंग से चुप्पी साध ली थी. जबकि होना यह चाहिए था कि धर्मनिरपेक्षता के झंडाबरदार हर धर्म की बुराइयों पर समान रूप से विरोध जताते. चुनिंदा विरोध की वजह से धीरे-धीरे उनकी विश्वसनीयता ख़त्म होती चली गई. इस तरह से अगर हम देखें, तो प्रगतिशील जमात ने ही धर्मनिरपेक्षता को सबसे ज़्यादा नुक़सान पहुंचाया.

एक साथ लगभग एक ही तरह की दो बातें सामने आई हैं. एक तरफ़ तो भारत सरकार ने वैवाहिक बलात्कार को क़ानूनी जामा पहनाने से इंकार कर दिया. सरकार का तर्क है कि भारत में विवाह एक पवित्र संस्था है, लिहाजा वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा यहां लागू नहीं हो सकती है. राज्यसभा में भारत सरकार की तरफ़ से गृह राज्य मंत्री ने अपने लिखित बयान में कहा कि वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझा जाता है, अनेक कारणों से भारतीय परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त रूप से लागू नहीं की जा सकती. इन कारणों में शिक्षा-निरक्षरता का स्तर, अनेक रीति-रिवाज एवं मूल्य, धार्मिक आस्थाएं और विवाह को संस्कार मानने की समाज की सोच आदि शामिल हैं. भारत सरकार द्वारा संसद में दिए गए इस बयान पर पूरा का पूरा तथाकथित प्रगतिशील खेमा तलबारबाजी में जुट गया. दुनिया के तमाम देशों में लागू वैवाहिक बलात्कार के क़ानून की दुहाई दी जाने लगी. स्त्रियों के अधिकारों की बात पर कोलाहल होने लगा, स्त्री देह की स्वतंत्रता की दुहाई दी जाने लगी, आदि-आदि. ऐसा लगा कि आसमान सिर पर उठा लिया गया हो. भारत सरकार को दकियानूसी सोच वाली से लेकर उसके इस जवाब को पुरातनपंथी तक करार दे दिया गया. कथित बुद्धिजीवियों में इस बात को लेकर होड़ मच गई कि कौन भारत सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा लानत-मलामत कर सकता है. संभव है कि उनके तर्क ठीक हों. यह भी संभव है कि देश को अब इस तरह के क़ानून की ज़रूरत हो. इस लेख का मकसद ऐसे क़ानून की ज़रूरत और उसकी बारीकियों के बारे में बात करना नहीं है, बल्कि उन बुद्धिजीवियों को आईना दिखाना है, जो विरोध के लिए धर्म विशेष का चुनाव करते हैं.

अब एक दूसरा वाकया देखिए, जो लगभग इसी तरह का है. मलेशिया के एक मौलवी ने फतवा जारी करके कहा कि औरतें अपने पति को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कभी भी मना नहीं कर सकती हैं, चाहे वे ऊंट पर ही क्यों न बैठी हों. उन्होंने भी वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा को यूरोपियन अवधारणा करार दिया. यह फतवा धर्म की आड़ में जारी करते हुए कहा गया कि महिला शारीरिक संबंध से सिर्फ़ तब इंकार कर सकती है, जब वह रजस्वला हो, बहुत बीमार हो. मलेशिया के पेराक मुफ्ती जकारिया ने साफ़ शब्दों में कहा कि मुस्लिम महिला शारीरिक संबंध बनाने से इंकार का अधिकार उसी वक्त खो देती है, जब उसका पिता उसे उसके पति के हाथों सौंप देता है. उन्होंने साफ़ किया कि मुस्लिम महिलाओं के पास पति को मना करने का हक़ ही नहीं है. अपने इस फतवे के समर्थन में वह धर्म की सबसे बड़ी ढाल इस्तेमाल करते हैं. अन्य मुस्लिम विद्वानों का कहना है कि इस्लाम में बलात्कार की अवधारणा शादी से बाहर की है, बल्कि वे तो यहां तक कहते हैं कि बलात्कार कुंवारी लड़कियों पर ही लागू होता है. उनका कहना है कि इस्लाम में अगर शारीरिक संबंध बनाने के पहले पत्नी की सहमति नहीं ली गई, तो यह बलात्कार नहीं है, बल्कि इसे बेरदब कहा जाता है, जिसका मतलब होता है असभ्य. इसे हराम नहीं माना जाता है, बल्कि इसे मकरूह कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ऐसा कार्य, जिसे नहीं किया जाना चाहिए था. इस फतवे के ख़िलाफ़ कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी. इसमें किसी को स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन नज़र नहीं आया. किसी भी कथित प्रगतिशील बौद्धिक ने इस पर सार्वजनिक तौर पर ऐतराज नहीं जताया. जबकि भारत सरकार के तर्क में सामाजिक स्थितियों से लेकर शिक्षा के स्तर तक की दुहाई दी गई थी, वहीं फतवे में तो फ़ैसला सुनाया गया था. पिता द्वारा पति तो सौंपे जाने की बात भी थी. इस वक्तव्य में किसी को भी महिला उपभोग की वस्तु नज़र नहीं आती है, कोई हाय-तौबा नहीं मचती है. अब इन दो लगभग समान स्थितियों पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं इन कथित प्रगतिशीलों को कठघरे में खड़ाकर देती हैं और उनकी मंशा पर संदेह करने का पुख्ता आधार प्रदान करती हैं.

इस्लाम में कट्टरपंथियों का बोलबाला बढ़ते चले जाने की बड़ी वजह यही है कि हम उस पर सख्त रूप से अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं. हाल में तो प्रतिक्रिया देने वालों को मौत की नींद सुला देने की वारदातें ज़्यादा होने लगी हैं. बांग्लादेश में ब्लॉगर की नृशंस हत्या, फिर पाकिस्तान में भी मानवाधिकार कार्यकर्ता सबीन का कत्ल आदि जैसी वारदातें धर्म की आड़ में की जा रही हैं.

दरअसल, इस्लाम में कट्टरपंथियों का बोलबाला बढ़ते चले जाने की बड़ी वजह यही है कि हम उस पर सख्त रूप से अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं. हाल में तो प्रतिक्रिया देने वालों को मौत की नींद सुला देने की वारदातें ज़्यादा होने लगी हैं. बांग्लादेश में ब्लॉगर की नृशंस हत्या, फिर पाकिस्तान में भी मानवाधिकार कार्यकर्ता सबीन का कत्ल आदि जैसी वारदातें धर्म की आड़ में की जा रही हैं. इस्लाम धर्म के नाम पर इस तरह की दहशत का खेल पूरी दुनिया में खेला जा रहा है. अभी हाल में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में एक प्रोफेसर पर जानलेवा हमला हुआ, क्योंकि उसने सलमान रुश्दी के पक्ष में लेक्चर दे दिया था. कुछ दिनों से श्रीलंका की तमिल लेखिका शर्मिला सईद निर्वासित जीवन बिताने को मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने एक तमिल भाषी रेडियो पर 2012 में इस बात की वकालत की थी कि श्रीलंका में वेश्यावृत्ति को क़ानूनी कर दिया जाए. उनके इस बयान को इस्लाम की कसौटी पर कसा गया और वहां उसे पाप की श्रेणी में पाया गया, क्योंकि इस्लाम में वेश्यावृत्ति को गुनाह माना गया है. उसके बाद शर्मिला सईद और उनके परिवार वालों को धमकियां मिलनी शुरू हो गईं. फेसबुक पर उनके नाम से प्रोफाइल बनाकर अश्लील और भद्दे कमेंट लिखे जाने लगे. ये प्रोफाइल रक्तबीज की तरह बढ़ते थे. शर्मिला और उनके पिता फेसबुक से कहकर एक को हटवाते थे, तो सौ और प्रोफाइल बन जाते थे. हर जगह यही तर्क दिया जाने लगा कि एक मुस्लिम महिला कैसे वेश्यावृत्ति की वकालत कर सकती है? शर्मिला के माफी मांगने के बाद भी मामला ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि कठमुल्ले उनसे बगैर शर्त माफी की मांग कर रहे थे, जबकि शर्मिला इसके लिए राजी नहीं थीं. यहां भी शर्मिला के समर्थन में इक्का-दुक्का बुद्धिजीवी ही आए और अपील जारी करने की औपचारिकता निभा गए.

अब अगर हम गहराई से इस पूरे परिदृश्य पर विचार करें, तो बहुत अंधेरा नज़र आता है. आलोचना पर हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति भारतीय मुस्लिम समाज पर भी हावी होने के लिए सिर पर तैयार खड़ी है. भारत में इस कट्टरपंथ को रोकने के लिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा, साथ ही समाज के हर तबके के बुद्धिजीवियों को समान भाव से कट्टर पंथ पर हल्ला बोलना होगा. अगर हमारे प्रगतिशीलों ने चुनिंदा विरोध की आदत से तौबा नहीं की, तो संभव है कि कट्टरपंथ और हिंसक हो जाए. वह स्थिति हमारे लोकतंत्र के साथ-साथ देश को भी कमजोर करेगी. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

ज़िंदगी को क़रीब से छूती ग़ज़लें

कुमार कृष्णन

समकालीन हिंदी ग़ज़लों की अभिव्यक्ति और उनकी संप्रेषणीयता हिंदी काव्य को एक नए मोड़ पर ले जाने और उसका एक नया भविष्य रचने के लिए अग्रसर है. आज हिंदी में जो ग़ज़लें लिखी जा रही हैं, उनका सीधा-सीधा सरोकार समकालीन आम जीवन से है. भाव, कल्पना एवं बुद्धि के साथ-साथ आक्रोश और ओज का भी मिला-जुला स्वर देखने को मिल जाता है. यही स्वर पठनीयता को अपनी ओर आकर्षित करता है. यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि पिछले वर्षों में हिंदी कविता पठनीयता के संकट से जूझती रही. इस संकट का मूल कारण है, कविता से छंद और लय का लोप हो जाना. भारत का सामाजिक परिवेश सदा-सदा से लयात्मक रहा है. जीवन, मृत्यु एवं उत्साह के क्षणों में भी लय की प्रधानता देखी गई है. ऐसी परिस्थिति में कविता से छंद का लोप होना एक त्रासद भविष्य की ओर संकेत करता है, लेकिन कविता की इस भविष्यहीनता को दुष्यंत कुमार की ग़ज़लों ने एक नया क्षितिज प्रदान किया और हिंदी काव्य साहित्य में ग़ज़ल का परिवेश हिंदी कविता के लिए सुखद संकेत रहा. धीरे-धीरे ग़ज़ल पाठकों के साथ सीधा संवाद करते हुए पूरी तरह घुल-मिल गई.

दुष्यंत कुमार के बाद हिंदी ग़ज़ल का जो आंदोलन चला, वह आज भी निरंतर जारी है, जिसकी एक कड़ी के रूप में डॉ. मृदुला झा की ग़ज़लों को भी हम भरोसे के साथ ले सकते हैं. हाल में ही उनका ग़ज़ल संग्रह-सतरंगी यादों का कारवां कुल 83 ग़ज़लों को साथ लेकर पाठकों के समक्ष आया है. संग्रह की सारी ग़ज़लें पढ़ने के बाद मुकम्मल तौर पर कहा जा सकता है कि मृदुला झा की ग़ज़लें समकालीन समाज की विसंगतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए पाठकों से सीधा-सीधा संवाद करती हैं. यही संवाद डॉ. मृदुला झा के समकालीन होने का प्रमाण देता है. बानगी देखिए:-

बेघरों को घर दिलाना चाहते हैं,
मुफलिसी उनकी मिटाना चाहते हैं.
दहशतों के दंश को जड़ से मिटाकर,
खुशनुमा हर पल बनाना चाहते हैं.

फूल ही फूल नहीं, जीवन में कांटे भी स्वीकार करें.
कितनी भी कड़वी हो, लेकिन सच्चाई से प्यार करें.

डॉ. मृदुला झा की ग़ज़लों में जीवन के यथार्थ की साफ़गोई भी है. आज का यथार्थ है कि हमारा समाज दिशाहीन होता जा रहा है. भोगवाद की व्याकुलता की आग में अपनी लोलुप मानसिकता के कारण हम जल रहे हैं और उस जलन के बीच हम अपनी बेहतरी की कामना भी करते हैं. इन्हीं सब बातों को पकड़ते हुए मृदुला झा यह साफ़-साफ़ कहने में नहीं हिचकती हैं कि जीवन कांटों भरा पथ है. हमें यह सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए कि जीवन में सिर्फ़ फूल नहीं, कांटे भी मिलते हैं.

डॉ. मृदुला झा में जीवन के किसी भी यथार्थ को काव्यात्मक ढंग से अभिव्यक्त करने की अद्भुत कला है. इस कला के इर्द-गिर्द उनका यथार्थ विचरण करता नज़र आता है, तो एक विचित्र तरह का नाद और सौंदर्य भी उपस्थित होता है. ग़ज़लों के बारे में कहा जाता है कि ग़ज़ल सौंदर्य के बगीचे में एक मुस्कराता हुआ फूल है. यथार्थ के कड़वे संप्रेषण के बावजूद मृदुला झा ने ग़ज़ल रूपी फूल को मुरझ-ाने नहीं दिया:-

झुरमुटों से झांकता है चांद अब,
बात करना चाहता है चांद अब.

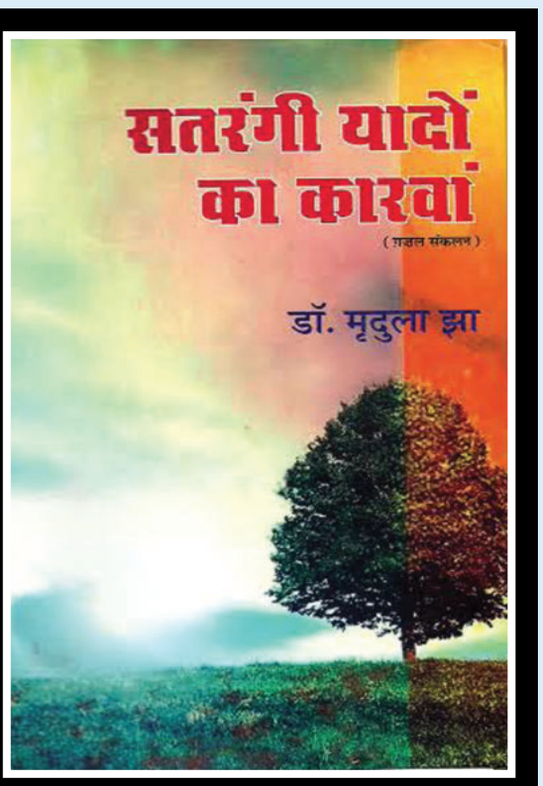

समीक्ष्य कृति : सतरंगी यादों का कारवां (ग़ज़ल संग्रह)
रचनाकार : डॉ. मृदुला झा
प्रकाशक : मोनिका प्रकाशन, प्रताप नगर, जयपुर (राजस्थान)
मूल्य : 250 रुपये

दुष्यंत कुमार के बाद हिंदी ग़ज़ल का जो आंदोलन चला, वह आज भी निरंतर जारी है, जिसकी एक कड़ी के रूप में डॉ. मृदुला झा की ग़ज़लों को भी हम भरोसे के साथ ले सकते हैं. हाल में ही उनका ग़ज़ल संग्रह-सतरंगी यादों का कारवां कुल 83 ग़ज़लों को साथ लेकर पाठकों के समक्ष आया है. संग्रह की सारी ग़ज़लें पढ़ने के बाद मुकम्मल तौर पर कहा जा सकता है कि मृदुला झा की ग़ज़लें समकालीन समाज की विसंगतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए पाठकों से सीधा-सीधा संवाद करती हैं.

आ गया वह आज मेरे द्वार पर,
तीरगी संहारता है चांद अब.

संग्रह की ग़ज़लों में यथार्थ पक्ष और और सौंदर्य पक्ष का आत्मिक मिलन निरंतर बना रहता है, जिससे ग़ज़ल की मासूमियत न तो विचलित होती है और न प्रभावित. इसे हम मृदुला झा की ग़ज़लगोई की सफलता मान सकते हैं, क्योंकि दिल की धड़कनों और दिमाग की करवटों का जो परिधान उन्होंने अपनी ग़ज़लों को दिया है, ऐसी विशेषता हिंदी के बहुत कम ग़ज़लकारों में पाई जाती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

> इस लैपटैब की स्क्रीन 10 इंच की है और इसमें विंडोज 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये डुअल सिम स्लॉट के साथ आता है. दोनों ही सिम 3जी कनेक्टिविटी के साथ आएंगी. इस लैपटैब में माइक्रोसॉफ्ट के ओरिजिनल सॉफ्टवेयर दिए गए हैं. यह टैबलेट 1.8 गीगाहर्ट्ज के क्वाड–कोर इंटेल एटम प्रोसेसर के साथ आता है.

माइक्रोसॉफ्ट का नया वेब ब्राउजर एज

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लेटेस्ट ब्राउजर पर से परदा उठाते हुए ऐलान किया है कि विंडोज 10 ओएस और उससे आगे के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में उसका लेटेस्ट ब्राउजर देखने को मिलेगा. इसे माइक्रोसॉफ्ट एज नाम से जाना जाएगा. इसे एज कहने के पीछे कारण यह है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 ब्राउजर के लिए जिस रेंडरिंग इंजन का इस्तेमाल कर रहा है, उसका नाम एज एचटीएमएल है.

माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट एज के डीटेल्स बताते हुए बताया कि इसे कॉन्टेंट क्रिएट और कन्ज्यूम करने के लिए बनाया गया है. इस ब्राउजर में नए टैब्स के लिए नया लेआउट होगा जिसकी डिजाइन अप्रोच फ्लैट होगी. फेवरेट्स फोल्डर ब्राउजर में बिल्ट होगा, बार–बार विजिट की जाने वाली वेबसाइट्स के थमनेल दिखेंगे, वेब ऐप्स होंगे और कोर्टाना से पर्सनलाइज़्ड इन्फर्मेशन ली जा सकेगी. नए ब्राउजर से आप सीधा वेब पेजों पर लिख सकेंगे और उन्हें शेयर कर सकेंगे, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ सकेंगे और सुविधा के लिहाज से ऑफलाइन रीडिंग फीचर का इस्तेमाल कर सकेंगे. खुले हुए टैब्स के ऊपर माउस घुमाने पर वेबपेज का छोटा थमनेल व्यू देखने को मिलेगा. इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने क्रोम और फायरफॉक्स एक्सटेंशन्स के लिए सपोर्ट भी ऐड किया है जिसे एज के लिए कुछ बदलाव करके ऑप्टिमाइज किया जा सकता है. ■

टोयोटा ने कैमरी का नया मॉडल लॉन्च किया

टोयोटा ने अपनी फुल साइज सेडान कार कैमरी का नया मॉडल बाजार में उतारा है. कंपनी ने इसके पेट्रोल और हाइब्रिड (पेट्रोल+बैटरी से चलने वाला) दोनों मॉडल का फेसलिफ्टेड वर्जन उतारा है. यह पहले वाले मॉडल से ज्यादा आकर्षक है. हालांकि इसमें इंजन संबंधी कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन माइलेज में इजाफा किया गया है. इसमें नई डिजायन वाली ग्रिल, एलईडी हेडलैंप्स, बड़ा एयरटैंक, नई डिजायन वाले फोग लैंप, नए टैल लैंप, 10 स्पॉक अलॉय व्हील, वायरलैस मोबाइल चार्जर, हीटेड सीट्स, 4.2 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, वुड फिनिस्ड सेंटर क्लस्टर आदि नए फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन लगा है जो 160 पीएस का पावर और 213 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. नई टोयोटो कैमरी का माइलेज 12.98 किलोमीटर प्रतिलीटर है. इस कार का यह हाइब्रिड वर्जन है जिसमें 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर लगा है. यह 208 पीएस का पावर और 233 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है. अन्य फीचर्स इसके पेट्रोल मॉडल जैसे ही है. टोयोटा कैमरी हाइब्रिड का माइलेज 19.16 किलोमीटर प्रतिलीटर का है. कंपनी ने इसकी कीमत 28.80 लाख रूपये रखी है. ■

होंडा ने सीबी यूनिकॉर्न 160 किया पेश

होंडा ने यूनिकॉर्न 160 के दो वैरियंट उतारे हैं. इलेक्ट्रिक स्टार्ट और फ्रंट डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स तो बेस वैरियंट में भी हैं. इसके टॉप वैरियंट में कॉम्बी ब्रेक सिस्टम भी दिया गया है जो सेफ्टी के लिहाज से एक अच्छा कदम है. हालांकि टॉप वैरियंट के लिए आपके करीब 6 हजार रुपये ज्यादा चुकाने पड़ेंगे.

होंडा टू वीलर्स ने नए और ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ सीबी यूनिकॉर्न 160 बाइक पेश की है. होंडा की यूनिकॉर्न एक ऐसी बाइक रही है जो खामोशी के साथ लगातार खरीदारों की पसंद रही. नई सीबी यूनिकॉर्न 160 में होंडा ने डिजाइन को लो प्रोफाइल रखते हुए स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की है. होंडा ने यूनिकॉर्न 160 के दो वैरियंट उतारे हैं. इलेक्ट्रिक स्टार्ट और फ्रंट डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स तो बेस वैरियंट में भी हैं. इसके टॉप वैरियंट में कॉम्बी ब्रेक सिस्टम भी दिया गया है जो सेफ्टी के लिहाज से एक अच्छा कदम है. हालांकि टॉप वैरियंट के लिए आपके करीब 6 हजार रुपये ज्यादा चुकाने पड़ेंगे. 17 इंच के अलॉय वील्स के साथ ट्यूबलेस टायर्स भी दिए गए हैं. डिजिटल कंसोल में स्पीड, आरपीएम, फ्यूल के अलावा ट्रिप मीटर और वॉच भी दी गई है. इसमें होंडा का नया 160 सीसी का इंजन लगा है. यह इंजन 14.5 बीएचपी की पावर और 14.6 एनएम का टॉर्क देता है. सेगमेंट के हिसाब से यह इंजन यकीनन पावरफुल है और 0–100 किमी/घंटा तक की रफ्तार के बीच में पावर की कमी बिल्कुन महसूस नहीं होती. इसकी कीमत 71924–77178 रुपये है.

माइक्रोमैक्स का कैनवास लैपटैब

माइक्रोमैक्स ने अपना हाईब्रिड डिवाइस कैनवास लैपटैब लॉन्च किया है. ये टू इन वन डिवाइस बिना कीपैड के टैबलेट की तरह काम करता है और कीपैड लगे होने पर ये लैपटॉप की तरह काम कर सकता है जो 1366 गुणा 768 का पिक्सल रेजोल्यूशन देता है. इस लैपटैब की स्क्रीन 10 इंच की है और इसमें विंडोज 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये डुअल सिम स्लॉट के साथ आता है. दोनों ही सिम 3जी कनेक्टिविटी के साथ आएंगी. इस लैपटैब में माइक्रोसॉफ्ट के ओरिजिनल सॉफ्टवेयर दिए गए हैं. यह टैबलेट 1.8 गीगाहर्ट्ज के क्वाड–कोर इंटेल एटम प्रोसेसर के साथ आता है. इस टैबलेट में 2जीबी रैम है जो मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर साबित हो सकती है. इसमें 32जीबी इंटरनल मेमोरी की सुविधा उपलब्ध है. इस टैबलेट में 2 मेगापिक्सल फ्रंट और बैक कैमरा दिया गया है. इसमें 7700 एमएएच की बैटरी है. माइक्रोमैक्स के इस लैपटैब की कीमत 14999 रुपये है. ■

ऐप के जरिए खरीदें ट्रेन का जनरल टिकट

जनरल डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट के लिए लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है. लेकिन अब आप लंबी लाइन में खड़े होने जरूरत नहीं होगी. भारतीय रेल ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसके जरिए यात्री जनरल टिकट कटा सकेंगे. रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस ऐप को आम लोगों के लिए लॉन्च किया गया है. इस ऐप के जरिए टिकट बुक करने वाले यात्रियों को इसका प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं होगी. टीटी को मोबाइल एसएमएस दिखा कर यात्रा की जा सकेगी. ये ऐप यात्रियों का समय भी बचाएगी. इस ऐप का नाम यूटीएस (UTS)दिया गया है जो गूगल प्लेस्टोर पर उपलब्ध है. ये ऐप सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (CRIS) ने तैयार किया है. इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद यूजर्स को ई–वॉलेट क्रिएट करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन आईडी दी जाएगी. जिसके जरिए यूजर्स पेमेंट कर पाएंगे. यात्री इस ई–वॉलेट को आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट या रेलवे टिकट काउंटर पर जाकर क्रेडिट या डेबिट कार्ड की मदद से टॉप–अप करवा सकते हैं. साथ ही इस ऐप के जरिए मासिक पास वाले यात्री भी अपने पास को रीन्यू करा सकते हैं. ■

एलजी का जी4 एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च

एलजी ने स्मार्टफोन बाजार में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए अपने बहुप्रतिक्षित फोन जी4 को लॉन्च किया है. एलजी जी4 स्मार्टफोन की बॉडी कर्व्ड है, जबकि इसके पीछे लेदर फिनिश का ऑप्शन भी दिया गया है. फोन की यूएसपी इसका कैमरा है, जिसे लेकर कंपनी बहुत उत्साहित है. वाइड एपरचर वाले इस कैमरे में नए कलर स्पैक्ट्रम सेंसर लगाए गए हैं, जो पहले से बेहतर और सटीक व्हाईट बैलेंस की सुविधा देते हैं. इसमें एक नया मैनुअल मोड भी जोड़ा गया है. इस फोन स्क्रीन 5.5 इंच की है जो 1440 गुणा 2560 पिकस्ल का रोजोल्यूशन देती है. इसका रियर कैमरा 16 एमपी का है जो 5312 गुणा 2988 पिकस्ल का रेजोल्यूशन देता है और फ्रंट कैमरा 8 एमपी का है. इसकी बैटरी 3000 एमएएच है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

मेवेदर ने भले ही यह मुक़ाबला जीत लिया हो लेकिन वह अपने चाहने वालों का दिल नहीं जीत सके. लोगों की नाराजगी की वजह मेवेदर का पैसों को लेकर मोह और महिलाओं के प्रति उनका खराब इतिहास है. इस जीत के बाद जिस तरह उन्होंने मीडिया के सामने खुद को बड़बोले तरीके से पेश किया, इस, वजह से भी लोग उनसे बेहद खफा हैं. मेदेवर ने जीत के बाद सौ मिलियन डॉलर के चेक को मीडिया के सामने शेखी बघारते हुए लहराया था.

मेवेदर ने जीता बॉक्सिंग का महा मुक़ाबला

पेशेवर बॉक्सिंग को दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में से एक माना जाता है, लेकिन यह दुनिया के सबसे पसंदीदा खेलों में से एक भी है. यहां बॉक्सिंग रिंग में मुक्कों के साथ साथ पैसे भी बरसते हैं. ऐसा ही नजारा एक बार फिर अमेरिका के लासवेगास में देखने को मिला जहां अमेरिकी मुक्केबाज फ्लॉयड मेवेदर और फिलीपींस के मैनी पैकियाओ के बीच हुए मुक़ाबले में दो हजार करोड़ रुपये दांव पर लगे थे. जितना पैसा दूसरे खेलों का स्टार खिलाड़ी अपने पूरे करियर में नहीं कमा पाता है उससे कई गुना ज्यादा इस महा-मुक़ाबले में हारने वाले खिलाड़ी ने कमाये.

चौथी दुनिया ब्यूरो

आलीशान नाइट लाइफ और कसीनोज के लिए जाने जाने वाले अमेरिका के लास वेगास में 2 मई को बॉक्सिंग इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला हुआ. इस महा-मुक़ाबले को सदी का मुकाबला कहा गया. ऐसा कहना भी जायज है क्योंकि मुकाबले में 2000 करोड़ रुपये दांव पर लगे हुए थे. मुकाबले के लिए रिंग में एक तरफ थे अमेरिका के फ्लॉयड मेवेदर तो दूसरी तरफ फिलीपींस के मैनी पैकियाओ. इस मुकाबले से पहले प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मेदेवर को कोई भी बॉक्सर आज तक मात नहीं दे सका था. इस महा-मुक़ाबले में भी मेवेदर ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा और करियर का 48 वां मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस मुकाबले से पहले उन्होंने 47 मुकाबले लड़ते थे जिसमें से 47 में उन्हें जीत हासिल हुई थी. उनमें से 26 में में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को नॉकआउट किया था. वहीं रिंग के दूसरी तरफ खड़े पैकियाओ पेशेवर बॉक्सर बनने के बाद 65 बार रिंग में उतरे हैं, जिसमें से 57 में उन्हें जीत मिली और 6 में हार. जबकि 2 मुकाबले ड्रा रहे थे. 38 वर्षीय अमेरिकी बॉक्सर मेवेदर ने फिलिपींस के 36 वर्षीय पैकियाओ को 12 राउंड तक चले इस मुकाबले में महज छह अंको के अंतर से मात दी.

मेवेदर अपने करियर में कभी नहीं हारे हैं. वह पेशेवर मुक्केबाजी की पांच श्रेणियों के वर्ल्ड चैम्पियन हैं. हालांकि पैकियाओ ने आठ अलग-अलग भार श्रेणियों में ताज हासिल किया है. इस तरह की विविधता वाले मुक्केबाजों का रिंग में लड़ना आम बात नहीं थी. दो महान मुक्केबाजों के बीच मुकाबला देखना बेहद दिलचस्प था. यह मुकाबला कई और कारणों की वजह से भी खास था क्योंकि फ्लॉयड मेवेदर के मुक्कों की गति सांप के हमला करने की गति से भी तेज हैं. वे 30 मील/घंटे की रफ्तार से अपने विरोधी पर प्रहार करते हैं. विपक्षी के प्रहार पर प्रतिक्रिया देने में भी वे सामान्य व्यक्ति की तुलना में दो-गुना तेज हैं. हालांकि उनके विरोधी पैकियाओ भी कम नहीं थे वे 0.12 सेकेंड की गति से मुक्का मारते हैं जबकि आम आदमी को पलक झपकाने में 0.3 सेकेंड लगते हैं. पिछले पांच मुकाबलों के दौरान उन्होंने हर राउंड में औसत 60 मुक्के मारे थे जो कि मेवेदर की तुलना में 20 ज्यादा थे. उनकी विपक्षी की आंखों पर मुक्का मारने की उनकी कला बहुत घातक है. मेवेदर ने 55.3 प्रतिशत मुकाबले नॉकआउट से जीते हैं उन्होंने आखिरी बार साल 2011 में फाइट की थी. नॉकआउट राउंड में पैक्याओ ने 66.6 प्रतिशत जीत दर्ज की है. करियर में मेवेदर ने प्रति राउंड में 39 पंच मारे हैं. इस महा-मुक़ाबले में तकरीबन 2 हजार करोड़ रुपये दांव पर लगे हुए थे. मुक़ाबला जीतने के बाद फ्लॉयड मेवेदर जूनियर को 1147 करोड़ रुपए मिले जबकि पैकियाओ को 647 करोड़ रुपये मिले. इस जीत के साथ ही 67 किग्रा वर्ग के डब्ल्यूबीए, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीओ के खिताब भी मवेदर के नाम हो गए.

दुनिया के लिए भले ही यह मुकाबला करोड़ों की कमाई के कारण अहम था लेकिन पैकियाओ के लिए पैसे से ज्यादा कुछ और निशाने पर था. वे अपने देश फिलीपींस के सांसद हैं और बतौर राजनेता उन्होंने अपनी छवि सुधारी है. वे देश का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और प्रशंसक भी इसकी मांग करते रहे हैं. यदि वह, यह मुकाबला जीत जाते तो उनकी छवि और सुदृढ़ होती. हालांकि राष्ट्रपति बनने के लिए उन्हें 40 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा. पैकियाओ की भारी सफलता ने उन्हें पहले से ही एशिया का सबसे सफल बॉक्सर बना दिया है. अपने मूल देश फिलीपींस में एक बड़ा वर्ग उनका समर्थक है, वहां वे एक सांसद हैं और उनके मानवीय कार्यों के लिए उनकी सराहना भी होती है. स्थानीय स्तर पर उन्हें नेशनल फिस्ट के रूप में जाना जाता है, जो बाधाओं के खिलाफ लड़ने का एक सवश्रेष्ठ उदाहरण हैं. वे भी भले ही मुक़ाबला हार गए हैं, लेकिन एशियाई युवाओं को मुक्केबाजी के लिए प्रेरित करेंगे. पैकियाओ बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, मुक्केबाजी उनका प्रधान गुण हो सकती है लेकिन उनकी संगीत और

बॉक्सिंग ने खेलों से कमाई के मामले में फुटबॉल और बास्केटबॉल सहित सभी खेलों को पछाड़ दिया है. फोर्ब्स की लिस्ट में मेवेदर पहले पायदान पर हैं. भारत में क्रिकेट सबसे बड़ा खेल है, महेंद्र सिंह धोनी कमाई के मामले में विश्व के नंबर एक क्रिकेटर है. लेकिन उनकी कुल कमाई 1800 करोड़ रुपये है. केवल इस महा-मुकाबले से मेवेदर ने धोनी की कुल कमाई के दो तिहाई के बराबर पैसा बना लिया. इस मुकाबले को फाइट ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया था. मेवेदर को इस फाइट से जितने पैसे मिले उतने डेविड बेकहम ने पूरे करियर में कमाए. मुकाबले के दौरान मेवेदर की सिर्फ 5 मिनट की कमाई, लियोनेल मेसी की साल भर की कमाई के बराबर है.

अन्य खेलों में भी रुचि है, पैकियाओ के गीतों के दो एल्बम बाजार में है. वह बास्केट बॉल भी खेलते हैं और फिलीपींस में सिटकोम और रियलिटी शो में भी दिखाई देते हैं. इन्हीं वजहों से उनके आलोचक अक्सर उन पर अपना ध्यान खोने का आरोप लगाते हैं.

फ्लॉयड मेवेदर मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन हैं और उनकी सालाना कमाई 6,500 करोड़ रुपये है. मेवेदर दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले बॉक्सर और खिलाड़ी हैं. वर्ल्ड चैंपियनशिप के तकरीबन दस खिताब जीत चुके मेवेदर के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि उनकी पूरी कमाई खिताब जीतने या तनख्वाह से ही आती है, विज्ञापनों से नहीं. हालांकि वह कई बड़े ब्रांडों के विज्ञापनों में कभी-कभी दिखाई दे जाते हैं. बॉक्सिंग ने खेलों से कमाई के मामले में फुटबॉल और बास्केटबॉल सहित सभी खेलों को पछाड़ दिया है. फोर्ब्स की लिस्ट में मेवेदर पहले पायदान पर हैं. भारत में क्रिकेट सबसे बड़ा खेल है, महेंद्र सिंह धोनी कमाई के मामले में विश्व के नंबर एक क्रिकेटर है. लेकिन उनकी कुल कमाई 1800 करोड़ रुपये है. केवल इस महा-मुकाबले से मेदेवर ने धोनी की कुल कमाई के दो तिहाई के बराबर पैसा बना लिया. इस मुकाबले को फाइट ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया था. मेवेदर को इस फाइट से जितने पैसे मिले उतने डेविड बेकहम ने पूरे करियर में कमाए. मुकाबले के दौरान मेवेदर की सिर्फ 5 मिनट की कमाई, लियोनेल मेसी की साल भर की कमाई के बराबर है.

मेवेदर ने भले ही यह मुक़ाबला जीत लिया हो लेकिन वह अपने चाहने वालों का दिल नहीं जीत सके. लोगों की नाराजगी की वजह मेवेदर का पैसों को लेकर मोह और महिलाओं के प्रति उनका खराब इतिहास है. इस जीत के बाद जिस तरह उन्होंने मीडिया के सामने खुद को बड़बोले तरीके से पेश किया. इस वजह से भी लोग उनसे बेहद खफा हैं. मेदेवर ने जीत के बाद सौ मिलियन डॉलर के चेक को मीडिया के सामने शेखी बघारते हुए लहराया था. इस वजह से फोटोग्राफरों ने उनकी तस्वीर खींचने से भी इंकार कर दिया था. पहले भी मेवेदर बॉक्सिंग रिंग के अलावा अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. अपनी पूर्व प्रेमिका पर हमला करने की वजह से उन्हें साल 2012 में दो माह जेल में भी बिताने पड़े थे. पैसों को लेकर लोभ के पीछे उनका अतीत है. मेवेदर का बचपन बेहद गरीबी में बीता. वह अमेरिका के मिशिगन में अपने चार भाई-बहनों के साथ एक कमरे में रहे. इस जीत के बाद खेल जगत के सबसे अमीर खिलाड़ी इस खिलाड़ी का कद और बड़ा हो गया है.

जीत के बाद उन्हें चुनौती देने वालों की सूची थमने का नाम नहीं ले ही है. उन्हें पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश मुक्केबाज आमिर खान ने चुनौती दी है. वहीं भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंद्र सिंह भी मेवेदर के खिलाफ लड़ने की इच्छा जाहिर की है. मेवेदर से दस साल छोटे 28 वर्षीय आमिर खान का मानना है कि वह अमेरिकी मुक्केबाज के करियर के आखिरी प्रतिद्वंद्वी बनने के सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं. मेवेदर इसी साल सितंबर में संन्यास लेन वाले हैं और इससे पहले वह एक बार और रिंग में उतरना चाहते हैं. मेदेवर की जीत के बाद विजेंद्र सिंह ने कहा कि यदि मौका मिले तो वह मेवेदर के साथ मुक़ाबला करना पसंद करेंगे. वह एक शानदार मुक्केबाज हैं उन पर पैसों और महिलाओं को लेकर भले ही कितने आरोप लगे हों लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया है वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ वेल्टरवेट मुक्केबाज हैं. वहीं भारत के पूर्व ओलंपिक मुक्केबाज अखिल कुमार का कहना है कि मेवेदर और पैकियाओ के बीच हुए महा-मुक़ाबले में फाइट कम और हाइप ज्यादा थी. इसमें दिखावा और हुड़दंग ज्यादा था. अगर मुक्केबाजी के असली मुकाबलों की बात की जाए तो शुगर रे, मोहम्मद अली और रॉकी जूनियर के मुकाबलों को आज भी देखें तो आप रोमांचित हो जायेंगे. इस मुकाबले को देखने के लिए फैंस ने 13 लाख रुपये से लेकर सवा दो करोड़ रुपये तक खर्च किए. फैंस इस मुकाबले का इंतजार पिछले पांच वर्षों से कर रहे थे. भारतीय समयानुसार 2 मई को सुबह साढ़े आठ बजे यह मुक़ाबला खेला गया. यह अब तक की सबसे बड़ी ईनामी राशि वाला मुकाबला था. इससे पहले ऐसा सुपर मुकाबला साल 2002 में हैवीवेट टाइटल के लिए माइक टायसन और लेनोक्स लुईस के बीच और साल 2011 में व्लादिमीर कल्चिको और डेविड हे के बीच हुआ था, इस मुकाबले को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह था. मुकाबले के विजेता को डब्ल्यूबीसी (वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल) द्वारा एक बेल्ट दी गई जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपये है. लास वेगास के एमजीएम एरिना की क्षमता 16,500 दर्शकों की थी. मुक्केबाज़ी के महत्व को ध्यान में रखते हुए हॉलीवुड की शीर्ष हस्तियां और दिग्गज व्यापारी एक रिंगसाइड सीट पर थे.

यह वेल्टरवेट श्रेणी का मुकाबला था. इस जीत के साथ ही मेवेदर यूनिफाइड चैंपियन बन गए हैं. इस मुक़ाबले से पहले वे डब्ल्यूबीए और डब्ल्यूबीसी चैंपियन थे. दोनों मुक्केबाजों के रिंग में आने से पहले दोनों देशों के राष्ट्रगान गाये गए. इस दौरान वहां मौजूद दर्शकों का उत्साह देखते ही बना. फिलिंपिंस में राजधानी मनीला समेत सभी बड़े शहरों की सड़कों पर मुकाबले के दौरान सन्नाटा छाया रहा. यहां जीत दर्ज कर मेवेदर ने डब्ल्यूबीओ श्रेणी का खिताब पैकियाओ से छीन लिया. शुरुआती दो राउंड में मेवेदर आगे थे, लेकिन पैकियाओ ने वापसी करते हुए अगले दो राउंड जीते. आखिरी राउंड में मेवेदर अपने विरोधी पर भारी पड़े. आखिर में तीन जजों ने 118-110,116-112 और 116-112 से मेवेदर के पक्ष में फैसला सुनाया. हार के बाद पैकियाओ ने कहा कि उन्हें लगा था कि वह मुक़ाबला जीत गए हैं. उन्होंने हार के बाद जजेस के निर्णय पर उंगली उठाई. वेल्टरवेट वर्ग के इस खिताबी मुक़ाबले में मेयवेदर ने तीन जजेस के फैसले के आधार पर पैकियाओ को हराया. मुकाबले के बाद पैक्याओ ने कहा- मुझे लगा कि मैं फाइट जीत गया हूं. मेवेदर ने मुक़ाबले में कुछ भी नहीं किया. वो सिर्फ रिंग में एक तरफ से दूसरी तरफ घूम रहे थे. मैंने उन पर कई बार सटीक हमले किए और पंचेस जमाए. मुझे लगता है कि इस फाइट का असली विजेता मैं हूं. पैकियाओ ने कहा कि जब कोई मुक्केबाज लगातार यहां-वहां घूम रहा हो तो उस पर पंच लगाना आसान नहीं होता. यदि वो एक जगह टिक कर लड़ते तो मैं ज्यादा पंचेस लगा सकता था. हालांकि पैकियाओ ने इस बात से इंकार किया कि मेवेदर को उनकी ऊंचाई और पहुंच का लाभ मिला. इस पर उन्होंने कहा कि मेवेदर से भी ज्यादा ऊंचे और ज्यादा पहुंच वाले मुक्केबाजों से वह भिड़ चुके थे. इस वजह से उनका आकार या पहुंच मुकाबले में महत्व नहीं रखती थी.

इस मुकाबले को सदी के महान मुक्केबाजी मुकाबले के रूप में याद किया जाएगा, दुनिया में जिसने भी इस मुकाबले को देखा उसके लिए यह कभी न भुलाई जा सकने वाली यादों में शुमार हो गया. इससे पहले सबसे ज्यादा ईनामी राशि 2013 में मेवेदर और मेक्सिको के साउल अलवारेज के मुकाबले में करीब एक हजार करोड़ रुपए जमा हुई थी. मेवेदर ने 1996 में अटलांटा ओलंपिक में एक कांस्य पदक जीता था. जबकि पैकियाओ को ओलंपिक में भाग लेने का मौका कभी नहीं मिला है. लेकिन हाल ही में उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में भाग लेने की इच्छा जताई है. उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ (एआईबीए) ने प्रोफेशनल मुक्केबाजों को भी ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति दी है, जहां अब तक केवल एमेच्योर मुक्केबाज ही भाग ले सकते थे. इस मुकाबले से दुनिया भर का ध्यान जुटाने की उम्मीद थी और पेकियाओ के पास यह दिखाने का मौका भी था कि उनकी मौजदूगी से ओलंपिक में ग्लैमर जुड़ जाएगा. हाल ही में मेवेदर ने कहा कि वे मोहम्मद अली से बढ़कर हैं. इस ऐतिहासिक मुकाबले के बाद मेवेदर ने दिखा दिया है कि उनमें अपने शब्दों को जीवित करने की क्षमता है.■

navinonline2003@gmail.com

एयर होस्टेस बनीं सोनम

सोनम कपूर एक नए अंदाज में नजर आने वाली हैं, इस बार वह फ्लाइट अटेंडेंट नीरजा भानोत के भूमिका अदा करेंगी. 1986 में कराची में प्लेन पैन-एम फ्लाइट-73 को हाइजैक किया गया था. प्लेन को हाइजैक करने वाले आतंकवादियों ने विमान में सवार यात्रियों को बचाने की कोशिश करने वाली नीरजा को मौत के घाट उतार दिया था. फिल्म के अपने किरदार की पहली तस्वीर सोनम ने ट्विटर पर साझा की है. मशहूर फैशन फोटोग्राफर अतुल कस्बेकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं. जबकि राम माधवानी फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं. नीरजा भानोत के जीवन पर आधारित इस फिल्म की शूटिंग पिछले महीने शुरू हुई है. फिल्म में अभिनेत्री शबाना आजमी नीरजा की मां के किरदार में नज़र आयेंगी.■

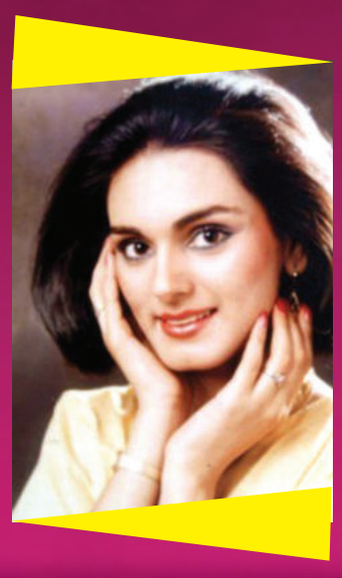

कंगना ने तोड़ी परंपरा

62 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कंगना सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ग्रहण करने गाउन पहनकर पहुंचीं. इससे पहले सभी अभिनेत्रियां पुरस्कार लेने साड़ी में पहुंचती थीं. यह कंगना के फिल्मी करियर का दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है.

अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर स्थापित परंपरा को तोड़ दिया है. इस बार कंगना ने यह कारनाम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के दौरान किया है. आम तौर पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में चलन रहा है कि कलाकार यहां पुरस्कार ग्रहण करने पारंपरिक परिधानों में पहुंचते हैं, लेकिन 62 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कंगना सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ग्रहण करने गाउन पहनकर पहुंचीं. इससे पहले अमूमन सभी अभिनेत्रियां पुरस्कार लेने साड़ी पहनकर पहुंचीं थीं.

यह कंगना के फिल्म करियर का दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है. पिछली बार फिल्म फैशन के लिए सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था. इस बार कंगना को फिल्म क्वीन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है. फिल्म में कंगना शादी टूटने के बाद अकेले हनीमून पर चली जाती हैं. ऐसा लगता है कि क्वीन का किरदार उनकी सोच और उनके व्यतित्व से मिलता-जुलता है. इसलिए वह अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय इस फिल्म में कर पाईं. उनकी उन्हीं स्थापित परंपराओं को तोड़ने और चुनौती देने वाले व्यक्तित्व की झलक पुरस्कार वितरण के दौरान भी दिखाई दी. न्यूयार्क में रहने वाले भारतीय डिजाइनर विभु महापात्र ने कंगना के लिए गाउन डिजाइन किया था. जिसे कंगना ने समारोह में पहना था. विभु अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल के लिए परिधान डिजाइन कर चुके हैं. ■

गीतकार बने कपिल सिब्बल

जाने माने वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल आजकल फिल्मों के लिए गीत लिख रहे हैं. आने वाली फिल्म जैनब-ए सेलीब्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए कपिल सिब्बल ने पांच गाने लिखे हैं. जैनब राजनीति पर आधारित एक फिल्म है. सिब्बल ने कहा है, कि जागरूकता लाने और सामाजिक संदेश फैलाने के लिए सिनेमा एक अच्छा और उपयोगी माध्यम है जो कि लोगों को प्रभावित करता है. इस फिल्म के जरिए मैं खुशी, मानवता और सौहार्द का संदेश देना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने विचारों और मानसिकता को नहीं बदलेंगे तब तक कोई भी क़ानून समाज में बदलाव लाने में सक्षम नहीं होगा. अगर हम अपने समाज को अधिक करुणामय बनाना चाहते हैं तो हर व्यक्ति के विचारों को बदलना जरूरी है. प्रणव सिंह के निर्शेशन में बनी ये फिल्म सामाजिक-राजनीतिक प्रेम कहानी का मिक्सचर है. आशुतोष राणा, जिमी शेरगिल, संजय सूरी और हितेन तेजवानी इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं. यह फिल्म एक हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की जैनब की प्रेम कहानी पर आधारित है. जो सांप्रदायिक दंगों और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ जाकर प्यार करते हैं. जिमी, संजय और आशुतोष ने फिल्म के बारे में कहा कि, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और हम सभी के लिए यह एक चुनौती भी. लेकिन यही इसे व्यापक बनाती है. फिल्म का विषय अधिक प्रासंगिक है.■

वैश्विक राजनीति पर व्यंग्य है वेलकम टू कराची

अरशद वारसी लंबे अंतराल बाद फिल्म वेलकम टू कराची में नज़र आने वाले हैं. खिलाड़ी 786 की रिलीज के बाद निर्देशक आशीष मोहन की भी यह यह नई फिल्म है. निर्देशक आशीष ने अपनी फिल्म के बारे में बताया कि यह फिल्म वैश्विक राजनीति पर व्यंग्य है. यह दिखाती है कि राजनीतिक दल सिर्फ अपने फायदे के लिए किस तरह आम आदमी का इस्तेमाल करते हैं. मेरे लेखक और मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है. फिल्म के लिए बहुत रिसर्च करने की जरूरत थी. मैं किसी दूसरी फिल्म से पहले इसे बनाना चाहता था. इस फिल्म की शूटिंग इंग्लैंड और इंदौर में हुई है. फिल्म 21 मई को रिलीज होगी. उन्होंने कहा कि दर्शकों को खिलाड़ी 786 जैसी ही कॉमेडी की खुराक मिलेगी. उन्होंने कहा कि, मेरी अंतिम फिल्म एक एंटरटेनर थी. इसी तरह, इस फिल्म में भी आप एक भी पल बोर नहीं होंगे. यह एक गंभीर विषय है लेकिन मैंने इसे मनोरंजक लहजे में कहा है. लोग इसका मजा लेंगे. फिल्म के आखिर में एक मैसेज भी है जिससे लोग उस संदेश के बारे में भी सोचेंगे. पहले फिल्मे में इरफान खान को लिया गया था, लेकिन बाद में जैकी को लिया गया क्योंकि निर्माताओं के साथ डिफरेंसेस की वजह से इरफान ने फिल्म छोड़ दी थी.■

अनिल कपूर सबसे स्टाइलिश सेलिब्रिटी

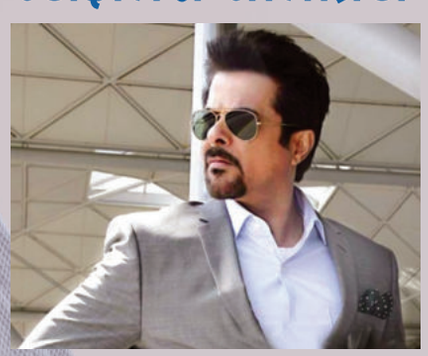

अभिनेता अर्जुन कपूर अपने चाचा अनिल कपूर को हिंदी सिनेमा का सबसे स्टाइलिश सेलिब्रिटी मानते हैं. दिल धड़कने दो में काम कर रहे अनिल ने स्वयं को बहुत समय से चुस्त-दुरुस्त बनाये रखा है. अर्जुन ने कहा कि वह बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश सेलिब्रिटी हैं. वह समय के साथ और जवान और स्टाइलिश होते जा रहे हैं.■

फास्ट एंड फ्यूरियस-7 ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस-7 ने भारत में शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की इस नई फिल्म ने भारत में 100 करोड़ रुपयों की रिकॉर्ड कमाई की है. जो भारत में किसी भी हॉलीवुड फिल्म का अबतक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. गौरतलब है कि इस फिल्म ने अपने पहले ही हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. इसे देशभर में 2800 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था. इस फिल्म में विन डीजल, पॉल वॉकर, डेवेन जॉनसन, जेसन स्टेथम और मिशेल रोड्री गूज मुख्य भूमिका में हैं. पॉल वॉकर की ये उनकी आखिरी फिल्म रही. फिल्म 2 अप्रैल को भारत में 2-डी, 3-डी और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज हुई थी. खबरें आ रही हैं कि इस सीरीज की आठवीं फिल्म साल 2017 में रिलीज होगी. यह फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म है, जो अभिनेता पॉल वॉकर के बगैर बनेगी.■

पिता को खुश करने की कोशिश करता रहूंगा रणबीर

मेरे पिता दिखावा नहीं करते हैं. जब उन्होंने फिल्म बर्फी देखी थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारा अभिनय अच्छा है, लेकिन आर्ट फिल्मों में काम मत करो. उनका सिनेमा बहुत अलग है और वह कभी-कभी मुझसे उसका अनुसरण करने की उम्मीद करते हैं. रणबीर ने कहा मैं उन्हें अपने जीवन में पाकर खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं. वह मुझे वास्तविकता बताते हैं. मैं उन्हें खुश करने की हमेशा कोशिश करता रहूंगा.

बॉलीवुड के रॉकस्टार रणबीर कपूर का कहना है कि वह अपने पिता ऋषि कपूर को खुश करने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे. रणबीर का कहना है कि वह अपने पिता के साथ अपने काम के बारे में बहुत कम चर्चा करते हैं. फिल्मों के बारे में उनकी और उनके पिता की समझ एकदम अलग है, बावजूद इसके वह अपने पिता की राय का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि मेरे पिता दिखावा नहीं करते हैं. जब उन्होंने फिल्म बर्फी देखी थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारा अभिनय अच्छा है, लेकिन आर्ट फिल्मों में काम मत करो.

उनका सिनेमा बहुत अलग है और वह कभी-कभी मुझसे उसका अनुसरण करने की उम्मीद करते हैं. रणबीर ने कहा कि मैं उन्हें अपने जीवन में पाकर खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं. वह मुझे वास्तविकता बताते हैं. मैं उन्हें खुश करने की कोशिश हमेशा करता रहूंगा. हालांकि, इसमें 15 से 20 वर्ष लग सकते हैं. उनके लिए उनके पिता के ईमानदार विचार बहुत मायने रखते हैं और वह इस बात से खुश हैं कि ऋषि कपूर को आगामी फिल्म बॉम्बे वेलवेट में उनका काम पसंद आया है. अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी यह फिल्म 15 मई को में रिलीज होगी. निर्देशक अुराग कश्यप ने कहा कि ऋषि ने हाल में फिल्म देखी है. उन्हें एवं नीतू सिंह को फिल्म बहुत पसंद आई. दोनों का ही कहना है कि रणबीर ने इस फिल्म में अपने करियर की सबसे बेहतरीन एक्टिंग की है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

18 मई–24 मई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

डॉक्टर दम्पत्ति को लखनऊ के अपार्टमेंट में रखा था

दुसाहसिक अपहरण की फिसड्डी रिहाई-कथा

पंकज और शुभ्रा

प्रभात रंजन दीन

बिहार से अगवा किए गए डॉक्टर दम्पति को लखनऊ में छुपा कर रखे जाने की घटना ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि बिहार में एक बार फिर से पनप रहे अपहरण-उद्योग से जुड़े गिरोह कहीं लखनऊ में अपना ठौर तो नहीं बना रहे! इसके पहले भी बिहार में अपहरण की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं हैं, जिसमें अपहरणकर्ता लखनऊ से पकड़े गए थे और अगवा हुए लोगों को भी यहीं छुपा कर रखा गया था. बिहार के अपहृत डॉक्टर दम्पत्ति को लखनऊ के एक अपार्टमेंट में छुपा कर रखे जाने और पूरे गिरोह के यहां पकड़े जाने से यह सवाल फिर ताजा हुआ है और इस घटना ने उत्तर प्रदेश पुलिस के अभिसूचना तंत्र को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है.

अपहृत डॉक्टर दम्पत्ति की बरामदगी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स चाहे जितना श्रेय ले, लेकिन सच्चाई यह है कि फिरौती की रकम वसूलने के बाद गिरोह ने डॉक्टर दम्पत्ति को पहले ही छोड़ दिया था. गिरोह अपना साजो-सामान समेट कर लखनऊ के अपार्टमेंट से खिसक पाता, उसके पहले ही पकड़ लिया गया. बिहार पुलिस की सटीक सूचना पर यूपी पुलिस को यह कामयाबी मिल पाई. गोमतीनगर के एक अपार्टमेंट में इतने दिन से अपराधियों का पूरा गिरोह अगवा दम्पति को रखे रहा, लेकिन स्थानीय पुलिस या स्थानीय खुफिया इकाई को इसकी कोई भनक नहीं मिली. बिहार पुलिस ने जब यूपी पुलिस से सूचनाएं साझा कीं और औपचारिक रूप से पुलिस महानिदेशक एके जैन से मदद मांगी, तब जाकर अपहरण-गाथा की परतें खुलना शुरू हुईं. फिरौती की वसूली गई रकम के बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है कि रकम कैसे और कहां मिली और वह कितनी थी.

गिरोह के पकड़े जाने के कारण रहस्य से पर्दा धीरे-धीरे उठ सकता है. यह कह सकते हैं कि बिहार पुलिस की कोशिश आखिरकार रंग लाई. बिहार के गया शहर में एक मई को अपनी ऑडी कार से घर लौट रहे डॉ. पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी शुभ्रा गुप्ता का कार समेत अपहरण कर लिया गया था. अपहरण के बाद उन्हें लखनऊ ले आया गया था. अभी फिरौती वसूलने की भूमिका ही बांधी जा रही थी कि बिहार पुलिस के इनपुट पर लखनऊ में नाटकीय कार्रवाई कर नौ सदस्यों वाला पूरा गिरोह पकड़ लिया गया. लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. फिरौती वसूलने के बाद गिरोह ने डॉक्टर दम्पत्ति को पहले ही छोड़ दिया था. बिहार में लगातार कई अपहरणों को अंजाम देने वाले गिरोह को गिरफ्त में जरूर ले लिया गया और गिरोह का सरगना अजय सिंह भी साथियों के साथ पकड़ लिया गया. गिरोह सरगना अजय सिंह बिहार पुलिस के रिटायर्ड डीएसपी मंगल सिंह का बेटा है. इसका एक भाई पटना नगर निगम में अधिकारी है. ऑपरेशन को लीड करने वाले यूपी एसटीएफ के आईजी सुजीत पांडेय भी बिहार के ही रहने वाले हैं.

अजय सिंह की गिनती देश के कुछ बड़े अपहरणकर्ताओं में होने लगी थी. पहले वह बिहार से बाहर ही अपहरण करता था. अजय सिंह चर्चा में तब आया, जब उसने फरवरी 2003 में जयपुर से हीरों के बड़े व्यापारी रश्मिकांत दुर्लभजी की पत्नी सुमेधा दुर्लभजी का अपहरण किया था. यह परिवार लालकृष्ण आडवाणी का काफी करीबी है. देशव्यापी तलाशी ऑपरेशन के बाद साठ वर्षीय सुमेधा दुर्लभजी को फरीदाबाद से छुड़ाया गया था. लेकिन उस अपहरण में भी ढाई करोड़ की फिरौती वसूल ली गई थी. बाद में अजय सिंह अपने साथियों के साथ पकड़ा गया था. इसके पहले अजय सिंह ने चतरा लोकसभा क्षेत्र से चंद्रशेखर की पार्टी समाजवादी जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ा था. जयपुर जेल में रहते हुए भी इसने तरैया से विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी थी, लेकिन टिकट नहीं मिला. जयपुर अपहरण मामले में अजय सिंह को आजीवन कारावास की सजा मिली थी. वह अक्टूबर 2011 में पैरोल पर छूटकर आया था. महीने भर बाद जेल लौटना था, लेकिन फरार हो गया. इसके बाद अपने गिरोह को फिर से संगठित कर वह अपहरणों को अंजाम देता रहा. पुलिस अधिकारी के वेश में अगवा करने में इस गिरोह को महारत हासिल है. लखनऊ में इसके पहले भी वह काम कर चुका है.

अपहृत डॉक्टर दम्पत्ति को गोमती नगर में मखदुमपुर पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित शारदा अपार्टमेंट की नौवीं मंजिल के फ्लैट में छुपाकर रखा गया था. अपहरण में इस्तेमाल में आई डॉक्टर की ऑडी कार के साथ-साथ एक फॉरचुनर गाड़ी भी बरामद की गई, जो पहले एक अपहरण के मामले में ही झटकी गई थी. इन कारों पर बाकायदा लाल-नीली बत्तियां और हूटर वगैरह लगे थे. कई हथियार और गोलियां भी बरामद हुई हैं. इसके साथ ही पुलिस की कई वर्दियां और स्टार वगैरह और नशीली दवाएं वगैरह भी बरामद हुई हैं. गोमती नगर के शारदा अपार्टमेंट में हुई छापेमारी में गिरफ्तार किए गए अपहरणकर्ताओं को मीडिया के सामने लाया गया, लेकिन डॉक्टर दम्पत्ति को सामने नहीं लाया गया. दरअसल, डॉक्टर दम्पति को अपार्टमेंट से बरामद ही नहीं किया गया. अपहर्ताओं ने उन्हें पहले ही स्टेशन लाकर छोड़ दिया था. बिहार के पुलिस महानिदेशक पीके ठाकुर ने कहा भी कि चिकित्सक दम्पति सकुशल अपने घर वापस आ गए हैं. श्री ठाकुर ने कहा कि अपहर्ताओं ने लखनऊ रेलवे स्टेशन पर चिकित्सक दम्पति को रिहा कर दिया था. गोमती नगर के शारदा अपार्टमेंट के फ्लैट को अपहरणकर्ताओं ने अपहृतों को रखने के लिए ही किराये पर लिया था. बिहार से लखनऊ आए एसपी राकेश कुमार ने बताया कि बिहार पुलिस को सर्विलांस से गैंग की लोकेशन मिल गई थी. यूपी एसटीएफ के आईजी सुजीत पांडेय ने कहा कि शारदा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर-906 की रेकी करने के बाद पूरी तैयारी से लखनऊ पुलिस, बिहार पुलिस और एसटीएफ ने फ्लैट पर छापा मारा. पुलिस ने सरगना अजय सिंह समेत नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया. शारदा अपार्टमेंट का यह फ्लैट गौरव शर्मा का है, जो फिलहाल लंदन में रहते हैं. लेकिन एसटीएफ के इस बयान में कई पोल हैं, जिसका खुलासा नहीं किया गया. डॉक्टर दम्पत्ति की रिहाई के प्रसंग में यूपी पुलिस ने कुछ बताया ही नहीं.

(शेष पृष्ठ 18 पर)

एसटीएफ ने डॉ. दम्पत्ति के बारे में क्यों छुपाया

अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी लंबी-चौड़ी प्रेस विज्ञप्ति जारी की. उसमें गिरोह के पकड़े जाने से लेकर छापेमारी की कहानी और बरामदगी का ब्यौरा सब कुछ था, लेकिन अगवा दम्पत्ति की बरामदगी और उनकी उपलब्धता का कहीं कोई जिक्र नहीं था. उसी समय एसटीएफ का पूरा ऑपरेशन प्रायोजित होने का संकेत मिल गया. अगर यह ऑपरेशन स्वाभाविक होता तो सबसे पहले मीडिया के समक्ष अपहृत डॉक्टर दम्पत्ति को पेश किया जाता. संदेह के सवाल उस समय भी खड़े हुए जब आम तौर पर अपराधियों के मुंह ढंकने में मशक्कत करते रहने वाले पुलिसकर्मी इतने शातिर अपराधियों के साथ खड़े फोटो खिंचवाते रहे. एसटीएफ ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों में 1. अजय सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी -मुठानी, थाना-रफीगंज, जिला-औरंगाबाद, बिहार, 2. मृत्युंज्य कुमार पुत्र रामलखन सिंह निवासी-कजिया, थाना-रफीगंज, जिला-औरंगाबाद, बिहार, 3.बीटू कुमार पुत्र सुजीत कुमार सोनी निवासी-अकौड़ी गोला, जिला-रोहताश, बिहार, 4. विजय कुमार पुत्र राजेन्द्र निवासी- चिकसारी, थाना-रजनीगंज, जिला-औरंगाबाद, बिहार, 5. अमित सिंह पुत्र स्व. धनन्जय सिंह निवासी- सतेन्द्रनगर, थाना व जिला-औरंगाबाद, बिहार, 6. सुनील पुत्र राजदेव निवासी- केथरवा, जिला- औरंगाबाद, बिहार, 7. अमित कुमार पुत्र मृत्युन्जय सिंह, निवासी-तिकरी, थाना-रफीगंज, जिला-औरंगाबाद, बिहार, 8. श्रवण कुमार पुत्र रमेश पासवान निवासी-बिलाई, थाना-रविनगर, जिला-औरंगाबाद, बिहार और 9. अनिल सिंह पुत्र मान सिंह निवासी-निशाननगर, वडडी, थाना-शिवसागर, जिला रोहताश, बिहार शामिल हैं. ■

अपहरण फिल्मी, रिहाई पहेली

डॉक्टर दम्पत्ति के अपहरण की इस घटना ने फिल्मी स्टाइल को भी पीछे छोड़ दिया है. लाल बत्ती लगी गाड़ी पर सवार वर्दीधारी पुलिस के जवान और बीच में दुबके बैठे अपहृत दम्पत्ति. गया के डॉक्टर पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी के अपहरण में शातिर अपराधियों ने ऐसे ही फिल्मी तरीके से काम किया. अपराधियों ने पुलिस की वर्दी में डॉ. पंकज गुप्ता को रोका. उन्हें और उनकी पत्नी को उन्हीं की ऑडी कार में पुलिस वर्दीधारी लोगों के बीच बैठाया और फिर लाल बत्ती की गाड़ी के पीछे डॉक्टर की ऑडी गाड़ी को लगाकर सांय-सांय हूटर बजाते लखनऊ पहुंच गए. डॉ. पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी को अपहरण करने के बाद लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर के शारदा अपार्टमेंट में रखा गया. दोनों के लिए एसी कमरा और टीवी जैसी सुविधाएं भी मौजूद थीं. पुलिस के लिए उन्हें खोज पाना मुश्किल था. लेकिन बिहार पुलिस को अचानक उस व्यक्ति से सुराग मिला, जिसे अजय सिंह गिरोह ने ही दो महीने अगवा किया था और उसे लखनऊ ले आए थे. सासाराम के ठेकेदार रवि रंजन सिंह उर्फ डिंपू सिंह से मिले इस सुराग पर पुलिस लखनऊ पहुंच पाई. उत्तर प्रदेश पुलिस से मदद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात की. तब दोनों राज्यों की पुलिस ने गोमतीनगर में उस अपार्टमेंट को ढूंढ़ना शुरू किया. लेकिन, अपहर्ता तभी पकड़ में आए जब उन्होंने डॉ. पंकज गुप्ता को पहले ही छोड़ दिया. डॉक्टर पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी को अपहर्ताओं ने खुद गाड़ी पर बिठाकर चारबाग स्टेशन लाकर छोड़ दिया था. ■

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार

शत्रुंजय सिंह

पूर्वी उत्तर प्रदेश की फरेंदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा से सीट छीन ली है. फरेंदा के भाजपा विधायक बजरंग बहादुर सिंह की विधायकी राज्यपाल ने लाभ के दो-दो काम एक साथ करने की शिकायत पर खारिज कर दी थी. इस वजह से फरेंदा में उप चुनाव हुआ. भाजपा ने फिर से बजरंग बहादुर सिंह को ही अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सपा ने वह सीट हथिया ली.

उप चुनाव में कांग्रेस दूसरे नम्बर पर आकर भी गदगद है. फरेंदा सीट गंवाने से भाजपा की चिंता बढ़ गई है. राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस उपचुनाव का परिणाम यूपी के राजनीतिक भविष्य के लिए संकेत दे रहा है, लेकिन सपा को अत्यंत सतर्क रहने की जरूरत है. फरेंदा उप चुनाव में आजादी के बाद पहली बार सपा प्रत्याशी विनोद मणि साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए हैं. जबकि सपा के कई ऐसे विभीषण थे जो सपा को भस्म करने का हर संभव प्रयास कर रहे थे. पर महराजगंज के प्रभारी मंत्री विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह के राजनीतिक प्रबन्धन और दुग्ध विकास मंत्री राममूर्ति वर्मा के साथ पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह की रणनीति का नतीजा रहा कि सपा को मणि मिल गए. प्रभारी मंत्री विनोद सिंह का मानना है कि यह जीत प्रदेश सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर है. फरेंदा उपचुनाव ने साबित कर दिया है कि प्रदेश में भाजपा निचले पायदान पर ही है. भाजपा एवं अन्य विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ तरह-तरह के दुष्प्रचार किए. जिसे मतदाताओं ने नकार दिया. इससे यह साबित हुआ कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में जो वादे किए थे उसके पूरा नहीं होने से भाजपा से जनता का विश्वास उठ रहा है. जनता ने युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की विकासपरक नीतियों को स्वीकारा है.

फरेंदा विधान सभा में समाजवादी पार्टी ने पहली बार अपना सीट जीत कर क्षेत्र में खाता खोला है. 1996 के विधानसभा के चुनाव में सीपीआई गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में विनोदमणि अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं. फरेंदा विधान सभा सीट से 1952 में कांग्रेस के गौरीराम ने पहला विधायक बनने का गौरव हासिल किया था. उसके वाद 1956 और 1961 में नरसिंह पांडेय ने जीत दर्ज की. 1967 में निर्दल के रूप एक बार फिर गौरीराम ने जीत दर्ज की थी. 1969 में प्यारी देवी ने जीत दर्ज कर महिला विधायक बनने का गौरव हासिल किया. 1974 में यहां से लक्ष्मी नारायण जीते. उसके बाद श्याम नारायण तिवारी को राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान के बाद लक्ष्मी नारायण ने सीपीआई से श्याम नारायण को अपना समर्थन देकर 1977 में पहली बार हर्षवर्धन सिंह को हराकर जीत हासिल की. 1980 में निर्दल प्रत्याशी के रूप में श्याम नारायण ने कांग्रेस के हरीराम को हरा कर दूसरी बार जीत दर्ज की. 1985 में जनता पार्टी के हर्षवर्धन श्याम नारायण को हरा कर जीत गए. 1989 में एक बार फिर श्याम नारायन ने भाजपा के तुलसीराम को हरा कर तीसरी बार जीत दर्ज की. 1991 में श्याम नारायण फिर भाजपा के तुलसीराम गौड़ को हरा कर चौथी बार जीते. 1993 में भाजपा के शिवेन्द्र चौधरी सीपीआई के विनोद तिवारी को मात्र 50 मतों से हरा कर जीते थे. 1996 में सीपीआई-सपा गठबंधन के विनोद मणि ने भाजपा के शिवेन्द्र चौधरी को हराया और पहली बार विधायक बने. उसके बाद 2002 में श्याम नारायन बसपा के वीरेन्द्र चौधरी को हरा कर पांचवी बार जीते. 2007 में भाजपा के बजरंग बहादुर सिंह बसपा के वीरेन्द्र चौधरी को हरा कर पहली बार विधानसभा पहुंचे. 2012 में फिर भाजपा के बजरंग बहादुर सिंह ने कांग्रेस के वीरेन्द्र चौधरी को हराया. तीन वर्ष के कार्यकाल के बाद बजरंग बहादुर सिंह लोकायुक्त की जांच में दोषी पाए गए और 28 जनवरी को राज्यपाल द्वारा उन्हें विधायक पद से बर्खास्त कर दिया गया. फरेंदा में पहली बार उपचुनाव की घोषणा हुई. इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने विनोद मणि को टिकट दिया. फरेंदा के विधायक निर्वाचित होकर उन्हें क्षेत्र का 16वां विधायक होने का गौरव मिला.

उपचुनाव काफी उठा-पटक के बाद सम्पन्न हुआ. उपचुनाव रोकने के लिए निवर्तमान विधायक ने हाईकोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली. बलिया के विधायक उमाशंकर के खिलाफ वहीं के रहने वाले अशोक सिंह ने लोकायुक्त से जांच कराने की मांग की थी. लोकायुक्त द्वारा बलिया के विधायक उमाशंकर सिंह के जांच के समय फरेंदा विधायक बजरंग बहादुर सिंह भी उसी जांच के दायरे में आ गए. लोकायुक्त ने दोनों विधायकों को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश की थी. राज्यपाल ने 27 जनवरी को बजरंग बहादुर सिंह को बर्खास्त कर फरेंदा में उपचुनाव कराने का आदेश दिया. उप चुनाव में बसपा को छोड़ सभी दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे.

फरेंदा उपचुनाव सपा की जिला इकाई में नए समीकरण गढ़ गया. इस समीकरण में अब अमरमणि खेमा नहीं, बल्कि कुंवर अखिलेश सिंह खेमा भारी पड़ रहा है. सपा की जीत से कुंवर खेमा गदगद है तो मणि खेमा भीतर से मायूस. जीत के साथ ही चर्चा शुरू हो गई है कि 2017 के चुनाव में कुंवर खेमे की ही ज्यादा चलेगी. संभव है कि जेल में बंद अमरमणि अपने बेटे को दोबारा टिकट न दिलवा पाएं और नौतनवा से सपा से चुनाव लड़ने की मुन्ना सिंह की इच्छा पूरी हो जाए.

दरअसल इस उपचुनाव से पहले जिले में अमरमणि की ही चलती थी. उनके कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी पूर्व सांसद अखिलेश सिंह और उनके विधायक भाई कुंवर कौशल किशोर सिंह उर्फ मुन्ना चाह कर भी मणि को दबा नहीं पाते थे. मणि ने चाहा तो उनके भाई को लोकसभा चुनाव का टिकट मिल गया. मणि ने चाहा तो नौतनवा से अपने बेटे को उम्मीदवार बनवा लिया. पिछले लोकसभा चुनाव में सपा ने अखिलेश सिंह को उम्मीदवार बनाया, मगर मोदी-लहर में वे चुनाव हार गए. चुनाव बाद अखिलेश और अमरमणि की प्रतिद्वन्द्विता सबके सामने शत्रुता के रूप में सामने आ गई. एक कार्यक्रम में सिर-फुटौव्वल तक की नौबत आ गई. फरेंदा उपचुनाव आया तो दोनों खेमों ने अपने-अपनों को टिकट दिलवाने के लिए सारी ताकत झोंक दी.

अमरमणि चाहते थे कि उनके चाचा एवं पूर्व मंत्री श्यामनारायण त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया जाए. लेकिन ऐन वक्त पर अखिलेश और मुन्ना सिंह ने विनोद मणि का नाम आगे बढ़ा दिया. साथ ही पार्टी हाईकमान को भरोसा दिलाया कि सीट निकाल ली जाएगी. हाईकमान ने भी मणि के बजाय दोनों भाइयों पर भरोसा जताया. अखिलेश सिंह तो सपा में हैं लेकिन मुन्ना सिंह कांग्रेस के विधायक हैं. इसके बावजूद वह पिछले लोकसभा चुनाव के समय से ही समर्पित सपाई की भूमिका निभा रहे हैं. इस उपचुनाव में भी उनकी भूमिका कांग्रेसियों को खटकती रही मगर उन पर कोई असर नहीं पड़ा. उनका सारा जोर सपा को जिताने में लगा रहा. कांग्रेस की हार का उन्हें कोई गम नहीं है. हां, सपा की जीत पर कुंवर खेमे में जश्न का माहौल जरूर है.

इस उपचुनाव में प्रदेश सरकार के ताकतवर मंत्री अरविन्द सिंह गोप, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, अहमद हसन, महबूब अली, सांसद धर्मेंद्र यादव, राज्य मंत्री विनोद सिंह उर्फ पंडित, शंखलाल मांझी, विजय बहादुर पाल, नफीस मंसूरी, रामआसरे विश्वकर्मा सहित चुनाव प्रभारी मुनीर आलम व पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह, विधायक कुंवर कौशल सिंह जैसे नेताओं की मेहनत रंग लाई. जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सपा सरकार को विधानसभा के विकास के लिए रिक्त स्थानों को विकास के ऐसे रंगों से भरना होगा कि जनता को विकास दिखाई दे तभी पार्टी के पक्ष में जनाधार बढ़ेगा.

फरेंदा के प्रतिष्ठापरक उपचुनाव में प्रदेश की प्राकलन समिति के अध्यक्ष शिवेन्द्र सिंह, महाराजगंज के सदर से सपा विधायक सुदामा प्रसाद व अमरमणि के कुनबे का उक्त चुनाव से दूरी बनाए रखना और विधान परिषद के सभापति गणेश शंकर पांडेय के लोगों द्वारा प्रचार किए जाने व विजय जलूस में शामिल होने की चर्चा जनपद में बनी हुई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सपा और भाजपा दोनों पर भारी बागी

उत्कर्ष सिन्हा

समाजवादी पार्टी के विधायक ने प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था और उस पर सरकार की चुप्पी पर बगावत का ऐलान कर दिया है. सपा के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने सपा नेतृत्व के निरंकुश रवैये के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो दूसरी तरफ भाजपा के दलित सांसद भानु प्रताप वर्मा ने भी भाजपा नेतृत्व के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है. सपा और भाजपा, दोनों ही पार्टियां अपने-अपने नेताओं के बगावती तेवर और उनके द्वारा उठाए जा रहे जनहित के मुद्दों से परेशान हैं. समाजवादी पार्टी की सरकार और सपा विधायक देवेंद्र सिंह के बीच चल रहा टकराव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है. विधायक देवेंद्र सिंह के तेवर पर नाराज हुई समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें नोटिस भेज दी है. नोटिस मिलने के बाद विधायक के तेवर और भी तीखे हो गए हैं.

सपा विधायक देवेंद्र सिंह कहते हैं कि क्या कोई पुलिस वाला आपकी मां का आंचल फाड़े, आपकी बहू-बेटियों का अपमानित करे तो क्या आपको इसलिए चुप रहना चाहिए कि सूबे में उसकी अपनी सरकार है? सपा विधायक देवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष की कोख से समाजवादी पार्टी का और समाजवादी आंदोलन का जन्म हुआ है. डॉ. लोहिया और मुलायम सिंह यादव के संघर्ष के रास्ते पर चलना यदि सरकार विरोधी काम है तो बिना समय गंवाए वे मेरे खिलाफ कठोरतम कार्रवाई कर सकते हैं. [illegible] गोरखपुर में बांसडीहा और सीसावल में [illegible] गोरखपुर के एसएसपी और उसके [illegible] के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए. सपा के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह के फेसबुक-वाल पर लिखी ये टिप्पणियां उनके बागी तेवरों की मुनादी करने के लिए काफी हैं. देवेंद्र प्रताप सिंह आजकल गोरखपुर के पुलिस कप्तान प्रदीप यादव के मनमाने और अराजक रवैये के खिलाफ आन्दोलन कर रहे हैं. पिछले दिनों देवेंद्र सिंह ने एसएसपी के खिलाफ कलक्टर आफिस पर धरना भी दिया था, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए थे. कुछ रोज पहले ही गोरखपुर में बांसडीहा और सीसावल गांव में पुलिसिया कार्रवाई के विरुद्ध सपा विधायक व भाजपा सांसद कमलेश पासवान धरना पर बैठे थे, जिसमें देवेंद्र सिंह भी शामिल हुए थे. देवेंद्र सिंह अपने छात्र राजनीति के समय से ही समाजवादी रहे हैं और बागी तेवरों के लिए जाने जाते हैं. जेपी आन्दोलन से निकले देवेन्द्र सिंह

भाजपा सांसद भानु प्रताप वर्मा

सपा नेता देवेंद्र प्रताप सिंह

ने पूर्वांचल के विश्वविद्यालयों में छात्र नेताओं की एक पूरी पौध तैयार की है. सूबे में समाजवादी पार्टी के गठन के समय से ही वे सपा के साथ हैं और पूर्वांचल में राजपूतों पर योगी आदित्यनाथ के असर को रोकने और उसे समाजवादी पार्टी की तरफ लाने में भी उन्हीं की बड़ी भूमिका रही है. विधान परिषद में शिक्षकों और जनहित के सवालों को लेकर [illegible] आगे निकल जाने वाले देवेंद्र सिंह का यह बागी तेवर एसएसपी प्रदीप यादव के खिलाफ है. गोरखपुर में तैनाती के बाद से ही प्रदीप यादव का कार्यकाल विवादित रहा है. प्रदीप यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप तो लग ही रहे हैं सपा के जनप्रतिनिधियों से बदसलूकी भी उनकी कार्यशैली में शामिल है. इसी कड़ी में उन्होंने बांसगांव थाना क्षेत्र में क्षेत्रीय सांसद के साथ भी बदसलूकी कर दी थी. मौके पर पहुंचे एमएलसी के भाई और खुद एमएलसी के साथ भी उनका

व्यवहार ठीक नहीं रहा था. एसएसपी प्रदीप यादव के खिलाफ जब देवेन्द्र सिंह ने मोर्चा खोला तो सूबे की सत्ताधारी पार्टी ने उल्टा देवेन्द्र सिंह को ही नोटिस भेज दिया. [illegible] है. वर्मा के अनुसार नरेन्द्र मोदी जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी मसर्रत आलम की रिहाई में मदद करते हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराने और जिंदाबाद करने वाले गिलानी को रैली की अनुमति देते हैं. अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव, आडवाणी के राम रथयात्रा को रोकने वाले लालू

[illegible] कार्यकर्ताओं ने बड़े सपने बुने हैं, मगर लगातार हारते उपचुनावों और संगठन के नेतृत्व में गंभीरता के अभाव ने उनके उत्साह को कम कर दिया है. हालांकि पार्टी ने इसके लिए कार्यशालाओं और एक लम्बे कार्यक्रम की घोषणा कर दी है मगर पार्टी के भीतर उभर रहे असंतोष को शांत करने में अभी बहुत कुछ करना बाकी है.

पृष्ठ 17 का शेष

गिरोह का लखनऊ-हेल्पर कौन, पुलिस मौन

डॉक्टर दम्पत्ति के अपहरण की घटना पर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं. वाकया गया के बड़े चिकित्सक डॉ. पंकज गुप्ता और शुभ्रा गुप्ता के अपहरण का था. लिहाजा, यह मामूली अपहरण की घटना नहीं थी. बिहार में किसी महिला को भी साथ-साथ अगवा कर ले जाने की घटना संभवतः पहली ही घटना है. यह बिहार पुलिस के सामने चुनौती की तरह थी, लेकिन क्राइसिस-मैनेजमेंट में निपुण अधिकारियों का भी बिहार में उतना ही अकाल है. लखनऊ ऑपरेशन के दो ही दिन पहले चर्चित आईपीएस कुंदन कृष्णान को पटना का जोनल आईजी बनाया गया था. बिहार काडर के दूसरे लायक अधिकारी आरएस भट्टी अभी सीबीआई में तैनात हैं. लेकिन उनसे भी ऑफ-रिकॉर्ड मदद ली गई. तेज-तर्रार आईपीएस मनु महाराज भी इस मामले में मददगार रहे.

बिहार के अपहरण-उद्योग के कारनामों और उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका पर थोड़ा गौर करते चलें. जनवरी 2012 में वाराणसी से आसनसोल जाते समय बड़े उद्योगपति अनिल अग्रवाल का अपहरण भी गया के फोरलेन से ही किया गया था, जैसा डॉक्टर दम्पत्ति के साथ हुआ. करीब महीनेभर बाद अनिल अग्रवाल अपहर्ताओं के चंगुल से छूट कर लौटे थे. पांच करोड़ की फिरौती वसूली गई थी. भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण

दुस्साहसिक अपहरण की फिसड्डी रिहाई-कथा

सिंह के रिश्तेदारों के अपहरण मामले में भी मर्जी सिर्फ अपहर्ताओं की ही चली. पुलिस पुख्ता तौर पर किसी गिरोह को सामने नहीं ला सकी. सुर्खियों में रहे सूरत के सोहेल हिंगोरा अपहरण मामले में भी गिरोह सरगना पकड़ में नहीं आ सका. डॉ. पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी शुभ्रा गुप्ता का अपहरण भी उन्हीं की ऑडी गाड़ी से हुआ. थोड़ा फ्लैश-बैक में आएं तो ऐसे गिरोह को खंगालने और लखनऊ-लिंक तलाशने के लिए लखनऊ के उद्योगपति संजय झुनझुनवाला के अपहरण-कांड को भी देखना चाहिए. झुनझुनवाला को भी अपहरणकर्ता एसटीएफ के वेश में आकर 6 जून 2001 को उठा ले गए थे. नेशनल हाइवे पर अपहरण करने के विशेषज्ञ गिरोह की तलाश में बिस्कोण स्पॉन्ज आयरन के मालिक कृष्णा भालोटिया अपहरण कांड की फाइल को भी जांचा जा रहा था. भालोटिया की रिहाई भी फिरौती देने के बाद ही हुई थी. जहां तक डॉ. पंकज गुप्ता दम्पति के अपहरण का सवाल है, उसमें फिरौती के लिए कोई फोन कॉल नहीं किया

गया. अपहरणकर्ता चालाक निकले. फिरौती भी वसूल ली और कोई जान भी नहीं पाया. विशेषज्ञों का मानना है कि गिरोह के कुछ और सदस्य बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं और उनके सफेदपोश होने की अधिक संभावना है. अजय सिंह गिरोह अपराध की दुनिया के अपने सीनियर्स श्रीप्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की मोडस-ऑपरेंडी अपना रहा है. यह गिरोह उस प्रदेश के अपराधियों को भी अपने साथ शरीक करते थे, जहां माल (अपहृत व्यक्ति) छुपा कर रखा जाता था. अजय सिंह गिरोह द्वारा लखनऊ में एक अपार्टमेंट को पहले से ही किराए पर ले लेना और उसमें अगवा दम्पत्ति को छुपा कर रखना, स्थानीय अपराधियों की मदद के बगैर संभव ही नहीं है. लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा. एसटीएफ अपनी बहादुरी का श्रेय और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा दिए गए पांच लाख रुपये में से अपना-अपना हिस्सा बांटने में ही लगी है.

कई राज्यों में चलता था अजय सिंह गिरोह का काम

डॉक्टर दम्पत्ति को अगवा करने वाले अजय सिंह गिरोह का काम बिहार, उत्तर प्रदेश, ओड़ीशा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्यप्रदेश, गुजरात, दिल्ली और मुम्बई तक चल रहा था. एक राज्य से अपहरण कर उसे दूसरे राज्य में छुपा कर रखने और किसी अन्यत्र जगह पर फिरौती की रकम वसूलने में इस गिरोह को महारत हासिल है. 1995 में बोकारो के बड़े व्यवसायी सुशील गर्ग को अगवा कर अजय सिंह ने अपहरण-उद्योग में अपनी हाजिरी लगाई थी. सुशील गर्ग के परिवार से कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट पर फिरौती की रकम ली गई थी. हजारीबाग के लक्ष्मी सीमेंट के मालिक को अगवा कर पटना में करीब पांच करोड़ की फिरौती वसूली गई थी.

वर्ष 2003 में जयपुर के दुर्लभ ज्वैलर्स श्रृंखला के मालिक की पत्नी सुमेधा को अगवा कर उन्हें 18 दिन तक दिल्ली में रखा गया था, जबकि दुर्लभजी परिवार लालकृष्ण आडवाणी का अत्यंत करीबी है. अजय सिंह बाद में पकड़ा गया था, लेकिन उसके पहले ढाई करोड़ की फिरौती वसूल ली गई थी. अजय सिंह गिरोह ने ही राजस्थान में प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठान कोटावाला के मालिक को भी अगवा किया था. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक इंजीनियर को भी अगवा कर फिरौती वसूली थी. ■

feedback@chauthiduniya.com

खनन माफियाओं का राज

न पहाड़ बचेगा न मैदान

सूफी यायावर

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर खनन माफियाओं का राज बढ़ता जा रहा है. दोनों प्रदेश की सरकारें खनन माफियाओं के आगे नतमस्तक हैं. खनन माफियाओं की तरफ से सत्ता अलमबरदारों को मोटा चढ़ावा मिलता रहता है और खनन का गोरखधंधा निर्बाध गति से चलता रहता है. उत्तर प्रदेश में खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की अकूत सम्पत्ति का मामला लोकायुक्त की अदालत में चल ही रहा है. उत्तर प्रदेश में खनन माफियाओं द्वारा पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और वन अधिकारियों पर हमले की खबरें आती ही रहती हैं. अभी पिछले दिनों उत्तराखंड में सीमाई इलाके रामनगर में तैनात ट्रेनी आईएफएस अफसर कल्याणी बिष्ट पर खनन माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया. इसके पहले उन्हें धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने अवैध खनन से जुड़े मामलों में पड़ताल बंद नहीं की तो उनकी हत्या कर दी जाएगी. वन अधिकारी कल्याणी ने खुद बताया, हमें इलाके में अवैध खनन की शिकायत मिली थी. इसके बाद मैं अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची. वहां पहुंचते ही मौके पर मौजूद सात ट्रक मौके से फरार हो गए. हमने एक ट्रक का पीछा करना शुरू किया तो स्कूटर और बाइक पर सवार करीब 40-50 लोग वहां आ गए. उन्होंने अपने चेहरे को नकाब से ढंका हुआ था. उनके हाथों में तलवारें थीं. एक एसयूवी हमारे पास आई और उसमें सवार एक व्यक्ति ने कहा कि अगर हम वापस लौटकर यहां आए तो वे हमें जान से मार देंगे. हम कम लोग थे, इसलिए हमने उनसे बहस नहीं की और वापस लौट आए. वन अधिकारी के मुताबिक इस तरह काम करना बेहद मुश्किल है. ग्राउंड स्टाफ बुरी तरह डरा हुआ है और उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है. दोनों राज्यों की सरकारें निश्चिंत हैं. जबकि हाल ही कर्नाटक के कोलार जिले में रेत माफियाओं से टक्कर लेने वाले आईएएस अफसर डीके रवि की हत्या कर दी गई थी, जिसे संदेहास्पद मौत बताया गया था. इसी तरह मध्य प्रदेश के मुरैना में भी रेत माफियाओं ने आईपीएस अफसर नरेंद्र कुमार को कुचल कर मार डाला था.

उत्तराखंड में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने में वे उत्तर प्रदेश के माफियाओं की नकल कर रहे हैं. सीमा पर दोनों तरफ के माफिया मिल जुल कर काम करते हैं. आईएफएस अधिकारी कल्याणी उत्तराखंड के तराई पश्चिमी वन प्रभाग में तैनात हैं. दाबका नदी के बैतखेड़ी गेट पर अवैध खनन निर्बाध गति से हो रहा है. शिकायत मिलने पर कल्याणी अन्य वनकर्मियों के साथ मौके पर पहुंची थी. महिला अधिकारी पर हमला करने के मामले में पुलिस ने बाजपुर के जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किन्दा सहित 50 लोगों के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. कल्याणी ने रामनगर कोतवाली में तहरीर देकर सुरक्षा की गुहार भी लगाई है. कुलविंदर सिंह किन्दा पर पहले भी वनकर्मियों के दल पर जानलेवा हमले करने के केस दर्ज है. वह भाजपा का वरिष्ठ ब्लॉक प्रमुख भी रहा है, लेकिन अब कांग्रेस का जिला पंचायत सदस्य है. एक कैबिनेट मंत्री का खासमखास बताया जाने वाले किन्दा की दबंगई इलाके में बढ़ती ही जा रही है. सीमाई इलाके पर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बरेली, बदायूं के खनन माफियाओं के साथ मिल कर किन्दा अपना धंधा चलाता है और आतंक का साम्राज्य बना कर रखता है.

साफ है कि दोनों प्रदेश के मंत्रियों और नौकरशाहों की शह पर नदियों का खजाना लूटा जा रहा है. दोनों राज्यों की ऐसी कोई नदी नहीं बची है, जिसमें अवैध तरीके से खनन नहीं हो रहा है. स्वामी निगमानंद जैसे लोगों के बलिदान के बाद भी दोनों राज्य सरकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा. उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार हजारों करोड़ से अधिक है. उत्तर प्रदेश में आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के बाद दर्जनों ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो यह बताती हैं कि यूपी सरकार और खनन माफियाओं के बीच गहरी साठगांठ है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के माइनर्स और मिनरल माइनिंग ऐक्ट में 35 वां संशोधन किया. इस संशोधन के जरिए सरकार ने 2 मीटर तक की खुदाई को खनन की श्रेणी से बाहर कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के खनन के लिए एनओसी लिया जाना आवश्यक था, लेकिन राज्य सरकार ने इसमें संशोधन कर खनन माफियाओं की मदद की. अखिलेश सरकार खनन माफियाओं की मदद के लिए प्रतिबद्ध है. खनन मंत्री गायत्री प्रजापति के भ्रष्ट कारनामों के उजागर होने के बावजूद मुख्यमंत्री का सीधा संरक्षण खनन के अकूत फायदों का बयान है. इसी तरह की स्थिति उत्तराखंड में है, जहां मंत्रियों और दबंगों के इशारे पर उनके कारिंदे नदियों को खोदने में लगे हैं. इसमें कांग्रेस सरकार के मंत्रियों की पूरी तरह शह है. हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अवैध खनन को लेकर सरकारों पर तल्ख टिप्पणियां कर चुके हैं, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता. देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार, श्रीनगर, उत्तरकाशी और कुमाऊं के नैनीताल-ऊधम सिंह नगर की नदियों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है. उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे ऊधम सिंह नगर में धड़ल्ले से खनन हो रहा है. ऊधम सिंह नगर जिले में बाजपुर, किच्छा और सितारगंज की नदियों में प्रतिबंध के बावजूद अवैध खनन चल रहा है. खनन माफिया पर प्रशासन का कोई जोर नहीं है. बाजपुर क्षेत्र में भी अवैध खनन जारी है. उधम सिंह नगर के बन्नाखेड़ा, बेतखेड़ी, गोबरा घाट, कोसी घाट तथा घोंघा नदी, बोर नदी, गडप्पू स्थित नाले आदि क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी खनन जारी है. कोसी में खनन के लिए पट्टाधारकों को बहकर आए रेत उठाने की अनुमति मिलती है, लेकिन पट्टाधारक अपने पट्टे की पैमाइश से ज्यादा नदी खोद रहे हैं. हाईकोर्ट का आदेश है कि कोसी नदी से करीब दस फुट तक ही खनन हो सकता है, लेकिन खनन अधिकारी व प्रशासन की मिलीभगत से खनन माफिया करीब 15 से 18 फुट तक कोसी खोद चुका है. गडप्पू नाले से खनन कर दोराहा नैनीताल मार्ग से बरहैनी-कालाढूंगी के बीच से रोजाना सैकड़ों डंपर चोरी के रेत लेकर गुजरते हैं. इस मार्ग पर वन विभाग की चौकी, बरहैनी चौकी तथा कोतवाली है, लेकिन मिलीभगत के चलते कुछ नहीं होता. किच्छा तहसील क्षेत्र में गोला नदी से

सिरौली के नजदीक, सितारगंज क्षेत्र के साधुनगर गांव, कैलाश नदी, कटना नदी, नंधौर नदी में रात में जमकर अवैध खनन हो रहा है. शहर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक की तरफ से रेत लेकर आने वाले ट्रकों की कतारें जिला प्रशासन की मिलीभगत बताती हैं.

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी अवैध खनन चल रहा है. नदियों में बड़ी मात्रा में पत्थर, रेत और बजरी जमा है. बाढ़ से हर नदी में खनन सामग्री का ढेर लग हुआ है. नेताओं की मिलीभगत से खनन माफिया बेफिक्र होकर नदियों को लूटने में लगा है. अवैध खनन से हर माह सरकार को अरबों रुपये की चपत लग रही है. देहरादून जिले में डोईवाला, बालावाला मियांवाला में सौंग, मोथरोवाला-नकरौंदा नागल-बुल्लावाला में सुसवा और प्रेमनगर में शीतला नदी में अंधाधुंध खनन चल रहा है. जिले की हर नदी में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है और सुबह से शाम तक सैकड़ों ट्रालियां, डंपर-ट्रक खनन सामग्री लेकर निकल रहे हैं. नेता और प्रशासन को मोटा चढ़ावा मिल रहा है. शिवालिक वृत्त देहरादून, वनप्रभाग मसूरी, वन प्रभाग कालसी, देहरादून डिवीजन के सौरना व सौंग नदी, कालसी डिवीजन के शीतला और यमुना नदी के तट पर, मसूरी वन प्रभाग के मालदेवता, नथुवावाला, बालावाला, कालीमाटी, रायपुर व सहस्रधारा आदि क्षेत्रों में अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है.

हरिद्वार जिले में खनन माफिया बेखौफ होकर गंगा व उसकी सहायक नदियों से रेत, बजरी, पत्थर व बोल्डर निकाल रहे हैं. हालात यह कि लक्सर-हरिद्वार रोड पर गंगा किनारे के गांवों में लगे अधिकांश स्टोन क्रशरों पर रोक लगने के बाद पहले से ज्यादा स्टॉक नजर आ रहा है. अवैध खनन का अधिकांश माल उत्तर प्रदेश जा रहा है. गंगा किनारे विशनपुर कुंडी से लेकर लक्सर के भिक्कमपुर क्षेत्र तक गंगा किनारे के गांवों महतौली, भोगपुर, हरसीवाला, भोवापुर, टांडा, धारीवाला, रानीमाजरा, बिशनपुर, कुंडी सहित सभी घाटों पर दिन ढलते ही माफिया की जेसीबी, ट्रक, ट्रैक्टर-ट्राली धड़ल्ले से अवैध खनन करती हैं. खनन माफिया गंगा के साथ उसकी सहायक नदियों बाणगंगा, सोलानी सहित अन्य नदियों में भी अवैध खनन कर रहे हैं. खनन माफिया के बढ़ते हौसलों पर दोनों राज्य सरकारों की चुप्पी एक गंभीर सवाल बन कर खड़ी है. देहरादून और लखनऊ के बाद अब दिल्ली तक धरना-प्रदर्शन हो रहे हैं. लेकिन हालात बदल नहीं रहे.

खनन मंत्री पर लोकायुक्त की कार्रवाई जारी

उत्तर प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के भ्रष्टाचार और उसके जरिए कमाई गई अकूत सम्पत्ति के मामले में लोकायुक्त अदालत की कानूनी प्रक्रिया चल रही है. पिछले दिनों खनन मंत्री ने लोकायुक्त अदालत में दाखिल हलफनामे में खुद को पाक साफ और धुला हुआ बताया. तो इसके जवाब में सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ दायर परिवाद में लोकायुक्त जस्टिस एनके मल्होत्रा के समक्ष प्रजापति और उनके परिवार वालों की सम्पत्ति की कई महत्वपूर्ण जानकारियां सौंपीं. नूतन ठाकुर ने प्रजापति की पत्नी महराजी, पुत्री सुधा और अंकिता (ग्राम परसावा), पुत्र अनुराग (दिलकुशा रोड), और अनिल (इन्द्रजीत खेड़ा, अमेठी), (ग्राम परसावा) के नाम पर अक्टूबर 2013 से अब तक अर्जित कई सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया. इसके अलावा प्रजापति के पुत्र अनिल प्रजापति के डायरेक्टरशिप वाली फर्म लाइफ क्योर मेडिकल सेंटर (प्रतापगढ़, अमेठी), शुभांग एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (अमेठी, इन्द्रजीत खेड़ा) और डिसेंट कंस्ट्रक्शन (इन्द्रजीत खेड़ा) की सम्पत्ति का भी विवरण लोकायुक्त के समक्ष दिया गया. प्रजापति के यहां काम करने वाले देवतादीन की महमूदपुर में सात सम्पत्तियों के साथ खनन मंत्री की सरकारी गाड़ी चलाने वाले रामराज के नाम इन्द्रजीतखेड़ा में खरीदी गई 15 सम्पत्तियों और मंत्री की प्राइवेट गाड़ी चलाने वाले रामसहाय के नाम खरीदी गई 10 सम्पत्तियों का विवरण भी लोकायुक्त को दिया गया.

ग्राम पंचायत परसावा में अन्त्योदय योजना में खनन मंत्री के तीन भाई जगदीश, छेदीराम और श्रीराम के बीपीएल सूची में नाम होने के साक्ष्य भी लोकायुक्त को सौंपे गए. नूतन ठाकुर ने खनन मंत्री गायत्री प्रजापति द्वारा वर्ष 2012 में अमेठी विधान सभा के लिए भरा फॉर्म प्रस्तुत किया जिसमें उनकी पत्नी और बच्चों का आयकर रिटर्न शून्य दिखाया गया है और उनके पूरे परिवार में मात्र कुछ सम्पत्ति ही दिखाई गई है. ठाकुर ने खनन मंत्री के खिलाफ लोकायुक्त को शिकायत भेजने वाले अमेठी निवासी महेंद्र कुमार को साक्ष्य के रूप में तलब करने का भी अनुरोध किया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

अमित शाह ने प्रदेश नेताओं को लगाई फटकार

राजकुमार शर्मा

भाजपा कार्यकर्ताओं में जान फूकने लिए उत्तराखंड दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि आने वाली तीन दशक तक देश पर अब भाजपा का ही नेतृत्व रहेगा. अमित शाह के उत्तराखंड दौरे से उत्साहित प्रदेश भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला. लेकिन अमित शाह ने उत्तराखंड में भाजपा के घटते जनाधार के कारण प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को कड़ा फटकार भी लगाई. उन्होंने कहा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लगातार भाजपा विधानसभा चुनाव जीतती आ रही है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? शाह के सवाल ने भाजपा के दिग्गजों की परशानी बढ़ा दी है और शाह के सवाल यक्ष प्रश्न गए हैं. अमित शाह को पार्टी में उभरी गुटबाजी के साथ हरीश रावत के नेतृत्व में बढ़ती कांग्रेस की चिंता भी पूरे कार्यक्रम में दिखाई दी. शाह ने जिस प्रकार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हमला किया और कहा कि हम लोग इटली से नहीं आए हैं. सरकार में बैठे लोग देश के ही हैं. इसमें भाजपा और अमित शाह की बौखलाहट साफ नजर आती है. भाजपा उत्तराखंड में कभी अर्श पर होती है तो कभी फर्श पर. 2009 में भाजपा उत्तराखंड में लोकसभा की पांचों सीट गवाने के बाद 2012 में हुए उत्तराखंड विधासभा चुनाव में सत्ता भी गंवा बैठी. उसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मोदी लहर के कारण पांचों सीटों पर जीत हासिल की और भाजपा को लगा कि उसके अच्छे दिनों की शुरूआत हो चुकी है. लेकिन भाजपा की यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, क्योंकि उसके बाद खाली हुई विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को कांग्रेस के हाथों हार का सामना करना पड़ा. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं को चेतावनी दी कि आपसी कलह छोड़कर जनता की सेवा जुट जाने जाएं. अमित शाह 2017 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में पार्टी को नई शक्ल देने की तैयारी कर चुके हैं. अमित शाह ने मोदी सरकार के कामों की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री लिखा भाषण पढ़ते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेशों में हिन्दी में भाषण देते हैं और वहां पर बसे भारतीय उनके हिन्दी भाषण को सुनकर खुश होते हैं. शाह भूमिअधिग्रहण बिल और किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि सरकार अब पहले से अधिक मुआवजा दे रही है और सरकार किसान विरोधी नहीं है. उन्होंने कहा कि किसानों की एक इंच जमीन कॉरपोरेट को नहीं दी जाएगी. विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है.

उत्तराखंड में हुए विधानसभा उपचुनावों में लगातार भाजपा की हार अमित शाह की चिंता का विषय है. भाजपा अपना स्थाई जनाधार बचाने कामयाब नहीं हो पा रही है और यही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सबसे बड़ी चिंता कारण है. हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के बढ़ते जनाधार को देखते हुए अमित शाह ने अपने संबोधन में प्रदेश भाजपा नेताओं को एकजुटता का पाठ भी पढ़ाया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के नेता और कार्यकर्ता एक हो जाएं तो भाजपा शाषित राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी भाजपा को लगातार कामयाबी मिलना तय है. तब पांच साल भाजपा और पांच साल कांग्रेस की बजाए, भाजपा ही भाजपा सत्ता में होगी. लेकिन अमित शाह के सामने भी गुटबाजी साफ दिखाई दी. मिनी कोरग्रुप की बैठक भी हंगामेदार रही. अमित शाह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आपसी जंग खत्म नहीं हुई तो 2017 में भाजपा का सत्ता में आना संभव नहीं है. प्रदेश के भाजपा मीडिया प्रबंधन पर भी सवाल खड़े हुए और आरोप लगाया गया कि प्रदेश भाजपा कुछ लोगों के हाथों में कैद होकर रह गई है. निर्धारित कार्यक्रम के तहत बंद कमरे में सवाल-जवाब शुरू होते ही विधायकों ने प्रदेश पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की बौछार कर दी. अंततः संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े पदाधिकारियों ने अमित शाग को सलाह दी कि वे विधायकों से होने वाले सवाल-जवाब को टाल दें वरना फजीहत होगी. विधायकों के तल्ख तेवर को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) रामलाल व सह महामंत्री (संगठन) शिवप्रकाश ने भांप लिया और प्रदेश पदाधिकारियों के खिलाफ जहर उगल रहे विधायकों को भी शांत कराया. और कहा कि ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे पार्टी की फजीहत हो.कुछ विधायकों को यह भी भरोसा दिया गया कि वे दिल्ली आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलें. सभी की बात सनी जाएगी और जो जरूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे. विधायकों की बैठक टलने के बाद काफी चिंतन-मंथन हुआ. फिर प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक शुरू हुई. जिसमें प्रदेश के तीनों पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी, भगत सिंह कोश्यारी व डा.रमेश पोखरियाल निशंक के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल सहित एक दर्जन से ज्यादा प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी शामिल हुए. पहले से ही गुटबाजी की फीड बैक ले चुके शाह ने सभी वरिष्ठों को जमकर फटकार लगाई और कहा कि लड़ाई बंद कमरे में हो तो कोई दिक्कत नहीं. संगठन को सशक्त करने के मकसद से बातचीत तो होनी चाहिए पर जिस तरह से वरिष्ठ आपस में उलझ रहे हैं. इससे तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि मिशन 2017 का डगर भाजपा के लिए सहज नहीं है. अमित शाह ने कहा कि मिशन-2017 का रोड मैप सभी लोग मिल कर तैयार करें. प्रदेश मिनी कोर ग्रुप की बैठक दो साल से नहीं होने पर भी शाह ने वरिष्ठ नेताओं को जमकर फटकारा और कहा कि गुटबाजी की खबर दिल्ली तक है. शाह ने चेतवानी दी कि सुधर जाए नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें.नई पीढ़ी की ओर भी शाह ने स्पष्ट रूप से संकेत दिए और कहा कि भाजपा हाईकमान प्रदेश और संगठन हित में आने वाले दिनों में जरूरी फैसला भी ले सकता है. शाह ने दुःख व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि भाजपा विपक्ष में है ,जिस तरह से भाजपा का तेवर सड़क से सदन तक होना चाहिए, वह नहीं दिख रहा है. शाह ने यह भी कहा कि मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए सभी वरिष्ठ बेचैन हैं, लेकिन प्रदेश में संगठन में धार कहां से आए. इसकी चिंता किसी को भी नहीं है. मोदी सरकार के एक वर्ष पूरे होने वाले हैं लेकिन जनता के अच्छे दिन कब तक आएंगे किसी को नहीं पता. अमित शाह मीडिया के सवालों के जवाब डर से मीडिया दूरी बनाए वापस लौट गए.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने शाह पर करारा हमला करते हुए कहा कि यह देश और भाजपा का दुर्भाग्य है कि गुजरात का तडीपाल घोषित व्यक्ति को मोदी के इशारे पर देश का भाग्य विधाता बना कर घुमाया जा रहा है. जिस कुर्सी को राजनाथ, जोशी जैसे लोग संभाल चुके है इस पर संघ परिवार के लोगों भी सोचना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड क्रांति दल में फूट

आर. के. शर्मा

उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाली उत्तराखंड क्रान्ति दल का संकट अभी भी वैसा ही बना हुआ है. अहम की लड़ाई की वजह से कई बार टूट चुकी उक्रांद भले ही जनता के विश्वास को खो चुकी हो, लकिन इस दल के बड़े नेता अपने अहम को अभी भी नहीं त्याग पा रहे हैं. जनदबाव के कारण एकता के लिए मिले हाथ भी दिल को नहीं मिला पा रहे हैं. उक्रांद में हुए बिखराव के बाद कई गुटों में बटे दल को जनता ने भी नकार दिया है. 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में उक्रांद की ओर से एकमात्र विधायक प्रीतम सिंह पंवार ही दल को सीढ़ी चढ़ा सके और उनके सरकार में शामिल होने के बाद उक्रांद कई टुकड़ों में बंट चुकी है. 2017 में विधानसभा चुनाव तो देखते हुए उक्रांद को एकजुट होने का एहसास होने लगा है. काशी सिंह एरी के नेतृत्व वाली उक्रांद की ओर से विगत दिनों किए गए प्रयासों के चलते उक्रांद(पी) उक्रांद (जुयाल) व उक्रांद (डी) के विलय की घोषणा की गई. तब से ही लगने लगा था कि इस एकता में जल्द ही दरार पड़ जाएगी. उक्रांद (पी) के अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवार इस शर्त के साथ एका के लिए तैयार हुए की महाधिवेनश में उन्हें ही दल का अध्यक्ष घोषित किया जाए. लेकिन ऐरी का कहना है कि अध्यक्ष पद तो महाधिवेशन में ही तय होगा. एका के लिए पंवार को ऐरी की ओर से महाधिवेशन बुलाने और महाधिवेशन का संयोजक नियुक्त किया गया था, अब महाधिवेशन से पहले सभी मुद्दों पर एक राय कायम करने के लिए पंवार कीओर से 6 मई को बुलाई गई बैठक से पहले ही ऐरी गुट ने कार्यसमिति की बैठक कर महाधिवेशन के लिए 16-17 मई की तारीख घोषित कर नये संयोजक की घोषणा कर दी है. जिसके कारण पंवार और एरी के बीच दरार पड़ गई है. वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी के बयान के बाद त्रिवेन्द्र सिंह पंवार ने भी काशी सिंह ऐरी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली. उन्होंने कहा कि काशी सिंह ऐरी मुख्यमंत्री हरीश रावत के पिछलग्गू बने हुए हैं. वह नहीं चाहते कि दल में एकता हो. इसलिए वह कई मुद्दों पर सहमति बनने के बाद अब इसे नकार रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐरी को स्पष्ट करना चाहिए कि वह कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे हैं या नहीं. पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंवार ने कहा कि राज्य में कांग्रेस-भाजपा का विकल्प बनाने के लिए दल में एका के प्रयास किये जा रहे हैं, इन प्रयासों को सत्ता की चाकरी करने वाले कुछ नेता पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी में ऐरी और वे मुख्य धड़े हैं. एका की बात भी सबसे पहले हम दोनों धड़ों के नेताओं के बीच हरिद्वार में हुई थी. इस बैठक में कुछ बातों पर सहमति भी बनी थी लेकिन ऐरी आज कुछ लोगों के दबाव में आकर बनी सहमति को नकार रहे हैं. जो पार्टी की एकता के लिए सही नहीं है. उन्होंने कहा कि पूर्व में भी हम लोगों में जो असहमति रही वह कांग्रेस सरकार को समर्थन को लेकर थी. वर्तमान में भी यही सहमति एका में बाधा बन रही है. उन्होंने कहा कि आज भी काशी सिंह ऐरी मुख्यमंत्री हरीश रावत के पिछलग्गू बने हुए हैं. आज भी वह मुख्यमंत्री द्वारा बनायी गई समिति में सलाहकार हैं. उन्होंने कहा कि जब वह मुख्यमंत्री को ही सलाह देंगे तो भाजपा कांग्रेस का विकल्प उक्रांद कैसे बनेगा. उन्होंने कहा कि ऐरी को स्पष्ट करना चाहिए कि वह कांग्रेस के साथ है या नहीं. उन्होंने कहा कि पार्टी की मजबूती से ज्यादा चिंता इन्हें कांग्रेस को सत्ता में बने रहने की है. ■

> उक्रांद (पी) के अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवार इस शर्त के साथ एका के लिए तैयार हुए की महाधिवेनश में उन्हें ही दल का अध्यक्ष घोषित किया जाए. लेकिन ऐरी का कहना है कि अध्यक्ष पद तो महाधिवेशन में ही तय होगा. एका के लिए पंवार को ऐरी की ओर से महाधिवेशन बुलाने और महाधिवेशन का संयोजक नियुक्त किया गया था.

feedback@chauthiduniya.com

> नेपाल सीमा से लगे इलाकों में मानव तस्करी कोई नई बात नहीं है. मासूम बच्चियों से लेकर बड़ी लड़कियों को देह व्यापार के दलदल में झोंकने का गोरखधंधा अर्से से जारी है. बड़ी उम्र की महिलाओं को भी तस्करी के जरिए देह व्यापार के हवाले किया जा रहा है. महिला आयोग तक केंद्र सरकार से यह कह चुका है कि नेपाल, बांग्लादेश सीमा पर महिलाओं और लड़कियों की तस्करी बहुत होती है, इसके लिए कड़ी निगरानी और सख्त कानून की जरूरत है.

त्रासदी से पीड़ित महिलाओं और बच्चों की तस्करी

वैष्णवी वंदना

पड़ोसी देश नेपाल भूकंप से भी ज्यादा त्रासदी झेल रहा है. भूकंप के कारण तबाह हुए देश में भुखमरी और किल्लत से त्रस्त होकर वहां के लोग, महिलाएं और बच्चे अन्यत्र भागने पर विवश हो रहे हैं. इसका फायदा उठा रहे हैं मानव तस्करों के गिरोह, जो भारत या अन्य देशों में रोजदार दिलाने के नाम पर महिलाओं को वेश्यावृत्ति और बच्चों को बंधुआ मजदूरी की सुरंग में धकेल रहे हैं. नेपाल से लगे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने इस बारे में अलर्ट भी जारी किया है. नेपाल सरकार ने अपने देश से हो रही मानव तस्करी के बारे में पड़ोसी देश भारतवर्ष को सूचित किया है. प्रलयंकारी भूकंप और उसके बाद पीड़ित परिवारों के पलायन का फायदा मानव तस्कर उठा रहे हैं. खासकर महिलाओं और किशोरों को मानव-व्यापार का शिकार बनाया जा रहा है. इसे देखते हुए पुलिस को सतर्क कर दिया गया है. भारत-नेपाल के सीमावर्ती इलाके में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है. उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कहा गया है कि भूकंप के कारण बड़ी संख्या में नेपाल और बिहार के सीमावर्ती इलाके में पीड़ितों का आना जारी है. इनके लिए बड़े पैमाने पर राहत कार्य भी चलाए जा रहे हैं. इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और किशोर हैं. शासन ने आशंका जताई है कि भूकंप में अपना बहुत कुछ गंवा चुके इन लोगों की मजबूरी का फायदा मानव तस्कर उठा सकते हैं. मानव व्यापार का शिकार होने से महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विभिन्न एजेंसियों के साथ तालमेल स्थापित कर काम करने का निर्देश दिया गया है. इसके तहत जिला पुलिस, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), रेल पुलिस और दूसरी सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं.

जिलों के पुलिस अधीक्षकों के अलावा जोनल आईजी और रेंज डीआईजी को भी मानव-व्यापार निरोधी अभियान की समीक्षा का निर्देश दिया गया है. साथ ही सभी चार रेल जिलों के एसपी और अन्य जिलों की भी पुलिस को तत्पर रहने को कहा गया है. इसका मकसद आवागमन के दौरान मानव-व्यापार के पीड़ित व्यक्तियों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करना है. नेपाल में आए जानलेवा भूंकप के बाद मानव तस्करी किए जाने की खबर ने खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं. भूकंप के बाद से पड़ोसी देश में हाहाकार मचा हुआ है. इसी दौरान यूपी की सीमा से सटे नेपाली इलाकों से बच्चों, लड़कियों और महिलाओं को तस्करी कर भारत लाए जाने की खबर मिली. इस जानकारी के बाद सरकार ने अलर्ट जारी किया और नेपाल सीमा से लगे जनपदों में चौकसी बढ़ा दी गई. सभी सीमा चौकियों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है. इसके साथ ही नेपाल से आने वाले विमानों पर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट और वाराणसी एयरपोर्ट पर भी खास निगरानी रखी जा रही है. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) पर भी मुस्तैदी बरतने को कहा गया है. सीआईएसएफ को भी अलर्ट किया गया है. खासतौर पर उन यात्रियों पर नजर रखी जा रही है जो पहली बार नेपाल से हवाई यात्रा कर रहे हैं. उनके दस्तावेजों की भी सख्ती से जांच की जा रही है. भारत और नेपाल की सीमा 1,751 किलोमीटर लंबी है. दोनों देशों के नागरिक सीमा के पार बेरोक-टोक आ-जा सकते हैं. इस छूट का फायदा उठाकर कई गिरोह गैरकानूनी कामों को आसानी से अंजाम देते हैं. सीमा पर हथियारों से लेकर नशीले पदार्थों और मानव तस्करी भी की जाती है. भूकंप के बाद खुफिया विभाग को मानव तस्करी की खबर मिली है. भूकंप से नेपाल के लाखों लोग वहां बेघर हो गए हैं. इन लोगों की मजबूरी का फायदा मानव तस्कर उठा रहे हैं. भारत के दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, लखनऊ और पटना जैसे कई बड़े शहरों में घरेलू काम के लिए नेपाली महिलाओं और बच्चों की भारी मांग रहती है. कई प्लेसमेंट एजेंसियां भी इस गैरकानूनी काम में लगी हैं. उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों ने सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को आपस में तालमेल स्थापित कर इस दिशा में चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं. उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा ने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए नेपाल सीमा से लगे जनपदों में नेपाल से आने वाले लोगों पर कड़ी निगाह रखने का फरमान जारी किया है. नेपाल सीमा से लगे इलाकों में मानव तस्करी कोई नई बात नहीं है. मासूम बच्चियों से लेकर बड़ी लड़कियों को देह व्यापार के दलदल में झोंकने का गोरखधंधा अर्से से जारी है. बड़ी उम्र की महिलाओं को भी तस्करी के जरिए देह व्यापार के हवाले किया जा रहा है. महिला आयोग तक केंद्र सरकार से यह कह चुका है कि नेपाल, बांग्लादेश सीमा पर महिलाओं और लड़कियों की तस्करी बहुत होती है, इसके लिए कड़ी निगरानी और सख्त कानून की जरूरत है. महिला आयोग की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि इन महिलाओं और लड़कियों की गरीबी का फायदा उठाकर इन्हें काम देने के नाम पर 20-25 हजार रुपये में इनका सौदा कर दिया जाता है. कोलकाता भी पूर्वी भारत में महिलाओं की तस्करी और खरीद-फरोख्त का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है. राज्य के ग्रामीण इलाकों और बांग्लादेश व नेपाल से बड़े पैमाने पर महिलाओं की तस्करी हो रही है.

महिलाओं की बढ़ती तस्करी में पड़ोसी देशों की अहम भूमिका है. नेपाल के अलावा पश्चिम बंगाल की लगभग एक हजार किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है. इसके जरिए बांग्लादेश की गरीब महिलाओं को कोलकाता स्थित दक्षिण एशिया की देह व्यापार की सबसे बड़ी मंडी सोनागाछी लाया जाता है और यहां से उनको मुंबई, दिल्ली व पुणे जैसे शहरों के दलालों के हाथों बेच दिया जाता है. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक अधिकारी कहते हैं कि सीमा पार से आने वाली महिलाओं को देख कर यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन घुसपैठिया है और किसको तस्करी के जरिए यहां लाया जा रहा है. इसी तरह नेपाल से सिलीगुड़ी कॉरीडोर से युवतियों को बेहतर नौकरियों का लालच देकर यहां लाया जाता है. अभी कुछ ही अर्सा पहले उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे जिले महराजगंज लड़कियों की तस्करी के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था और 11 नेपाली लड़कियां मुक्त कराई गई थीं. भारत-नेपाल सीमा पर स्थित ठूठीबाड़ी के रास्ते से 11 नेपाली लड़कियों को भारतीय सीमा में लाया जा रहा था. इसकी सूचना मिलने पर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों ने मौके पर पहुंचकर उन लड़कियों को मुक्त कराया और नेपाल के पोखरा के रहने वाले प्रकाश नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. पकड़े गए अपराधी ने कुबूल किया है कि उसका गिरोह अब तक 20 लड़कियों को खाड़ी देशों में भेज चुका है और 18 अन्य लड़कियों को भी भेजने की तैयारी थी. 11 नेपाली लड़कियों को वह दिल्ली में अपने एक साथी के हवाले करने जा रहा था. इसके एवज में उसे प्रति लड़की पांच हजार रुपये मिलने थे. मुक्त कराई गई लड़कियों को वापस नेपाल भेज दिया गया था. संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव तस्करी शाखा में काम कर चुके एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहते हैं कि नशीली दवाओं और हथियारों के कारोबार के बाद मानव तस्करी विश्वभर में तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है. संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को डराकर, बलप्रयोग कर या दोषपूर्ण तरीके से भर्ती, परिवहन या शरण में रखने की गतिविधि तस्करी की श्रेणी में आती है. दुनिया भर में 80 प्रतिशत से ज्यादा मानव तस्करी यौन शोषण के लिए की जाती है और बाकी बंधुआ मजदूरी के लिए. भारत को एशिया में मानव तस्करी का गढ़ माना जाता है. सरकार के आंकड़े ही बताते हैं कि देश से हर साल औसतन 50 हजार बच्चे गायब होते हैं. लेकिन आज तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया जिससे भारत में तस्कर हुए बच्चों का सही आंकड़ा पता चल सके. आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटी उम्र की लड़कियों को नेपाल से तस्करी कर भारत लाया जाता है. मानव तस्करी के मामले में कर्नाटक भारत में तीसरे नंबर पर आता है. अन्य दक्षिण भारतीय राज्य भी मानव तस्करी के सक्रिय स्थान हैं. चार दक्षिण भारतीय राज्यों में से प्रत्येक में हर साल ऐसे तीन सौ से पांच सौ मामले रिपोर्ट होते हैं. दिल्ली भारत में मानव तस्करी का गढ़ है और दुनिया के आधे गुलाम भारत में रहते हैं. दिल्ली घरेलू कामकाज, जबरन शादी और वेश्यावृत्ति के लिए छोटी लड़कियों के अवैध व्यापार का केंद्र है.

नेपाल और उत्तर पूर्वी राज्यों या झारखंड से लाए गए बच्चों, छोटी लड़कियों और युवतियों को दूरदराज के राज्यों में यौन शोषण और बंधुआ मजदूरी के लिए बेचा जाता है. एजेंट उनके माता पिता को पढ़ाई, बेहतर जिंदगी और पैसों का लालच देकर लाते हैं लेकिन उन्हें स्कूल भेजने के बजाय ईंट के भट्टों पर, कारपेंटर, घरेलू नौकर या छोटे कारखानों में काम करने के लिए बेच देते हैं. लड़कियों को यौन शोषण के लिए बेच दिया जाता है. नेपाली लड़कियों को उन क्षेत्रों में शादी के लिए भी मजबूर किया जाता है जहां लड़कियों का लिंग अनुपात लड़कों के मुकाबले बहुत कम है. ■

भारत मानव तस्करी का बड़ा बाजार

संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट कहती है कि देश की राजधानी दिल्ली मानव तस्करों की पसंदीदा जगह बनती जा रही है. यह आधिकारिक तथ्य है कि देशभर में करीब एक हजार लिस्टेड गैंग मानव तस्करी के धंधे में सक्रिय हैं. यह तथ्य सीबीआई का है. जबकि गृह मंत्रालय की विभिन्न इकायों के माध्यम से मुश्किल से 225 मानव तस्कर विरोधी इकाइयां ही सक्रिय हैं. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ही कहती है कि 50 हजार से अधिक बच्चे हर साल लापता हो जाते हैं. लेकिन उनमें से मुश्किल से 10 हजार बच्चों का ही पता चल पाता है. मानव तस्करी को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत मानव तस्करी का बड़ा बाजार बन चुका है और देश की राजधानी दिल्ली मानव तस्करों की पसंदीदा जगह बनती जा रही है, जहां देशभर से और नेपाल-बांग्लादेश से बच्चों और महिलाओं को लाकर बेचा जाता है और विदेशों में भी भेजा जाता है. भारत ने मानव तस्करी रोकने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय संधियों को मंजूरी दे रखी है. इनमें संयुक्त राष्ट्र ट्रांसनेशनल संगठित अपराध संधि और महिलाओं और बच्चों की तस्करी से जुड़ी दक्षेस संधि जैसे समझौते शामिल हैं. इसके अलावा बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय समझौता भी है. इसके बावजूद बांग्लादेश और नेपाल से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मानव तस्करी जोरों से हो रही है. बांग्लादेश और नेपाल से मानव तस्करी में संगठित गिरोह शामिल हैं, लेकिन उनके खिलाफ यदा-कदा ही कार्रवाई हो पाती है. कई गैर सरकारी संगठनों की रिपोर्ट कहती है कि नेपाल और भारत में सबसे अधिक मानव व्यापार (सीमा पार और देश में) वेश्यावृत्ति के धंधे के लिए हो रहा है और इनमें 60 प्रतिशत 14 से 16 साल की किशोर लड़कियां हैं. उत्तर प्रदेश के दर्जनभर से अधिक संवेदनशील जिलों में महिला एवं बाल विभाग द्वारा किए गए अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है. उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में इटैलिया मुहल्ला ही है जहां नेपाल, बांग्लादेश, कोलकाता, मुम्बई जैसी जगहों की महिलाएं वेश्यावृत्ति के धंधे में लगी हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करता. नेपाल के करीब होने के कारण यहां नेपाली महिलाओं की संख्या अधिक है. स्वाभाविक है कि इनमें से अधिकतर महिलाएं तस्करी से ही यहां लाई गई हैं. यह इलाका धीरे-धीरे महिलाओं की खरीद फरोख्त का अड्डा बनता जा रहा है. लेकिन शासन-प्रशासन को कोई फिक्र नहीं. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया बिहार झारखंड

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

18 मई–24 मई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001-2008 & 14001 COMPANY

www.vastuvihar.org
Cutomer Care : 080 10 222222
• 1 Builder • 9 States • 58 Cities • 107 Projects
• स्विमिंग पूल
• शॉपिंग सेन्टर
• 24x7 बिजली, पानी एवं सुरक्षा
9 लाख में 2 BHK FLAT

5 STAR BUNGALOW
सिलीगुड़ी, रांची, बोकारो, धनबाद, पटना
भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया एवं दरभंगा में तैयार
Five Star Bungalow यानि...
6 डिग्री कड़ाके की ठंड हो या 42 डिग्री की गर्मी,
घर की भीतरी तापमान मात्र 21 डिग्री से 27 डिग्री
नोट :– वास्तु विहार में पहले से लिए गये घर को Five Star में बदलने के लिए कार्यालय से सम्पर्क करें।

केंद्र सरकार से नाराज़ नीतीश

केन्द्र सरकार के इस रुख से नीतीश कुमार और उनके जदयू व सरकार के सहयोगी दलों का क्षुब्ध होना लाजिमी है. भूकंप से तबाह नेपाल में बचाव व राहत कार्य को युद्ध-स्तर पर चलाने में नीतीश ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी. जिस दिन भूकंप आया उस दिन जनता परिवार के विलय को लेकर महत्वपूर्ण बैठक तो थी ही, दिल्ली में ही अन्य कई व्यस्तताएं भी थीं. लेकिन सभी को छोड़ बिहार के मुख्यमंत्री पटना लौट आए. सूबे के भूकंप पीड़ित क्षेत्र ही नहीं, नेपाल में भी मदद पहुंचाने की तुरन्त व्यवस्था की. बचाव व राहत कार्य की देखरेख की कमान खुद संभाल ली. नेपाल के भूकंप पीड़ितों को सूखी खाद्य-वस्तु व तात्कालिक उपयोग के जरूरी सामान के राहत पैकेट भिजवाने की पूरी व्यवस्था पटना में की.

सुकान्त

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेपाल जाना अंततः नहीं हो सका, भारत सरकार ने फिलहाल वहां जाने से उन्हें रोक दिया. इससे वे आहत हैं, उनके जनता दल यूनाइटेड में रोष है. मुख्यमंत्री नेपाल के जनकपुर जाकर वहां के भूकंप पीड़ितों के आंसू पोंछना चाहते थे. चूंकि वह आम भारतीय नहीं हैं लिहाजा उनकी नेपाल यात्रा के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की अनुमति जरूरी थी. पहले यह अनुमति तो मिल गई लेकिन बाद में जाने के ठीक एक दिन पहले केन्द्र सरकार ने उन्हें अपनी यात्रा स्थगित करने को कह दिया. केन्द्र सरकार का कहना था कि भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल व विदेश सचिव जयशंकर की नेपाल से वापसी के बाद उनकी सलाह पर ही नीतीश कुमार को यात्रा स्थगित करने का मशविरा दिया गया. इस मसले पर जदयू के रोष का इज़हार तो संसद में हो गया. राज्य सभा में जदयू के नेता शरद यादव ने भारत सरकार से जानना चाहा कि पहले अनुमति देना और बाद में इसे वापस लेना सहज नहीं है. किन हालात में ऐसा किया गया, यह सरकार को बताना चाहिए. नीतीश कुमार को नेपाल जाने से रोकने के सवाल पर बिहार के सत्तारूढ़ जदयू ही नहीं, उसके सहयोगी दलों ने भी केन्द्र के रवैये पर क्षोभ जताया है. राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का आरोप है कि केन्द्र की राजग सरकार के बिहारी मंत्रियों के दबाव में ऐसा निर्णय लिया गया है. नीतीश कुमार इस यात्रा के लिए मानसिक तौर पर किस हद तक तैयार थे, यह उनकी टिप्पणी से ही साफ हो जाता है. नीतीश ने केन्द्र सरकार के निर्णय पर कहा–लगता है नेपाल यात्रा मेरी किस्मत में नहीं लिखी है. एक बार पहले भी नेपाल जाने की कोशिश की थी, पर उस वक्त भी अनुमति नहीं मिली. यहां यह बताना गैर वाजिब नहीं होगा कि 2008 में कोसी की कुसहा त्रासदी के समय भी वह नेपाल जाना चाहते थे. उस समय भी विदेश मंत्रालय ने अनुमति नहीं दी थी.

केन्द्र सरकार के इस रुख से नीतीश कुमार और उनके जदयू व सरकार के सहयोगी दलों का क्षुब्ध होना लाजिमी है. भूकंप से तबाह नेपाल में बचाव व राहत कार्य को युद्ध–स्तर पर चलाने में नीतीश ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी. जिस दिन भूकंप आया उस दिन जनता परिवार के विलय को लेकर महत्वपूर्ण बैठक तो थी ही, दिल्ली में ही अन्य कई व्यस्तताएं भी थीं. लेकिन सभी को छोड़ बिहार के मुख्यमंत्री पटना लौट आए. सूबे के भूकंप पीड़ित क्षेत्र ही नहीं, नेपाल में भी मदद पहुंचाने की तुरन्त व्यवस्था की. बचाव व राहत कार्य की देखरेख की कमान खुद संभाल ली. नेपाल के भूकंप पीड़ितों को सूखी खाद्य–वस्तु व तात्कालिक उपयोग के जरूरी सामान के राहत पैकेट भिजवाने की पूरी व्यवस्था पटना में की. यहां से वायु सेना के विमानों से राहत पैकेट कई दिनों तक भेजे गए. सीमावर्ती कस्बों रक्सौल (पूर्वी चंपारण), बैरगनिया (सीतामढ़ी), जयनगर (मधुबनी) व जोगबनी (अररिया) में बड़े राहत शिविर शुरू किए गए. फिर, कोई एक दर्जन स्थानों पर छोटे–छोटे कैंप आरंभ किए गए. सीमावर्ती क्षेत्रों से राहत पैकेट, दवा, पानी, तिरपाल या अन्य जरूरी सामान ट्रकों के जरिए नेपाल के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाने लगा. नेपाल में फंसे बिहारियों और भारतीयों को इन राहत शिविरों तक लाने के लिए बिहार सरकार के पर्यटन निगम और पथ परिवहन निगम की दर्जनों बसों को नेपाल में विभिन्न स्थानों पर भेजा गया. इन राहत शिविरों तक आने वाले पीड़ितों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई. मुख्यमंत्री ने खुद रक्सौल और बैरगनिया के राहत शिविरों को देखा और वहां के काम–काज पर संतोष जताया. उन्होंने नेपाल में भूकंप के दौरान मृत बिहारियों के परिजनों को भी चार–चार लाख रुपये की अनुग्रह–राशि देने की घोषणा की, भुगतान भी शुरू करवा दिया. इस यात्रा के दौरान उन्होंने अनुभव किया कि भारत की सीमा से जुड़े नेपाल के हिस्से (मधेश) की आबादी का हाल जानना भी जरूरी है. वस्तुतः सीमा के दोनों तरफ (इस पार भारत और उस पार नेपाल) की आबादी की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन–शैली एक है और इनमें बेटी–रोटी का संबंध है और यह बहुत गहरा है. लिहाजा दोनों तरफ की आबादी के सुख–दुख का असर दोनों तरफ के क्षेत्रीय सामाजिक–राजनीतिक आचरण पर भी पड़ता है. ऐसे में किसी राजनेता के दिल में इनके आंसू पोंछने की आकांक्षा का जगना सहज है. नीतीश कुमार के मन भी यह आकांक्षा जगी, भारत सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया. पर फिर वह मुकर गई. ऐसा क्यों? यह लाख टके का सवाल है और इसका उत्तर केन्द्र के औपचारिक या अनौपचारिक नुमाइंदे ही दे सकते हैं. प्राकृतिक आपदाओं से तबाह लोगों को राहत दिलाने में नीतीश कुमार बिहार के सभी राजनेताओं में आगे दिखते रहे हैं. पहले बेमौसम की वर्षा, फिर काल–बैसाखी की आंधी और ओला–वृष्टि और फिर भूकंप– इन सभी मौकों पर सूबे के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता काबिल–ए–तारीफ रही है. उनकी प्रशंसा देश के गृहमंत्री ने लोकसभा में की और उन्हें धन्यवाद दिया. बिहार में यह पहला मौका है कि इन प्राकृतिक आपदाओं में मृत लोगों के परिजनों को चौबीस से अड़तालिस घंटे के भीतर चार–चार लाख रुपये की अनुग्रह–राशि के चेकों का भुगतान कर दिया गया. बेमौसम की वर्षा, काल बैसाखी व भूकंप से क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, किसानों की फसल क्षति का आंकलन किया जा रहा है.

इन कार्यों में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, कई कृषि अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है. वस्तुतः इन हफ्तों में नीतीश कुमार की पुरानी छवि का नवीनीकरण हुआ है और उनसे लोगों की उम्मीदें नए सिरे से फिर काफी बढ़ गई हैं. यह वास्तविकता है कि गत एक साल के राजनीतिक घटनाचक्र से नीतीश कुमार की छवि में कोई निखार तो नहीं ही आया, बल्कि उनके राजनीतिक और प्रशासनिक आभा–मंडल पर इनका नकारात्मक असर ही दिखने लगा था. लेकिन एक बार फिर उनकी छवि निखरी है, आभा मंडल का रंग गहरा हुआ है. बिहार में विधानसभा चुनावों की हवा तेज होती जा रही है और राजनीतिक माहौल सरगर्म होने लगा है. कहते हैं, अंत भला तो सब भला. सो, संभव है चुनाव से पहले की यह छवि सत्ता राजनीति में इर्ष्या का कारण बने. बिहार का बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां नेपाल के मधेश की हवा का गहरा असर पड़ता है, ऐसा ही मधेश में बिहार के इस क्षेत्र का असर होता है. तो क्या नीतीश कुमार को जनकपुर की. यात्रा स्थगित करने की केन्द्र की सलाह के पीछे राजनीति है? यह यक्ष प्रश्न है और इसका सीधा उत्तर सहज नहीं है.

प्राकृतिक आपदा की घड़ी में बिहार सरकार दिखी, केन्द्र सरकार भी दिखी, पर दल के तौर कोई राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल–कुछ अपवादों को छोड़ दें– कहीं नहीं दिखा है. भारतीय समाज का हाल तक का अनुभव रहा है कि प्राकृतिक संकट के समय स्वयंसेवी संगठन या राजनीतिक दल दिखते रहे हैं. पर हाल के कुछ वर्षों से यह अनुभव बिहार में धार्मिक कर्मकांडी अनुष्ठानों के दौर में तो दिखते हैं, संकट के दौर में नहीं. यह प्रकृतिक आपदा की बात ही नहीं, अन्य अवसरों पर भी ऐसा ही देखा गया है. पटना में गत वर्षों में छठ और दशहरा के अवसरों पर हृदय–विदारक हादसे हुए, लेकिन राजनीति दलों और स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका लोगों को याद करनी पड़ती है. एक दल के तौर इस बार भी किसी दल की भूमिका को याद करने के लिए तो मन पर बड़ा जोर डालना पड़ता है. हालांकि भूकंप राहत के नाम पर कुछ संगठनों के काम याद आ रहे हैं. ऐसे में जब एक राजनेता की छवि निखर रही हो, तो प्रतिस्पर्द्धी राजनीतिक समूह विशिष्ट रणनीति के तहत काउंटर करने का कुछ रास्ता तो खोज ही सकता है. कहते भी हैं, राजनीति और वह भी चुनावी राजनीति में सब कुछ जायज है.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

क्षतिग्रस्त पुलिया बनी परेशानी का सबब

गोगरी प्रखंड के सर्किल न. 1 के दर्जनों गांव आज भी विकास की रोशनी से कोसों दूर हैं. इस पर पिपड़पांती की क्षतिग्रस्त पुलिया कोढ़ में खाज साबित हो रही है. उक्त क्षेत्र में विकास के लिए पसराहा एन एच 31 से भिमरी तक कड़ोरां की लागत से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना द्वारा सड़क का निर्माण कराया जा रहा है. सड़क निर्माण के लए 23 मार्च का समय निर्धारित है. कार्य की धीमी प्रगति को देख ऐसा नहीं लगता कि उक्त सड़क तय समय सीमा के भीतर बन पाएगी. जगह–जगह गिट्टी को बिछा कर छोड़ दिया गया है जिससे आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पर रहा है. वैसे तो पसराहा से भिमरी तक बनने वाले सड़क में मिट्टी व छोटे पुलिया का निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है पर पिपड़पांती के पास धार में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर पुल के निर्माण का कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है. इसलिए उक्त मार्ग को मुख्य मार्ग से जोड़ा नहीं जा सका है. सर्किल न. 1 के खड़ौआ के सदन सिंह, कुमोद सिंह, गजेन्द्र सिंह ने कहा कि जिला को अधिक अन्न देने वाला उक्त क्षेत्र महज एक सड़क के बिना उपेक्षित है. वहीं देवठा के पूर्व मुखिया क्षत्रि शर्मा,मो. खलील ने जिला अधिकारी से मांग किया कि उक्त पुल का जल्द निर्माण करते हुए सड़क का निर्माण तय समय सीमा में पूरा किया जाय.

गम में डूबा सिराजपुर

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के तेमथा करारी पंचायत के सिराजपुर निवासी देवदत्त चौधरी के पुत्र संतोष कुमार की सड़क दुर्घना में हुई आकस्मिक मौत से पूरे गांव गम में डूबा हुआ है. गुरुवार दोपहर मृतक का शव गांव पहुंचने पर मृतक के परिजनों के चितकार से पूरा परबत्ता रो पड़ा. बेगूसराय जिला के मंझोल गांव से तिलक चढ़ाकर लौटने के क्रम में पसराहा ढाला पर ट्रक और मारुति टकराई जिससे संतोष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद पूरा गांव मृतक के दरवाजे पर पहुंच कर समझाने एवं सांत्वना देने का प्रयास कर रहे थे. लोगों के बीच इसी बात की चर्चा हो रही थी कि संतोष काफी मिलनसार वे किसी के श्राद्ध या किसी की शादी में बढचढ़कर भाग लेते थे.एक साल का पुत्र भी है. जो सिर्फ किलकारी मार रहा है. लेकिन उसे यह मालूम नहीं कि उस पर पिता का साया था वो अब इस दुनिया में नही रहा.

भूकंप से मकानों में दरार

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र में अचानक आये भूकंप के झटके से लोगों के बीच अफरा–तफरी मच गई. वहीं दर्जनों पुराने मकानों में आंशिक दरार पड़ गई. अनुमंडल क्षेत्र के तिहाय गांव के निर्मल राय, दयानंद भगत, अभय भगत के मकानों में बहुत बड़ी दरार पड़ गई. हालांकि कही से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है. भूकंप के झटके जैसे ही शुरू हुए और लोगों को धरती डोलने का एहसास हुआ तो चारों तरफ से भागो–भागो की आवाज होने लगी और लोग अपने अपने छोट–छोटे बच्चों को घर से लेकर बाहर निकल गये. इधर गो–गरी थाना अध्यक्ष उमाशंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि भूकंप के झटके समाप्त होने के तुरंत बाद ही अपने पुलिस पदाधिकारी को गश्ती तेज करने का आदेश दिया. इसके बाद गश्ती दल को यह निर्देश दिया कि आम लोगों के हाल चाल की जानकारी तुरंत लेकर सूचित करें. जमालपुर के गुलाम गोश टोला में मो0 इजराईल की मिट्टी की दिवार गिर जाने की सूचना मिली लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. अनुमंडल के कार्यपालक पदाधिकारी मनोरमा देवी ने अनुमंडल के सभी प्रखंडों की मोबाईल से खबर ली. वहीं स्थित परबत्ता के भरतखंड स्थित इलाहाबाद बैंक में भी दरार आने की सूचना है.■

– गीता

बदलते मौसम के मिजाज को अनदेखा न करें
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
डॉ. पंकज कुमार
फिजिसियन, गोगरी जमालपुर, खगड़िया

बढ़ती गर्मी में सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही आपको मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए, बेहतर होगा कि यदि आप घर से निकलें तो पूरे इंतजाम के साथ निकले ।

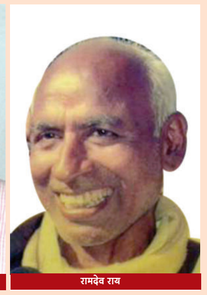

चिकित्सकों का कहना है कि गर्मी में सावधानी न बरतने पर हीट स्ट्रोक, डायरिया, दस्त, उल्टी, अस्थमा का अटैक जैसी भयंकर बीमारियों की शिकायत तेजी से बढ़ती हैं। ये बातें बतायीं डॉ पंकज (जेनरल फिजीशियन) ने इन्होनें कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा धूप में निकलते समय संभलकर निकलें ।और जब भी घर से भीषण गर्मी में निकलें तो खाली पेट न निकलें और पानी ज्यादा पीकर ही निकलें। तेज धूप में घर से बाहर न निकलें। यदि घर से बाहर निकलें तो शरीर को पूरा ढक लें। घर से निकलने से पहले सनस्क्रीन व सनग्लास का उपयोग करें। जितना ज्यादा हो सके, ठंडा और साफ पानी पीएं। खुले में रखी खाद्य सामग्री नहीं खाएं। मौसमी फल तथा शरीर को ठंडक पहुंचाने वाली चीजें खाएं। यदि कोई समस्या हो तो तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें। डॉ पंकज ने कहा गर्मी में इन बीमारियों का खतरा अधिक हो जाता जैसे उल्टी, दस्त, बुखार आना। शरीर में पानी की कमी, मुंह में छाले पड़ना । ऐसे समय में आप इन बातों का ख्याल हमेशा रखे । हल्का भोजन करें। तरल चीजें जैसे दही, मट्ठा का सेवन अधिक करें। बासी खाने से परहेज करें। बाजार के खुले में रखे कटे फल न खाएं। चाट व फास्ट फूड का सेवन न करें। ज्यादा मसाला व तेल के खाने से परहेज करें। बच्चों के सर्दी, जुखाम या डायरिया जैसे लक्षण को नजर अंदाज न करे क्योंकि यह बाद में घातक सिद्ध हो सकती है बच्चों को ओ.आर.एस. का घोल और तरल पदार्थ रेगुलर देते रहना चाहिए।■

- चित्रा भारती

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.
AREX Cough Syrup.
Dextromethorphan 5 mg +Guaiphenesine 50 mg +Ammonium Chloride 60 mg + CPM 2.5 mg
Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
ARIPIME -T Inj.
Cefixime 250 mg + tazobactum 31.25 mg
Meme Drops
Multi Vitamins, Zinc & L- Lysine
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

बेगूसराय

बछवाड़ा में दर-दर भटक रहे प्रत्याशी

सुरेश चौहान/रघुवीर झा

अवधेश राय

कुंदन कुमार

रामदेव राय

आगामी विधानसभा चुनाव में बछवाड़ा विधानसभा सीट पर भाकपा, भाजपा एवं कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष के आसार हैं. बिहार विधानसभा का चुनाव लगभग छह: माह बाद होगा. चुनाव में किस राजनीतिक दल का किस दल के साथ विलय या चुनाव पूर्व गठबंधन होगा, यह तय होना बाकी है. लेकिन इसकी परवाह किए बिना लगभग सभी दल के संभावित प्रत्याशी चुनाव अभियान प्रारंभ कर मतदाताओं का रूख जानने में जुट गए हैं. बेगूसराय जिले के बछवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गयी है. वर्त्तमान में बछवाड़ा विधान सभा सीट भाकपा के पास है. अवधेश राय यहां के विधायक हैं. बिहार विधानसभा में अवधेश राय ही भाकपा के एकमात्र विधायक हैं. गत विधान सभा चुनाव में यह सीट राजग ने भाजपा को दिया था. भाजपा के एक कद्दावर नेता की हठधर्मिता एवं दबाव के कारण पार्टी यह सीट गवां बैठी. पार्टी टिकट से वंचित स्थानीय भाजपा नेता अरविन्द कुमार सिंह वागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में इतरकर पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी वन्दना को धूल चटा दिया. भाजपा की इस अन्तर्कलह का पूरा लाभ भाकपा को मिला और इसके पत्याशी अवधेश राय विजयी हुए.

आगामी विधानसभा चुनाव में भाकपा के अवधेश राय, कांग्रेस के रामदेव राय एवं भाजपा के कुन्दन कुमार में त्रिकोणात्मक संघर्ष होने की प्रबल संभावना दिख रही है. अवधेश राय भाकपा के सिटिंग विधायक है. अगामी चुनाव में पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने की इनकी दा–वेदारी मजबूत मानी जा रही है. कैडर आधारित भाकपा की स्थिति यहां काफी अच्छी है. पार्टी नेताओं ने पंचायत से प्रखंड स्तर तक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर अपनी स्थिति काफी मजबूत बना ली है. पार्टी को भरोसा है कि विधायक द्वारा किए गए विकास कार्य एवं मजबूत जनाधार के बल पर दल का प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा.

आगामी विधानसभा चुनाव में भाकपा के अवधेश राय, कांग्रेस के रामदेव राय एवं भाजपा के कुन्दन कुमार में त्रिकोणात्मक संघर्ष होने की प्रबल संभावना दिख रही है. अवधेश राय भाकपा के सिटिंग विधायक है. अगामी चुनाव में पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने की इनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है. कैडर आधारित भाकपा की स्थिति यहां काफी अच्छी है.

बछवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में भाजपा की स्थिति भी काफी अच्छी है. गत विधानसभा चुनाव में यदि अरविन्द कुमार सिंह के वागी प्रत्याशी बनने के कारण भाजपा का मत विभाजन नहीं होता तो चुनाव परिणाम कुछ और हो सकता था गत विधानसभा चुनाव में बछवाड़ा सीट के लिए कुन्दन कुमार एवं अरविन्द कुमार सिंह प्रमुख दावेदार थे. पार्टी द्वारा कुन्दन कुमार को प्रत्याशी घोषित किया गया. लेकिन नोमिनेशन दाखिल करने के पहले रात में ही एक तीसरे प्रत्याशी वन्दना को चुनाव चिन्ह प्रदानकर नोमिनेशन करने को कहा गया. पार्टी नेतृत्व के इस अप्रत्याशित निर्णय से कार्यकर्ता भौचक रह गए. पार्टी के इस निर्णय से क्षुब्ध अरविन्द कुमार सिंह ने भाजपा से वगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया. चुनाव में पार्टी की घोषित प्रत्याशी वन्दना से अरविन्द कुमार सिंह का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा लेकिन जीत नहीं पाए. भाजपा ने अरविन्द कुमार सिंह को पार्टी से निलम्बित कर दिया. आगे चलकर इसे पुन: पार्टी में वापस ले लिया गया. कुन्दन कुमार बिना किसी भेदभाव के पार्टी की नीति एवं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहे. कयास लगाया जा रहा है कि अगामी विधानसभा चुनाव में कुन्दन कुमार को भाजपा प्रत्याशी बनाया जा सकता है.

बछवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी भी काफी मजबूत स्थिति में है. इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस एवं भाकपा का ही दबदवा रहा है. प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद रामदेव राय पार्टी के कद्दावर नेताओं में स्थान रखते है. इनकी पहुंच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक है. लेकिन पार्टी में अन्तर्कलह कूट–कूट कर भरा है जिसे प्रदेश अध्यक्ष पाटने की बजाय गुटबाजी की हवा देते दीख रहे हैं. प्रद–शाध्यक्ष द्वारा बिहार के सभी जिला कमेटी को भंग किए जाने के विरोध में रामदेव ने प्रदेश उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया. एक अनजान कांग्रेसी को जिलाध्यक्ष मनोनीत करने से जिले के कांग्रेसियों में काफी उबाल है. फिर भी अगामी विधानसभा चुनाव में बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से रामदेव राय को प्रत्याशी बनाया जा सकता है.

यदि जदयू एवं राजद का विलय हो जाता है और कांग्रेस का इसके साथ चुनावी गठबंधन हो जाता है तो भी कांग्रेस इस सीट पर अपना दावा पेश करेगी और रामदेव राय गठबंधन के प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं. भाकपा का यदि किसी दल के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन होता है तो वह भी बछवाड़ा सीट का दावा किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहेगी. भाजपा, लोजपा एवं रालोसपा गठबंन की ओर से लोजापा भी इस सीट पर अपना दावा पेश कर सकती हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

देवघर नगर निगम चुनाव 2015

मेयर पद के लिए कांटे की टक्कर

रणजीत झा

रीता चौरसिया

रीता नरौने

सावित्री देवी

देवघर नगर निगम चुनाव के अंतिम क्षणों में मेयर पद के लिए चुनाव में उतरीं महिलाओं के बीच कांटे की टक्कर दीख रही है. आखिर टक्कर हो भी क्यों न. शहर के दिग्गजों के महिला परिजन चुनाव मैदान में उतर कर मुकाबला रोचक जो बना दिया है. रीता चौरसिया, रीता नरौने, रीता खवाड़े एवं सावित्री देवी के बीच मुख्य मुकाबला है. नगर निगम चुनाव राजनीतिक दलगत नहीं हो रहा है, लेकिन उम्मीदवार अवश्य ही राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हैं. वैसे प्रदेश भाजपा ने रीता चौरसिया को समर्थन करने की घोषणा कर दिया है. इसमें रोचक बात यह है कि रीता चौरसिया, रीता खवाड़े एवं सावित्री देवी तीनों ही भाजपा से संबंध रखती हैं अथवा उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है. भाजपा से संबंध रखने वाली तीन दमदार उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनों से ही मुकाबले में डटी हुई हैं. अब देखना है कि स्थानीय भाजपा के समर्थक मतदाता किसे अपना समर्थन देते हैं. मेयर राजनारायण खवाड़े, जिन्हें भाजपा सांसद निशिकांत दूबे का पूरा समर्थन है, अपनी पत्नी रीता खवाड़े के जीत के प्रति आश्वस्त हैं. रीता खवाड़े को शिक्षित महिला होने के साथ मेयर की पत्नी के रूप में निगम के कामकाज का अनुभव प्राप्त है. पिछले नगर निगम चुनाव में जिस प्रकार भारी मतों से मतदाताओं ने राजनारायण खवाड़े को विजयी बनाया था, उसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार भी रीता खवाड़े मजबूत स्थिति में हैं. वहीं रीता चौरसिया जिला भाजपा महिला कमिटि की जिलाध्यक्ष हैं तथा प्रदेश भाजपा में भी पहचान बना चुकी हैं. चुनावी समर में चौंकाने वाले परिणाम देने में सक्षम दीख रही हैं. रीता चौरसिया का जनसंपर्क अभियान में मतदाताओं का रुझान दीख रहा है. उपमहापौर संजयानंद झा की पत्नी सावित्री देवी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में जनसंपर्क अभियान जारी रखी हुई हैं. सूबे के श्रम एवं नियोजन मंत्री राज पलिवार का स्थानीय मतदाताओं में अच्छी पैठ है, जिसका लाभ उनकी बहन सावित्री देवी को मिल सकता है. कई सामाजिक संगठन की ओर से भी उन्हें समर्थन का आश्वासन मिल चुका है. मंत्री राज पलिवार का नगर निगम क्षेत्र के मतदाताओं में अच्छी छवि एवं पैठ भी है, जिसका लाभ उनकी बहन सावित्री देवी को मिल सकता है. रीता नरौने भी चुनावी मैदान में अपने समर्थकों की दमदार उपस्थिति दिखा कर मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं. समाजसेवी स्वर्गीय कमल कांत नरौने उर्फ बालोदा के शुभचिंतकों व भारी समर्थकों को देखते हुए मुकाबला कड़ा होता दीख रहा है. रीता नरौने के पुत्र एवं वार्ड पार्षद राकेश नरौने का युवाओं में अच्छा पैठ है, जिसका फायदा मतदान में मिल सकता है. सबकी नजर मेयर राजनारायण खवाड़े पर टिकी है, जिनके रणनीति पर ही बहुत कुछ निर्भर है. संभव है मतदान से पूर्व अंतिम समय में कुछ आश्चर्यजनक उलटफेर हो जाए. वैसे देवघर नगर निगम के चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाला पंडा समाज का अंतिम निर्णय भी चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगा. पंडा समाज किसे अपना आशीर्वाद देता है, वह चुनाव के दिन तक ही स्पष्ट हो पाएगा. शहर के दिग्गजों के परिजनों के बीच हो रहे मुकाबले सिर्फ रोचक ही नहीं, आने वाले समय में देवघर नगर निगम के क्रियाकलापों एवं दर्जनों चुनौतियां खड़ी हैं, जिसको पूरा करना अतिआवश्यक है. यह चुनाव देवघर नगर निगम की दिशा तय करेगा. झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कही जानी वाली बाबानगरी देवघर तीर्थनगरी के साथ पर्यटन केन्द्र भी है, जिसे संवारने एवं नगरवासियों को सुविधा देने की चुनौती नये मेयर की होगी, जिसके लिए शिक्षित, मजबूत आत्मबल, निर्णय लेने वाली मेयर की आवश्यकता है. आने वाला समय ही बताएगा कि मेयर का ताज किसके सिर होगा.■

रीता चौरसिया जिला भाजपा महिला कमिटि की जिलाध्यक्ष हैं तथा प्रदेश भाजपा में भी पहचान बना चुकी हैं. चुनावी समर में चौंकाने वाले परिणाम देने में सक्षम दीख रही हैं. रीता चौरसिया का जनसंपर्क अभियान में मतदाताओं का रुझान दीख रहा है. उपमहापौर संजयानंद झा की पत्नी सावित्री देवी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में जनसंपर्क अभियान जारी रखी हुई हैं. सूबे के श्रम एवं नियोजन मंत्री राज पलिवार का स्थानीय मतदाताओं में अच्छी पैठ है, जिसका लाभ उनकी बहन सावित्री देवी को मिल सकता है. कई सामाजिक संगठन की ओर से भी उन्हें समर्थन का आश्वासन मिल चुका है.

feedback@chauthiduniya.com

गया

गया जिला परिषद में करोड़ों की राशि

सुनील सौरभ

कभी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जिला परिषद की बड़ी महत्ता थी. ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद की ही अतिथिशाला वी आई पी के लिए ठहरने की अच्छी जगह मानी जाती थी . जिला परिषद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का बोलबाला हुआ करता था, क्योंकि विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र जिला परिषद पर ही निर्भर होते थें. लेकिन बदली परिस्थिति में उपर्युक्त सारी बातें इतिहास बन चुकी हैं. जिला पर्षद के तमाम डाकबंगले जर्जर हो चुके हैं. उसकी भूमि का अतिक्रमण हो रहा है और जिला परिषद के सदस्य सिर्फ अपनी गाड़ी पर जिला पार्षद का बोर्ड लगाकर खुशफहमी में हैं. जिला परिषद के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बातें अब बेमानी लगती हैं. इसके पदाधिकारियों तथा जिला पार्षदों के बीच तालमेल का अभाव विकास कार्यों को प्रभावित कर रहा है. यही कारण है कि गया जिला परिषद के खाते में तीन वित्तीय वर्ष का 36 करोड़ रुपया पड़ा है. लेकिन विकास कार्यों के लिए न तो जिला पार्षद और न ही पदाधिकारी दिलचस्पी ले रहे हैं. नतीजा यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो विकास कार्य इस राशि से होने थे, वे रुके पड़े हैं. सच यही है कि इस राशि को खर्च की जाती तो गया जिले के पंचायतों, प्रखंडों का कायाकल्प हो जाता.

इस संबध में गया जिला परिषद के उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद यादव बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में एक स्कीम के लिए 13वें वित्त आयोग से आई करीब 36 करोड़ रुपये पड़ी है. अगर इस योजना में राशि खर्च की जाती तो प्रत्येक जिला पार्षद को 18 लाख रुपये विकास कार्यों के लिए मिलते, लेकिन विभागीय पदाधिकारी और जिला अभियंता इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों मे होने वाले विकास कार्य नहीं हो पा रहें हैं. उपाध्यक्ष ने बताया कि जिला परिषद की बैठक में यह आदेश दिया गया था कि अपने–अपने प्रखंड मे प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा सीडीपीओ आंगनबाड़ी भवन का साइड चिन्हित करें. लेकिन बीडीओ–सीडीपीओ ने इस आदेश की अवेहलना की. इसी प्रकार जिला परिषद भवन के जीर्णोद्धार के नाम पर 24 लाख रुपये खर्च कर दिया गया है. फिर भी इस भवन की हालत जर्जर है.

उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद यादव ने बताया कि जिला परिषद कर्यालय और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के कक्ष के जीर्णोद्धार के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है. कार्यालय में काम करने में काफी परेशानी होती है. जिला अभियंता चाहे कोई सफाई दें, सच्चाई यही है कि वे कर्यालय में नहीं रहते हैं. वर्तमान बिहार सरकार का दावा है कि विकास कार्यों के लिए जिले को मिली राशि का अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है, लेकिन वास्तविकता है कि अफसरों की लालफिताशाही के कारण जिले में अनेक विकास योजनाएं ठप पड़ी हैं. इसका सबसे बड़ा प्रमाण गया जिला परिषद में तीन वित्तीय वर्ष के करीब 36 करोड़ रुपये की राशि है.■

डॉ. शीतल यादव

उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद यादव ने बताया कि जिला परिषद कर्यालय और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के कक्ष के जीर्णोद्धार के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है. कार्यालय में काम करने में काफी परेशानी होती है. जिला अभियंता चाहे कोई सफाई दें, सच्चाई यही है कि वे कर्यालय में नहीं रहते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

अन्य ख़बरें

हवन यज्ञ का आयोजन

नेपाल के काठमांडू समेत उत्तर बिहार में आए विनाशकारी भूकंप ने आम आवाम को हिला कर रख दिया है. तकरीबन एक पखवाड़े बाद भी लोग भूकंप की आहट से ही कांप रहे है. सीतामढ़ी जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में भूकंप में मारे गये लोगों की आत्मा शांति के लिए गांधी मैदान में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया. जिलाध्यक्ष विमल शुक्ला के नेतृत्व में उपाध्यक्ष सीताराम झा, सत्येंद्र कुमार तिवारी, नगर अध्यक्ष सीमा गुप्ता, विजेंद्र प्रसाद यादव, शिव शंकर शर्मा समेत अन्य ने आचार्य अवधेश शास्त्री के निर्देशन में यज्ञ में भागीदारी दी. – विकास

अल्पसंख्यकों ने मांगी दुआ

सीतामढ़ी जिला कांग्रेस कमिटी कार्यालय ललित आश्रम प्रांगण में पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें नेपाल के काठमांडू समेत बिहार के अलग–अलग हिस्सों में भूकंप के शिकार हुए लोगों की आत्मा शांति के लिए हवन यज्ञ के साथ ही दुआ मांगी गयी. कार्यक्रम में शिवहर जिलाध्यक्ष मो. असद के अलावा मो. परवेज आलम अंसारी, मो. शम्स शाहनवाज, अंजारुल हक तौहीद समेत दर्जनों अल्पसंख्यक पार्टी कार्यकर्ता व आम लोगों ने भागीदारी दी. सीतामढ़ी जिलाध्यक्ष विमल शुक्ला ने कहा कि प्राकृतिक आपदा पर किसी का नियंत्रण नहीं है. ऐसे वक्त में धैर्य व संयम के साथ पीड़ितों के सेवार्थ सभी को साथ बढ़ने की आवश्यकता है.

मदद को किया भिक्षाटन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सीतामढ़ी जिला शाखा के तत्वावधान में पिछले दिनों नगर में भिक्षाटन किया गया. संघ के डॉ. वसंत कुमार मिश्रा की अगुआई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नेपाल के काठमांडू में आये विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों के सेवार्थ धन इकट्ठा किया. कार्यक्रम में संघ कार्यकर्ताओं को आम लोगों का भरपूर सहयोग मिला.■ – ब्रजेश

एक नज़र

सड़क नसीब नहीं

गोगरी अनुमंडल के पसराहा थाना अन्तर्गत सर्किल न. एक के दर्जनों पंचायत के हजारों लोगों को पैदल चलने के लिए एक अदद सड़क तक मयस्सर नहीं है. यहां के लोग आज भी पगडंडियों के सहारे चलने को मजबूर हैं. सर्किल न. 1 को मुख्य मार्ग एन एच 31 से जोड़ने वाली एक मात्र सतिसनगर पहाड़पुर सड़क अपनी जर्जरता पर आंसू बहा रही है. क्षेत्रीय विकास व चुनाव का मुख्य मुद्दा रहने वाली उक्त सड़क जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार है. उक्त सड़क को बी एन बांध एवं एनएच 31 को जोड़ने वाली रिंग बांध पर बनाया गया है.वैसे तो सड़क निर्माण में गुणवत्तापूर्ण कार्यो को लेकर सवाल उठते रहे हैं. उक्त सड़क भी अपने निर्माण के चंद साल बाद ही दरकने लगी. विगत साल उक्त सड़क को बी एन बांध पर बसुआ तक बढ़ाया गया जिसमें ईंट सोलिंग का कार्य किया गया. जिससे पैकांत, वीरवास, बसुआ,पिपड़पांती, कोयला भीमरी जैसे अत्यंत पिछड़े गांव मुख्य मार्ग से जुड़ गया. लेकिन सड़क की जर्जरता दुर्घटना को आमंत्रण दे रही है. सबसे अधिक परेशानी स्कूली छात्राओं को उठानी पड़ती है. हल्की बारिश हो जाने पर वाहन को कौन कहे पैदल चलना मुश्किल हो जाता है. वहीं गोगरी प्रखंड के सर्किल न. 1 में कोशी के किनारे बालू माफिया द्वारा बालू का अवैध खनन बदस्तूर जारी है. वह बालू बड़ी –बड़ी लॉरियों में भरकर उक्त सड़क से ढोया जाता है.भारी वाहन के गुजरने से सड़क गड्ढे में बदल चुकी है. अब सवाल उठता है कि किसके आदेश से जर्जर बांध पर बनी उक्त सड़क से भारी वाहन को गुजारा जाता है.

– गीता कुमार

एलर्जी का समय पर कराएं इलाज

एलर्जी लाइलाज बीमारी है और इस बीमारी से बचने के लिए समय पर इलाज जरूरी है. उक्त बातें मोतिहारी शहर के छतौनी चौक पर स्थित एलर्जी एवं दम्मा क्लिनिक में एलर्जी एवं दम्मा रोग विशेषज्ञ डॉ विवेक कुमार ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि बार–बार सर्दी का होना, खांसी व सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज का आना, सांस लेने में तकलीफ होना व दम फूलना आदि इस बीमारी का लक्षण है. आम तौर पर छोटे–छोटे बच्चों व युवाओं में भी यह बीमारी होती है. तंबाकू सेवन करने वाले लोगों को दम्मा होने की खतरा रहती है. इसके लिए इन्होंने जागरूकता फैलाने पर जोर दिया और कहा कि विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पर स्लोगन जारी की गयी है '' यू कैन कंट्रॉल योर अस्थमा एवं इट्स टाइम टू कन्ट्रोल अस्थमा'' उन्होंने बताया कि अस्थमा के रोगियों को फेफड़े की कम्प्यूटर की जांच की जाएगी एवं बीमारी का पता लगाया जा सकेगा. पांच मई को क्लिनिक पर नि:शुल्क शिविर लगायी गया जहां बड़े पैमाने पर मरीजों का इलाज किया गया. मौके पर महबूब आलम, अभिषेक कुमार, अमरेन्द्र वर्मा, सुबोध कुमार, त्रिलोकी प्रसाद, राकेश कुमार व श्यामू कुमार आदि उपस्थित थे.

संकल्प ग्रहण समारोह सम्पन्न

भारत विकास परिषद शाखा शिवम एवं बापूधाम सुंदरम का नये सदस्यों का संकल्प ग्रहण समारोह एवं दायित्व धारियों का दायित्व ग्रहण समारोह मोतिहारी के एक निजी होटल में हुआ. उक्त कार्यक्रम में नई शाखा बापूधाम सुंदरम की भविष्य की योजनाओं की रूप रेखा अध्यक्ष व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ चन्द्र सुभाष, सचिव मृत्युन्जय कुमार एवं डॉ पंकज सिंह द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी. शाखा शिवम द्वारा गोद लिए अमवा गांव का प्रगति प्रतिवेदन नवोदय के पूर्व प्राचार्य जगत नारायण प्रसाद प्रस्तुत गया. डॉ मधुबाला सिन्हा को भारत विकास परिषद ने विकास मित्र के रूप में ग्यारह रूपये दान देने को लेकर उन्हें स्मृति चिन्ह दिया गया. मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने इस शाखा के द्वारा जागरूकता फैलाने की अपील सदस्यों से करते हुए कही कि इसमें भूकम्प पीड़ित से लेकर आम आवाम का मदद करना सबकी नैतिक जिम्मेवारी है. मौके पर रेड क्रॉस के सचिव ई. विभूति नारायण सिंह, अन्नपूर्णा पिज्जा के रामेश्वर प्रसाद सहित अनेक लोगों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया. मौके पर ई. जीपी सिंह, ईपीके अम्बष्ट, अमरनाथ प्रसाद, रामेश्वर सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित थे.

भूकम्प पीड़ितों से मुलाकात

भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिए गंभीर है और हर संभव प्रयास कर रही है. उक्त बातें लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने मोतिहारी सदर अस्पताल में भूकम्प से घायल मरीजों से मिलने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नही की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस विनाशकारी भूकम्प में ज्यादातर गरीब तबके के लोग मरे व घायल हुए है जो गांव में रहते है. क्योंकि गांव ज्यादातर मकान मिट्टी की दीवारों से बने जो ऐसे विनाशकारी आपदा को बर्दाश्त नहीं कर सकता. केन्द्रीय मंत्री श्री पासवान ने भूकम्प में घायल मरीजों का बेहतर इलाज करने का निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिया. मंत्री श्री पासवान सदर अस्पताल में इलाजरत भूकम्प में घायल मधुबन थाना के पकड़िया निवासी जयनारायण पासवान, ढाका तेलहारा निवासी सिकिन्दर पासवान की पत्नी जैलस देवी, शिवचरण पासवान की पत्नी राधिका देवी व फेनहारा थानाक्षेत्र के रतनवा निवासी राम कुसुम साह के दस वर्षीय पुत्र मंजेश कुमार से मिलकर कुशल क्षेम पूछा और इन्हे ढाढस बंधाया. वही मंत्री श्री पासवान सदर अस्पताल की व्यवस्था देख अस्पताल प्रबंधक व सिविल सर्जन को धन्यवाद दिया. सदर अस्पताल के मुआयना के बाद मंत्री श्री पासवान रक्सौल के लिए रवाना हो गए जहां वे रक्सौल स्थित हजारी मल हाई स्कूल में चल रहे राहत शिविर का जायजा लेंगे. मौके पर अस्पताल कर्मी पार्टी के नेता कार्यकर्ता समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

छात्रों ने मारी बाजी

राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा 2015 में जीवन पब्लिक स्कूल मोतिहारी एवं लखौरा शाखा के छात्रों ने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय स्तर पर परचम लहराया है एवं अपने विद्यालय का नाम रौशन किया है. उक्त परीक्षा में चार छात्रों ने बाजी मारी है. स्थानीय जीवन पब्लिक स्कूल के सभागार में सम्मान समारोह आयोजित कर उक्त सभी विजेताओं को विद्यालय के निदेशक जीवन प्रकाश श्रीवास्तव एवं प्राचार्य मनोज रंजन ने संयुक्त रूप से मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया. उक्त परीक्षा में आठवीं कक्षा का छात्र कुमार अभिषेक जिसका 53 रैंक है. तीसरी कक्षा का छात्र आदर्श कुमार का प्रथम रैंक, साक्षी कुमारी को दूसरी रैंक एवं दूसरी कक्षा के छात्र पंकज कुमार भी दुसरा रैंक प्राप्त हुआ. छात्रों ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने अभिभावक एवं स्कूल प्रबंधन सहित शिक्षक को दिया है. इक्त विद्यालय के निदेशक जीवन प्रकाश श्रीवास्तव ने छात्रों को सम्मानित करते हुए कहा कि इस तरह की इपब्धियों के लिए छात्रों के साथ–साथ विद्यालय परिवार भी गौरवांवित हुआ है.■

– इन्तेजारूल हक

प्यार पाना आसान नहीं होता है

राधिका

इस बार हम लेकर आए हैं एक ऐसे जोड़े की कहानी जो एक–दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है. एक दूसरे की खुशियों से ज्यादा जरुरी इन दोनों के लिए कुछ नहीं हैं. इस बार की कहानी है डॉ अनिल सुलभ और उनकी पत्नी किरण झा की.

इनकी प्रेम कहानी ने भी काफी उतार चढ़ाव देखे. काफी दिक्कतों का सामना किया. इतना हीं नहीं दोनों ने अपने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी. अनिल इस बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरी किरण से पहली मुलाकात 1982 में हुई थी. उन्हें अपने भतीजे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाना था. इसी सिलसिले में पैरवी के लिए वो मुझसे मिलने आई थीं. उस समय मेरे चाचाजी बिहार सरकार में मंत्री थे. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. शायद इस काम की वजह से किस्मत इन दोनों को मिलवाना चाहती थी. इनकी पहली मुलाकात पहली और आखिरी नहीं हुई. मुलाकातें बढ़ती गईं.

अनिल आगे बताते हैं कि शुरुआत में तो हम दोनों काम के सिलसिले में मिलते थे, लेकिन इस दौराव शायद मैं कहीं न कहीं किरण को पसंद आ गया था. इतना ही नहीं, मेरे मन में भी उनके प्रति फीलिंग्स आ गईं थीं. हमारा रिश्ता करीब एक साल तक चला और फिर हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया. लेकिन इस राह पर चलना इतना आसान नहीं था. जो रास्ता इन दोनों ने चुना था, उस राह में बहुत सारी कठिनाईयां थीं. हर कदम पर कोई न कोई बड़ी चुनौती इन दोनों का इंतजार कर रही थी. लेकिन कहते हैं कि अगर प्यार आसानी से मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं होती. और वह प्यार ही क्या है जो आसानी से मिल जाए. शायद इसी कहावत को अपना हौसला बनाकर इन दोनों ने इस रास्ते पर चलने का फैसला किया और अंततः दोनों ने अपने परिवारों के खिलाफ जाकर मंदिर में शादी कर ली. दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन उसके बाद का समय इन दोनों के लिए बहुत ही दुख भरा था. करीब एक साल तक दोनों के घरवालों ने उन्हें नहीं अपनाया. लेकिन धीरे–धीरे सबकुछ सामान्य हो गया और दोनों परिवारों ने इन्हें और इन दोनों के रिश्ते को अपना लिया.

कुछ लोग संसार में अच्छा करने और अपना नाम समय के पन्नों पर दर्ज कराने आते हैं. अनिल सुलभ उनमें से एक हैं. गजलकार, समाजसेवी, कला और संस्कृति के संरक्षक, सहज–व्यक्तित्व के धनी अनिल सुलभ हर रचनात्मक कार्य के लिए सहजता से सुलभ रहते हैं. इनके व्यक्तित्व के कई आयाम हैं. आप इन्हें मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के लिए जानते होंगे, लेकिन हिन्दी साहित्य सम्मेलनों से लेकर अच्छे रचनाकारों को सुनने, सराहने और उन्हें अपने मंचों पर सम्मान देने मे भी इनका विशेष योगदान रहता है. समाज सेवा को वह अपना कर्तव्य समझते हैं. वह सजदे और धोखे का अंतर पहचानने वाली पारखी नज़र रखने वाले व्यक्ति हैं.

अनिल सुलभ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी आंखों में एक प्रकार की चमक, व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण और चीजों को परखने की अदभुत क्षमता है. ये सभी बातें ही उन्हें भीड़ से अलग बनाती हैं. उनका अपनापन और अपनेपन का एहसास ही लोगों को उनसे जोड़ने का काम करता है. वर्तमान प्रगतिवादी समाज में उन्होंने सफलता के जितने परचम लहराए हैं वे सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं. वह जिस तरह की सहजता, सहिष्णुता और सादगी के प्रतिरुप दिखते हैं, वह उसी तरह अंदर से भी इन गुणों से परिपूर्ण हैं. अनिल सुलभ का व्यक्तित्व अपराजित जनशक्तियों का समावेशित रुप है. जिनका विश्वास है कि मनुष्य के पास एक प्रबल इच्छा शक्ति है जिसके बल पर वह एक मजबूत और उन्नत समाज का निर्माण कर सकता है. उन्होंने पत्रिकाओं को अपने सहयोग के जरिये जीवित रखने का अनूठा काम किया है. राज्य के बुजुर्ग साहित्यकारों का आदर किया है. शायद खुद से ज्यादा तरजीह सामाजिक कार्यों को देते रहे इसीलिए आज की तीन पीढ़ियों के बीच वे समान रुप से अजीज हैं. ये सच है कि उन्होंने अपने दम पर उनकी चौखट पर आये किसी जरुरतमंद को निराश नहीं किया. साहित्य, संगीत और संस्कृति कर्म के अनन्य पोषक के रुप में डॉ. सुलभ की ख्याति चारों दिशाओं में फैली है. वे सारी ऐसी संस्थाएं, जिन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं हैं डॉ. सुलभ द्वारा संपोषित होती हैं.

अनिल किरण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किरण के अंदर किसी भी चीज के प्रति जो दृढ़ता है वह मुझे भा गई थी. वह जिस तरह से किसी भी चीज के लिए अपने आप को समर्पित कर देती हैं, यही उनकी खासियत है. और जिस तरह से उन्होंने मेरे लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था वह और कोई नहीं कर सकता है. और आज भी जब मैं उनको देखता हुं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हुं कि मुझे किरण जैसी पत्नी मिली है. इतना हीं नहीं किरण ने मुझे घर के सारे दारोमदार से मुक्त कर रखा है. वह मुझे घर के किसी भी काम की चिंता नहीं होने देती हैं. उन्होंने हर चीज को बखूबी संभाला है.■

feedback@chauthiduniya.com

सोशल मीडिया पर लड़कियां कितनी सुरक्षित?

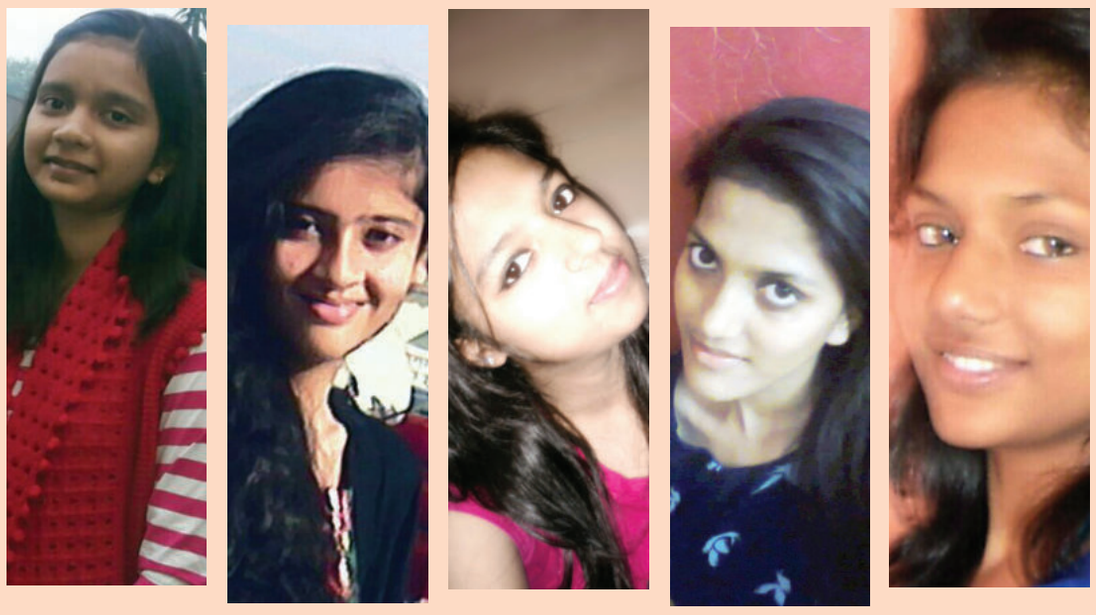

राधिका

सोशल नेटवर्किंग आजकल के लोगों की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है. लेकिन फेसबुक और और ट्विटर जैसी बेहद लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला आम–तौर पर लोग नहीं कर पाते हैं. भारत में इंटरनेट, खासकर सोशल मीडिया पर लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है. चाहे लड़का हो या लड़की, ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं. आज इंटरनेट के इस युग में लोग फेसबुक, ट्विटर या अन्य किसी सोशल नेटवर्किंग साईट्स का उपयोग करते हैं. सोशल मीडिया को यूज करना कोई बुरी चीज नहीं है लेकिन इसका गलत इस्तेमाल होने लगे तो यह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है. आपत्तिजनक तस्वीरें लगाने से लेकर अश्लील टिप्पणियां और वीडियो अपलोड करने जैसी कई चीजें होती हैं जिसका खामियाजा कई बार अन्य लोगों को भुगतना पड़ा है. और ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि इंटरनेट पर लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं?

जहां तक लड़कियों की बात है तो लड़कियां भी सोशल मीडिया पर काफी ऐक्टिव हो गई हैं. और हो भी क्यूं ना? ये उनका हक है. लेकिन कई बार इंटरनेट पर ऐसी घटनायें घट जाती है जो किसी भी लड़की के लिए परेशानी का सबब बन जाती है. जैसे साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, हैकिंग, फेक एकाउंट, आपत्तिजनक तस्वीरें, अश्लील टिप्पणियां, वीडियो अपलोड आदि. ये सारी चीजें साइबर क्राइम की दुनिया में सबसे ज्यादा होती हैं. जैसा कि आए–दिन देखा जाता है कि किसी लड़की की छेड़छाड़ की गई तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दी जाती हैं. जिससे उस लड़की को भारी परेशानियों और नुक़सान का सामना करना पड़ता है. किसी लड़की का फेक (नकली) एकाउंट बनाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है. या किसी लड़की का नकली ऑब्सीन वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है, जिस की वजह से उस लड़की को कई तरह की सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

मीनाक्षी रंजन, जो कि एक स्टूडेंट हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं इस बारे में उनका कहना है कि उन्हें भी सोशल मीडिया पर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. मीनाक्षी ने बताया कि उनके फेसबुक इनबॉक्स में कई दिनों से कुछ अनचाहे मेसेज आ रहे थे जिसमें लिखा होता था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं तुम्हारा इस जगह इंतजार करूंगा, तुम मुझसे मिलने आना. कुछ दिनों तक तो मीनाक्षी ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब यह सिलसिला नहीं थमा तो उन्हें मजबूरन, कुछ गलत होने के डर की वजह से अपना फेसबुक एकाउंट कुछ समय के लिए डी–एक्टिवेट(बंद) कर दिया था. इसी सिलसिले में अपराजिता शांडिल्या, जो कि एक स्टूडेंट है का कहना है कि उन्हें भी कई बार सोशल मीडिया पर मनचले लड़कों की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. और इस बात से वो इतनी आहत हुई कि, अब वो सोशल मीडिया पर दोबारा एकाउंट बनाना नहीं चाहती हैं. इसी क्रम में कई और लड़कियां– श्वेता, मन्स्विता झा और तनु से भी बातचीत के दौरान ये पता चला कि कभी ना कभी इन सब को साइबर क्राइम का शिकार होना पड़ा है.

साइबर क्राइम की शिकायत के लिए सरकार ने साइबर क्राइम सेल बनाए हैं, जहां इंटरनेट से जुड़े तमाम अपराधों से संबंधित शिकायतें दर्ज की जाती हैं. इस बारे में राजधानी पटना के साइबर क्राइम सेल के एडिशनल इंचार्ज एएसपी नीलेश कुमार का कहना है कि आए दिन ऐसे मामले दर्ज होते हैं जिसमें लड़कियों के एकाउंट, आपत्तिजनक तस्वीरें लगाने से लेकर अश्लील टिप्पणियां या वीडियो अपलोड होने की शिकायतें होती हैं. नीलेश ने बताया कि जब इस तरह के मामले हमारे पास आते हैं तो हम उन मामलों पर त्वरित कार्रवाई करते हैं, और ऐसी आपत्तिजनक चीजों को इंटरनेट से हटा देते हैं. लेकिन इसके साथ नीलेश कुमार का कहना है कि कम जानकारी होने की वजह लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं. बहुत सारे लोग फेसबुक पर अपनी तस्वीरे विजिबल टू ऑल कर देते हैं, जिससे कोई भी अनचाहा व्यक्ति उस तस्वीर को निकाल कर उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है. नीलेश आगे कहते हैं कि ऐसे केसेज से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सही जानकारी. इसके साथ ही सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है.

फेसबुक हो या ट्विटर, जीमेल हो या कोई और सोशल नेटवर्किंग साईट शायद कहीं भी लड़कियां पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं. कहीं ना कहीं हर लड़की के मन में यह डर हमेशा बना रहता है कि कहीं वो किसी साइबर क्राइम का शिकार ना हो जाये. ऐसे में एक अहम सवाल उठता है कि क्या यह सिलसिला कभी बंद होगा? क्या लड़कियों को हमेशा यूं ही डर–डर के रहना होगा? क्या ये परिस्थिती कभी बदलेंगी? इन सवालों पर सोचने की जरूरत है, इसके साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए और ठोस कदम उठाने की भी जरूरत है.■

feedback@chauthiduniya.com